अमेरिकी राजनीति

बाइडेन बनाम ट्रंप

अमेरिकी राजनीति व्हाइट हाउस की दौड़ में शामिल बाइडेन बनाम ट्रंप हो गई है। यह वर्ष अमेरिकी राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ महीने बाद होने वाले चुनाव में अमेरिकन मतदाताओं को वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा उनको चुनौती देने वाले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अभियान विज्ञापनों, रैलियों और बहसों का आनन्द उठाने का मौका मिलेगा। दोनों उम्मीदवार मतदाताओं के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। अमेरिकनों द्वारा लिए जाने वाले इस निर्णय का प्रभाव पूरी दुनिया के लिए दूरगामी महत्व वाला होगा। प्राइमरी लगभग समाप्त होने वाले हैं जिससे अमेरिका में राजनीतिक परिदृश्य साफ हो रहा है। बाइडेन ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवारी हासिल की है और ट्रंप स्पष्ट रूप से रिपब्लिकन पार्टी में सबसे आगे हैं। इस प्रकार नवंबर में होने वाले चुनाव का मंच सज गया है। डेमोक्रेटिक नामांकन तक बाइडेन की यात्रा दृढ़ता तथा उनके समर्थन में उभार का प्रतीक है। उम्मीदवारी के बारे में शुरुआती संदेहों के बावजूद उन्होंने देश भर के प्राइमरी चुनावों में विजय प्राप्त की और मतदाताओं में अपना व्यापक आकर्षण प्रस्तुत किया। उनकी सफलता के पीछे अनेक कारण हैं जिनमें प्रशासन में उनका अनुभव, एकता का संदेश तथा मतदाताओं से व्यक्तिगत स्तर पर संबंध बनाने की उनकी क्षमता शामिल है। प्राइमरी चुनावों के पूरे दौर में बाइडेन को विभिन्न उम्मीदवारों से कड़ा मुकाबला करना पड़ा जो ट्रंप को चुनौती देने का अवसर प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन प्राइमरी चुनाव आगे बढ़ने के साथ ही बाइडेन ने स्पष्ट बढ़त प्राप्त कर ली तथा डेमोक्रेटिक पार्टी के मध्यमार्गियों व प्रगतिशीलों का समर्थन प्राप्त किया।

कैलीफोर्निया, टेक्सास और फ्लोरिडा जैसे राज्यों में विजय से उनकी पार्टी उम्मीदवारी पक्की हुई।

दूसरी ओर रिपब्लिकन पक्ष में ट्रंप की उम्मीदवारी को ज्यादा मुकाबले का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि, कुछ कानूनी बाधायें थीं, पर अंततः वे उनसे पार पाने में सफल हुए तथा रिपब्लिकनों की स्पष्ट पसंद बन कर उभरे। ट्रंप को अपनी पार्टी के भीतर न्यूनतम विरोध का सामना करना पड़ा जिससे वे अपना जनाधार बढ़ाने पर ध्यान दे सके। आलोचनाओं के बावजूद पार्टी पर ट्रंप की पकड़ मजबूत बनी हुई है और उनकी 'अप्रूवल रेटिंग' काफी ऊंची बनी हुई है। उन्होंने अपने प्रति निष्ठा रखने वाले समर्थकों का मजबूत आधार तैयार किया है जो उनकी बेलाग शैली तथा लोकरंजक लफ्फाजी को पसंद करते हैं। हालांकि, कोविड-19 वैश्विक महामारी तथा अन्य समस्याओं से निपटने के उनके तरीके की आलोचना हुई थी, पर ट्रंप ने जिस मजबूती से उथलपुथल भरी राजनीति का मुकाबला किया उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय विमर्श में स्वास्थ्यरक्षा, आप्रवास और जलवायु परिवर्तन की प्रमुखता है। ऐसे में दोनों उम्मीदवारों से रिकार्ड संख्या में अपने समर्थकों को लामबंद करने की आशा है। बाइडेन के समक्ष गुटों में बंटी डेमोक्रेटिक पार्टी को एकजुट कर सभी विचारधारा वाले मतदाताओं को आकर्षित करना है। उनको परिपक्व राजनेता की तरह अपनी क्षमताओं का लाभ उठा कर भविष्य के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण रखना होगा। इस बीच ट्रंप अर्थव्यवस्था व राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपने रिकार्ड को सामने रख कर ट्रंप समर्थकों को ऊर्जान्वित करते हुए बाइडेन को वाम-चरमपंथियों का औजार बताएंगे। बाइडेन के प्रगतिशील व राजनीतिक रूप से सही होने के बावजूद ट्रंप की नेतृत्व शैली कंजरवेटिव सोच को आकर्षित करती है। दोनों उम्मीदवारों के बीच ऐतिहासिक मुकाबला सुनिश्चित है। अमेरिकी मतदाताओं को तय करना है कि अमेरिका दीवालें खड़ी करेगा या उनको तोड़ेगा।

पेटेंट पूलिंगः कल्याण व समृद्धि का मार्ग

साझा उद्देश्य से अपने पेटेंटों का साझा या पेटेंट पूलिंग कर विभिन्न पक्ष सहयोग व खोज को बढ़ावा दे कर आवश्यक खोजों तक पहुंच सुनिश्चित कर सकते हैं।

अमित सिंह
(लेखक, पेटेंट क्षेत्र से संबद्ध हैं)

पेटेंटों का साझा या 'पेटेंट पूलिंग' दो या उससे अधिक पेंटट धारकों के बीच एक समझौता है जिससे वे अपने एक या अधिक पेटेटों के बीच क्रास-लाइसेंसिग कर सकते हैं या तीसरे पक्षों को लाभ पहुंचा सकते हैं। साझा उद्देश्य से अपने पेटेंटों का साझा कर विभिन्न पक्ष सहयोग व खोज को बढ़ावा दे कर आवश्यक खोजों तक पहुंच सुनिश्चित कर सकते हैं। ऐतिहासिक रोडमैप से स्पष्ट है कि पेटेंट पूल उस समय सामने आते हैं जब तकनीक बहुआयामी और जटिल होती है तथा तकनीकी परिदृश्य के विभिन्न आयामों को एकसाथ लाकर बेहतर तकनीकी समाधान निकालना संभव होता है। आमतौर से ये पेटेंट पूल उस समय परिपक्व तकनीकों का साझा करते हैं जिनसे और विकास संभव होता है। तकनीकी आयामों के साथ दो प्रतियोगियों के बीच पेटेंट पूल बनाने की प्रेरणा पेटेंट प्राप्त तकनीक के हस्तांतरण के साथ ही अंततः नई खोजों या तकनीकी समाधानों को जन्म देती है। इससे आईपी-संबंधी कानूनी टकराव से भी बचा जा सकता है। पेटेंट पूल से लाइसेंस धारकों तथा लाइसेंस देने वालों का काम आसान हो जाता है। इससे लाइसेंस प्रक्रिया में लगने वाले समय तथा खर्च में नाटकीय रूप से कमी आती है। वे तकनीक को जल्दी, सक्षम रूप से व न्यायोचित ढंग से बाजार में लाने में सहायक उपकरण सिद्ध होते हैं जिनसे लाइसेंस धारकों को अपने निवेश का उचित लाभ मिलता है। कभी-कभी पूलों का आंतरिक कामकाज अपारदर्शी लग सकता है। लेकिन अक्सर एसईपी लाइसेंसों के मामले में अलग-अलग कंपनियों के टकरावों की तुलना में ये ज्यादा पारदर्शी व सक्षम सिद्ध होते हैं। इस संबंध में क्वालकाम और एपल के बीच चले टकराव पर गौर किया जा सकता है।

जहां तक खोज का सवाल है, पेटेंट पूल महत्वपूर्ण आर्थिक आयाम हैं। पेटेंटेड तकनीक का साझा कर कंपनियां अपना वह समय और पैसा बचा सकती हैं जो तकनीक तैयार करने में लगता। उल्लेखनीय है कि खोज के प्रयासों से परिणाम की गारंटी मिलना जरूरी नहीं है जिससे तकनीकी खाई बनी रहती है। पेटेंटों के मामले में मुकदमेबाजी के बजाय पेटेंट पूल बनाना हमेशा बेहतर कार्ययोजना होती है क्योंकि उद्योगों में अनेक पेटेंटधारक होते हैं और उनके क्षेत्र परस्पर आच्छादित करने वाले हो सकते हैं। वायरलेस व दूरसंचार उद्योग ऐसा ही एक तकनीकी क्षेत्र है जो बहुत प्रगतिशील व परिवर्तनशील है। इसके परिणामस्वरूप उचित परिणाम प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होने वाली तकनीकों का समर्थन करने वाली तकनीकों के अनेक पेटेंट सामने आते हैं।

दूसरे शब्दों में यह क्षेत्र अनेक सहायक पेटेंटों को जन्म देता है जिनका प्रयोग एक खास परिणाम प्राप्त करने के लिए होता है और वे एक दूसरे के पूरक नहीं होते हैं। ऐसे में लगता है कि इस तकनीकी क्षेत्र में पेटेंट पूलिंग की बहुत संभावनायें हैं। लेकिन दूसरी ओर स्वीडेन की 'सेंटर फार इंटेलक्चुअल प्रापर्टी' के उप निदेशक व उद्योग विशेषज्ञ ब्रोमैन हीडेन का मानना है कि दूरसंचार क्षेत्र में पूल अब तक विफल क्यों रहे हैं।

मानकीकरण व पेटेंट पूल क्षेत्र के प्रख्यात विशेषज्ञ हीडेन के अनुसार, 'वायरलेस क्षेत्र के बड़े लाइसेंसधारकों ने हमेशा मोबाइल टेलीकाम के क्षेत्र में अकेले चलना पसंद किया है। इस क्षेत्र मेंमानकों के क्रियान्वयन तथा संभावित लाइसेंसधारकों का घनत्व बहुत अधिक है। हैंडसेट बाजार में यदि आप एपल, सैमसंग और हुआवेई को लाइसेंस देते हैं तो कुल लाइसेंसिंग से प्राप्त आय का बड़ा हिस्सा इससे मिल जाता है।' ऐसे में इस क्षेत्र के बड़े लाइसेंसधारक, जैसे इरिक्सन, क्वालकाम और नोकिया स्वतंत्र रूप से काम करना चाहते हैं। लेकिन यह कहना उचित नहीं होगा कि दूरसंचार क्षेत्र में पेटेंट पूलिंग का प्रयोग नहीं होता है। हाल ही में आसुस व आईपी ब्रिज ने विया लाइसेंसिंग के माध्यम से 4जी मल्टी-जेनरेशनल पेटेंट पूल में हिस्सेदारी की है और अब ऐसे कुल लाइसेंसधारकों की संख्या बढ़ कर 25 हो गई है।

नई दवाओं तक पहुंचने का एक बेहतर रास्ता पेटेंट पूलिंग है। इससे तीसरे पक्षों को बौद्धिक संपदा के लिए 'नान-एक्सक्लूसिव लाइसेंस' प्राप्त करने का अवसर मिलता है जो नये उत्पाद विकसित करने के लिए जरूरी हो। जहां तकनीक के अन्य क्षेत्रों में पेटेंट पूलों का अस्तित्व दशकों से बना हुआ है, सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी उपस्थिति नई है। पेटेंट पूलों का प्रयोग गरीब व मध्य आय वर्ग वाले देशों में उभरती चुनौतियों का सामना करने में किया गया है। गरीब व मध्य आय वर्ग वाले देशों में एंटी-रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 'द युनाइटेड' ने पहले सार्वजनिक स्वास्थ्य पेटेंट पूल के रूप में 2010 में मेडिसिन्स पेटेंट पूल की स्थापना की थी। दवाओं तक पहुंच बेहतर करने में 'ह्यूमन इम्युनोडिफीसियेंसी वायरस'-एचआईवी संक्रमण की दवाओं तक पहुंच एक उदाहरण है। बाद में पेटेंट पूल का विस्तार ट्यूबरकुलोसिस तथा हेपेटाइटिस सी के इलाज का विस्तार करने में किया गया।

'द मेडिसिन्स पेटेंट पूल'-एमपीपी संयुक्त राष्ट्रसंघ समर्थित सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन है जो गरीब व मध्य आय वर्ग वाले देशों के लिए जीवनरक्षक दवाओं के विकास तथा उन तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। इससे बौद्धिक संपदा पूल प्रोत्साहित करने में सहायता मिलती है जो नये फार्मूलों के विकास तथा उनके जेनेरिक उत्पादन को बढ़ावा देता है। एचआईवी दवाओं तक पहुंच बढ़ाने में एमपीपी का अनुभव बताता है कि पेटेंट पूलिंग के माध्यम से कछ खोजों को आगे बढ़ाने तथा स्वास्थ्य तकनीकों के क्षेत्र में चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पेटेंट पूल एक प्रकार की खोजी साझेदारी सामने रखता है जिसका प्रयोग निजी आईपी घारकों के अधिकारों से सार्वजनिक हित आगे बढ़ाने में हो सकता है। मार्च, 2020 में एमपीपी ने अपना विस्तार कर उसमें ऐसी सभी स्वास्थ्य तकनीकों को शामिल कर लिया जो कोविड-19 के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया में योगदान कर सकती हों।

हालांकि, पेटेंट पूलों के सकारात्मक प्रभावों के बारे में आम सहमति है और यह भी स्वीकार किया गया है कि इस प्रभाव में काफी वृद्धि हो रही है, पर कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जहां पेटेंट पूलों से नियमों के उल्लंघन में संभावित प्रतियोगिता हो सकती है। इसका उदाहरण अमेरिका की दो कंपनियों के बीच पेटेंट पूल के मामले में विवाद है जिन्होंने लेज़र आई सर्जरी के बारे में तकनीकें विकसित की थीं। इस प्रकार की तकनीक बाजार में उपलब्ध नहीं थी। दोनों कंपनियों ने व्यक्तिगत पेटेंट संरक्षण की प्रार्थना की थी। इस पर फेडरल ट्रेड कमीशन-एफटीसी ने निर्णय दिया था कि पेटेंट पूल से प्रतियोगिता बाधित होती है जो पेंटेट पूल बनाने से पहले मौजूद थी। कुल मिला कर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो पेटेंट पूलिंग उस समय से तकनीकों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण समाधान के रूप में देखी जा रही है जब 1856 में सिलाई मशीनों के मामले में इसका प्रयोग किया गया था। लेकिन निकट अतीत में पेटेंट पूलिंग की स्वीकार्यता इसलिए बढ़ी है कि इसे गरीब और मध्य आय वर्ग वाले देशों को सस्ती व सक्षम दवाओं तथा चिकित्सा तकनीकों तक पहुंच के रूप में देखा जा रहा है। एचआईवी, हेपेटाइटिस सी व अन्य बीमारियों की दवायें तलाश करने में इसका प्रयोग किया गया है।

पेटेंट पूलिंग से नई तकनीकों की खोज में लगने वाला समय और पैसा बच सकता है, इससे अलग-अलग पेटेंट धारकों के बीच कानूनी टकराव से भी मुक्ति मिलती है तथा गरीब व मध्य आय वर्ग वाले देशों की जनता को अनेक क्षेत्रों में लाभान्वित किया जा सकता है। हालांकि, पेटेंट पूलिंग से प्रतियोगिता कानूनों का संभावित उल्लंघन हो सकता है, पर इसके सकारात्मक परिणाम कुछ संभावित नकारात्मक परिणामों की तुलना में बहुत अधिक हैं। भविष्य में समय और लागत प्रभावी होने के कारण पेटेंट पूलिंग के मामलों में तेजी से बढ़ोत्तरी हो सकती है। इससे संसाधन प्रबंधन करने तथा आईपी विवादों से बचने में भी सहायता मिलती है।

सेमीकंडक्टर उद्योग पर भारत का ज़ोर

> सेमीकंडक्टर विनिर्माण को सुरक्षित करने की दौड़ वास्तव में भू-राजनीति की वर्तमान स्थिति है जैसा कि एक छोटी सी चिप के माध्यम से देखा जाता है।

कुमारदीप बनर्जी
(लेखक, नीति विश्लेषक हैं)

विदेश मंत्री ने दक्षिण कोरिया और जापान का दौरा किया विदेश मंत्री एस जयशंकर इस सप्ताह दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे पर थे। भारत के एशियाई पड़ोस में ये दोनों देश, इसके कुछ निकटतम सहयोगी भी हैं और आंतरिक निवेश का एक प्रमुख स्रोत भी हैं। विदेश मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि कोरियाई यात्रा में भारत-कोरिया गणराज्य की विशेष रणनीतिक साझेदारी का विस्तार सहयोग के विविध क्षेत्रों तक किया जाएगा, जिसमें व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और संस्कृति शामिल हैं। उम्मीद है कि जेसीएम द्विपक्षीय सहयोग के संपूर्ण आयाम की व्यापक समीक्षा करेगा और इसे और मजबूत करने के रास्ते तलाशेगा। यह दोनों पक्षों को आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर भी प्रदान करेगा।

यात्रा के जापानी चरण में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर प्रकाश डाला गया, और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी, शांतिपूर्ण और समृद्ध भारत-प्रशांत के लिए सहयोग पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया। यह भी कोई संयोग नहीं है कि भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा समर्थित एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय कूटनीति मंच, रायसीना डायलॉग का एक विशेष गोलमेज सम्मेलन भी विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान टोक्यो में हुआ था।

इससे पहले टोक्यो में रायसीना गोलमेज सम्मेलन के आयोजन को उचित ठहराते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा था, रायसीना आज एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच बन गया है। हमारे पास अभी रायसीना डायलॉग था, जहां दुनिया भर से लोग, नेता, राजनीतिक नेता, थिंक टैंक और रणनीतिक विचारक

सभी दिल्ली आए थे। हमारे ग्रीस के प्रधान मंत्री मुख्य अतिथि थे। इसलिए, आज इस मंच की वैश्विक गूंज है। बेशक, जापान हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदार है और यह विशेष जुड़ाव हमारी बातचीत में मदद करेगा, जापान के साथ हमारे जुड़ाव में भी उतनी ही मदद करेगा।

दक्षिण कोरिया और जापान में बैठकों के वास्तविक नतीजे आने वाले कुछ महीनों में सामने आएंगे, जहां भारत ने अर्धचालक आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा करने का दावा किया है। हाल ही में भारतीय कैबिनेट ने लाखों करोड़ रुपये के सेमीकंडक्टर प्रस्तावों की एक पूरी श्रृंखला को मंजूरी दी। वर्तमान वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षमता पर ताइवान, दक्षिण कोरिया और चीन का अनुपातहीन कब्ज़ा है, जबकि अमेरिका और जान की हिस्सेदारी अल्पमत है। कोविड महामारी और उसके बाद चीन की कार्रवाइयों, जिसमें सेमीकंडक्टर (टोस्टर से लेकर हाई-एंड स्पेस रॉकेट तक सभी मशीनों का एक महत्वपूर्ण घटक) का हथियारीकरण शामिल है, ने लगभग हर देश को अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने और विविधता लाने के लिए मजबूर किया है। भारत के चीन के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं और आने वाले वर्षों में स्थिति में सुधार होने की संभावना नहीं है, जिससे भारत को अपने पुराने सहयोगियों जापान और अमेरिका और यूरोपीय संघ के उचित समर्थन के साथ दक्षिण कोरिया पर निर्भर रहना पड़ेगा। सेमीकंडक्टर निर्माण केक का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करने में।

जनवरी 2024 में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में, राज्य के मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि कई दक्षिण कोरियाई और जापानी सेमीकंडक्टर कंपनियां सक्रिय रूप से निवेश के लिए गुजरात पर विचार कर रही हैं। सेमीकंडक्टर विनिर्माण को सुरक्षित करने की दौड़ वास्तव में भू-राजनीति की वर्तमान स्थिति है जैसा कि एक छोटी सी चिप के माध्यम से देखा जाता है।

अमेरिका और चीन अधिक तकनीकी कौशल की दौड़ में एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बिल्डिंग ब्लॉक चिप्स (सूक्ष्म एकीकृत सर्किट बोर्ड, जटिल बहुस्तरीय, कई चरणों वाले डिजाइन और विनिर्माण की आवश्यकता होती है) हैं, जो आज की दुनिया की लगभग हर मशीन को शक्ति प्रदान करते हैं। अमेरिका ने पहले ही चीन को उच्च तकनीक वाले चिप्स के निर्यात को रोक दिया है, जो अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी के लिए अपना रास्ता खोज सकते हैं, जिससे इसकी कुल प्रौद्योगिकी प्रभुत्व महत्वाकांक्षाएं रुक गईं।

भारतीय प्रधानमंत्री और वर्तमान सरकार, इस वर्ष के मध्य में सत्ता में लौटने को लेकर आश्वस्त हैं और कल के लिए बड़े रोजगार पैदा करने वाले प्रौद्योगिकी कारखाने स्थापित करने में कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। विदेश मंत्री के दक्षिण कोरिया और जापान, अगले दशक के लिए भारत की महत्वाकांक्षी यात्रा की आवश्यकता को उचित ठहराते हैं।

आप की बात

लड़कियों को प्रोत्साहन

सेना ने लड़कियों के बीच खेल के प्रति रुचि जगाने के लिए दो आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट कंपनियों-एजीएससी के गठन का एलान किया है। खास सुविधाओं से लैस ये कंपनियां महू में भारतीय सेना लड़कों के लिए पहले से ही इस तरह की कपंनी चलाती है अब लड़कियों के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। सेना का यह प्रयास सराहनीय और स्वागत योग्य है। क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों के लिए समुचित संसाधनों की कमी है। खिलाड़ियों को यदि पर्याप्त सुविधा व संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं, उन्हें पौष्टिक भोजन व नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाए तो हमारा 140 करोड़ की आबादी वाला देश पदक तालिका में अग्रणी स्थान बना सकता है। भारतीय लड़कियों व किशोरियों ने देश-विदेश के अनेक खेलों में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की है। लड़कियों को खासकर प्राथमिक कक्षाओं से ही खेलों में भाग लेने के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे लड़कियां, पुलिस, अर्धसैनिक बलों व सेना के साथ अन्य क्षेत्रों में जाने के लिए ज्यादा सक्षम बनेंगी। लड़कियों में खेलों से शारीरिक शक्ति के साथ मानसिक दृढ़ता भी विकसित होगी जिससे वे समाज में महिला-विरोधी तत्वों से मुकाबला करने में सक्षम बनेंगी। इस दृष्टिकोण से भी सेना के इस विशेष प्रयास की प्रशंसा की जानी चाहिए।

– **विभूति बुपक्या,** खाचरोद

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव

अमेरिका में नवंबर में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से लगभग तय हो गया है कि मुकाबला इस बार भी राष्ट्रपति जो बाइडन और पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के बीच ही होगा। अमेरिका के चुनाव परिणाम पर पूरे विश्व की नज़रें टिकी हुई है और इस चुनाव के परिणाम पूरे विश्व की दूरगामी नीतियां का निर्धारित करेंगे। दोनों प्रत्याशी उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं। जो वाइडेन तो कई बार कार्यक्रमों के दौरान गिर भी पड़े हैं। ऐसे बुजुर्गों के कंधे पर न सिर्फ अमेरिका वरन समूचे विश्व के हितों का बोझ लादना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। चिकित्सा वैज्ञानिक कहते हैं कि इस उम्र में व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक क्षमताएं कम हो जाती हैं। ऐसे में नाभिकीय आयुधों से संपन्न दुनिया की सबसे बड़ी सेना का संचालन करना उचित नहीं कहा जा सकता है। हालांकि, सर्वेक्षण में आधे लोगों ने इतने वयोवृद्ध प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर नाराजगी जताई है, मगर वह कुछ नहीं कर सकते। वैसे अमेरिका का सैनिक रूप से मुकाबला करने वाले व्लादीमिर पुतिन और शी जिनपिंग भी काफी वृद्ध हैं। देखना होगा कि वृद्ध नेताओं के नेतृत्व वाली सरकारें भविष्य में अपने देश और दुनिया को क्या दिशा देंगी।

– **सुभाष बुड़ावन वाला,** रतलाम

सुरक्षित भारतीय

भारत सरकार का कहना है कि यदि हमारे देश का कोई नागरिक विदेश में किसी मुसीबत में फंस जाए तो सरकार उसे बचा कर सुरक्षित भारत ले आएगी। मोदी सरकार देश के हर नागरिक को विदेश से सुरक्षित भारत वापसी के लिए तत्पर रही है। कोरोना काल में भारतीयों की वापसी के साथ ही युद्धरत यूक्रेन से भी संकट में फंसे भारतीयों को सुरक्षित देश लाया गया। इसके अलावा सूडान, चीन, ईरान, इटली, जापान आदि से भी भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। वंदे भारत मिशन, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देव शक्ति, ऑपरेशन कावेरी, आदि मिशनों से भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। कतर में फंसे आठ भारतीय नौसैनिकों को सुरक्षित लाया गया। भारत सरकार रूस में फंसे 20 भारतीय नागरिकों की वापसी का प्रयास कर रही है जिनको फर्जी एजेंटों ने रूस-यूक्रेन युद्ध में झोंक दिया था। इस प्रकार भारत सरकार हमेशा देवदूत बनाकर विदेशों में संकट में फंसे भारतीय नागरिकों की सहायता करती है। सरकार की यह नीति हर भारतीय के लिए मोदी की गारंटी की तरह पक्की है। यह मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार के दुनिया में बढ़े कद, सैनिक क्षमता तथा अपनी जनता के प्रति प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण भी है।

– **मनमोहन राजावत,** शाजापुर

दलित-विरोधी सोच

दिल्ली में पिछले 10 साल से आम पार्टी-आप की सरकार है जिसके आदर्श के रूप में डॉ अंबेडकर को स्थान दिया गया है। लेकिन आप सरकार ने दिल्ली के 30 लाख अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया। दिल्ली राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन तक नहीं किया गया है जबकि यह मुद्दा एक विधायक द्वारा सदन में उठाया भी जा चुका है। दिल्ली राज्य अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण बोर्ड का गठन केवल 2 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। 10 साल से डॉ अंबेडकर राज्य पुरस्कार पर भी सरकार काम नहीं कर पाई। दिल्ली सरकार द्वारा 92 से अधिक तीर्थ यात्रा ट्रेन भेजी जा चुकी है लेकिन बोधगया व सारनाथ यात्रा का इंतजार है। आरोप है कि अनुसूचित जाति वर्ग के कंपोनेंट प्लान का पैसा दूसरे मदों में खर्च किया जा रहा है। आप सरकार ने राज्यसभा में 10 सांसद भेजे हैं इनमें एक भी अनुसूचित जाति का नहीं है। 2015-16 में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सरकार का बजट 397 करोड़ था जो अब घट कर 225 करोड रह गया है। इस प्रकार आप पार्टी की दलित-विरोधी सोच प्रकट होती है।

– **वीरेंद्र कुमार जाटव,** दिल्ली

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

समानता व बंधुत्व आवश्यक

भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाइ चंद्रचूड़ ने आह्वान किया है कि हमें संविधान की भावना के अनुरूप एक-दूसरे के प्रति सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए. उन्होंने रेखांकित किया है कि हमारे संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में मानव सम्मान सर्वोच्च महत्व का विषय था. हमारा संविधान न्याय, स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों के साथ-साथ बंधुत्व की भावना एवं व्यक्ति के सम्मान को भी प्रतिष्ठित करता है. यदि हम आपस में परस्पर सम्मान का आचरण नहीं करेंगे और हमारे व्यवहार में बंधुत्व नहीं होगा, तो स्वाभाविक रूप से समाज में तनाव एवं संघर्ष का वातावरण बनेगा. ऐसा वातावरण विकास, व्यवस्था एवं समृद्धि के प्रयासों के लिए बड़ा अवरोध होगा. यह अक्सर देखा जाता है कि विभिन्न श्रेणियों में बंटे हमारे समाज में लोग अपने पेशेवर या व्यक्तिगत जीवन में कनिष्ठों, सहायकों और कमजोरों के साथ उचित व्यवहार नहीं करते हैं. प्रधान न्यायाधीश ने वाहन चालकों, सफाई कर्मियों और चपरासियों के साथ होने वाले व्यवहार का उदाहरण भी दिया. आये दिन हम खबरों में देखते हैं कि आलीशान अपार्टमेंटों में रहने वाले लोग सोसाइटी के सुरक्षाकर्मियों या ठेले पर सामान बेचने वालों के साथ मारपीट या गाली-गलौज करते हैं. कार्यस्थल हो, आवास हो या बाजार, पीड़ित आम तौर पर इस तरह के अपमानजनक बर्ताव को बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे कथित रूप से 'बड़े लोगों' का मुकाबला नहीं कर पायेंगे. यह सभी को पता है कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर समाज और देश की उन्नति में योगदान देता है तथा वह योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है. जाति, लिंग, कार्य, क्षेत्र, धर्म या धन के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव असंवैधानिक तो है ही, ऐसा करना अमानवीय भी है. हम भारत के लोग तभी आगे बढ़ सकते हैं, जब हम एक-दूसरे का हाथ थामे चलेंगे. प्रधान न्यायाधीश ने उचित ही कहा है कि हमें अपने संवैधानिक अधिकारों का अहसास भी होना चाहिए तथा हमें अपने कर्तव्यों को भी समुचित ढंग से निभाना चाहिए. संविधान और उसके मूल्यों के बारे में व्यापक जागरूकता के प्रसार में शासन की भूमिका महत्वपूर्ण है. साथ ही, सरकार, प्रशासन और अदालतों को भी आम लोगों के अधिकारों के प्रति अधिक संवेदनशील होना चाहिए. कई बार तो उच्च शिक्षित और पेशेवर तौर पर सफल लोग अमानवीय और अन्यायपूर्ण बर्ताव करते देखे जाते हैं, जिनमें नेता, अफसर और जज भी शामिल हैं. ऐसे लोगों को अच्छा आचरण कर अपने पेशे और समाज में आदर्श बनना चाहिए. इसी प्रकार, घर-परिवार में बच्चे अपने माता-पिता और बड़ों के आचार-व्यवहार से सीखते हैं. प्रगति के लिए हमें प्रगतिशील मूल्यों को अपने आचरण का हिस्सा बनाना चाहिए.

किसी भी प्रकार का भेदभाव असंवैधानिक तो है ही, ऐसा करना अमानवीय भी है.

नदियों के कायाकल्प का संकल्प

डॉ विनोद तारे
प्राध्यापक, आइआइटी कानपुर
vinod@iitk.ac.in

(गंगा नदी की स्वच्छता के लिए 1985 में प्रारंभ किये गये गंगा एक्शन प्लान के आरंभिक दौर से लेकर नमामि गंगे मिशन में सक्रिय रूप से जुड़े हैं.)

गंगा नदी के संरक्षण और नदी के जैव-परितंत्र के पुर्नस्थापन के लिए किये गये प्रयासों की सफलता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा भारत सरकार के नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अग्रणी कार्यक्रम नमामि गंगे को प्राकृतिक जैव-परितंत्र की पुर्नबहाली के लिए संचालित दुनिया के दस सर्वश्रेष्ठ अभियानों की सूची में शामिल किया गया है. इस अभियान की सफलता को देखते हुए हाल ही में भारत सरकार के जलशक्ति मंत्रालय के अंतर्गत एनआरसीडी (नेशनल रिवर कन्जर्वेशन डायरेक्टोरेट) और 12 तकनीकी शिक्षण संस्थाओं (आइआइटी, एनआइटी और नीरी) के बीच छह नदियों (नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी और पेरियार) के बेसिन प्रबंधन की योजनाएं तैयार करने के लिए अनुबंध हुआ है. एक समय था, जब भारत की जीवनरेखा गंगा नदी को विश्व की पांचवी सर्वाधिक प्रदूषित नदी घोषित कर दिया गया था. नदी का जैव-परितंत्र गंभीर खतरे में था. करीब चार दशक की लंबी यात्रा में समन्वित प्रयासों की सतत श्रृंखला के परिणामस्वरूप गंगा नदी को नयी प्राण ऊर्जा मिली. इस संदर्भ में गंगा की यात्रा पर एक नजर डालना प्रासंगिक होगा.

वर्ष 1985 में केंद्र सरकार द्वारा गंगा एक्शन प्लान की घोषणा की गयी थी. इस योजना का प्रथम चरण 1986 से 2000 तक चला तथा 2001 से इसके दूसरे चरण का प्रारंभ हुआ. इन दोनों चरणों के पूर्ण होने पर गंगा की सफाई और बेहतरी को लेकर अपेक्षा के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं हो सके. वर्ष 2014 में कार्यभार संभालने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी के संरक्षण को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया तथा इस काम को मिशन के रूप में अंजाम देने की घोषणा की. नमामि गंगे मिशन की तीन विशेषताएं हैं. इन विशेषताओं के कारण यह मिशन कई चुनौतियों के बावजूद अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर चलते रहने का संकल्प ले चुका है. ऐसा इसलिए कि किसी भी मिशन को सफल बनाने के लिए जो मूलभूत तत्व आवश्यक होते हैं, वे सब इस मिशन के लिए उपलब्ध कराये गये हैं. दूसरी विशेषता है मिशन के उद्देश्य की स्पष्टता और इसका संयुक्त राष्ट्र विकास लक्ष्य के साम्य. तीसरी विशेषता है प्रशासनिक और अकादमिक संस्थाओं का परस्पर सामंजस्य.

वर्ष 2015 में सात भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थानों (आइआइटी) के संघ ने सरकार को गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लान का त्रिस्तरीय प्रारूप सौंपा था. इस प्लान को देखने के बाद यह निर्धारित किया गया कि आइआइटी संघ का दायित्व महज योजना बनाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इस योजना के सतत क्रियान्वयन और आकलन के लिए भी उसके सहयोग की आवश्यकता होगी. मिशन के अकादमिक विंग को सशक्त बनाने के लिए आइआइटी कानपुर के नेतृत्व में सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज (सी-गंगा) का गठन किया गया. सी-गंगा ने नदियों के मानचित्र बनाने जैसे भौगोलिक कार्य से लेकर अंतिम संस्कार की विधि में परिवर्तन जैसे भावनात्मक विषयों पर भी काम किया है. नमामि गंगे मिशन के पांच मुख्य आधार हैं- राजनीतिक इच्छाशक्ति, सार्वजनिक व्यय, सहभागिता, हिस्सेदारी, भागीदारी और समझाना-बुझाना. राजनीतिक इच्छाशक्ति के बगैर किसी व्यापक मिशन पर काम करना और आवश्यक संसाधनों को जुटाना संभव नहीं है. प्रधानमंत्री मोदी ने इस मिशन में व्यक्तिगत स्तर पर रुचि ली और वे मिशन की प्रगति के बारे में निरंतर जानकारी लेते रहे. इससे मिशन को आगे बढ़ाने में प्रेरणा और सहयोग प्राप्त हुआ. इतने बड़े मिशन पर काम करने के लिए बड़े बजट की आवश्यकता थी, जो समय-समय पर सरकार ने आवंटित किया, जिसके कारण मिशन का कार्य कभी बाधित नहीं हुआ. न केवल नमामि गंगे मिशन, बल्कि समांतर रूप से चल रहे जल संबंधी कार्यक्रमों, जैसे जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, अमृत आदि, के सुचारू संचालन के लिए भी पर्याप्त बजट आवंटित किया गया, जिसका समग्र प्रभाव गंगा बेसिन और अंततः गंगा नदी पर नजर आया.

नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ साझेदारियां हुईं और तकनीकी आदान-प्रदान हुआ. मिशन के विशेषज्ञों की टीम ने ऑस्ट्रेलिया की मरे-डॉर्लिंग, इंग्लैंड की टेम्स और यूरोप की राईन नदी के बेसिन प्रबंधन के बारे में जाना-समझा, लेकिन उसे हू-ब-हू अपनाने के बजाय भारत के स्थानीय परिवेश के अनुसार उचित विधियों का इस्तेमाल किया गया. इस योजना में जन-भागीदारी को बढ़ाने के लिए गंगा उत्सव, गंगा टास्क फोर्स, गंगा प्रहरी और गंगा मित्र जैसे अभियान भी संचालित किये गये. इस अभियान में नदी के जल की गुणवत्ता के रासायनिक मानदंडों, जैसे बीओडी, सीओडी, कॉलिफॉर्म आदि को सिर्फ बीमारी के लक्षण के रूप में देखा गया, परंतु लक्ष्य नदी के जैव-पारिस्थितिक तंत्र की पुर्नबहाली को रखा गया. वर्ष 2019 में राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने अर्थ गंगा की संकल्पना प्रस्तुत की. परियोजना का सिद्धांत व्यवहार में साकार होता तब नजर आया, जब प्रयागराज में आयोजित अर्धकुंभ मेले में अपेक्षित पर्यटक संख्या से तीन गुना अधिक पर्यटक पहुंचे. कुंभ की महत्ता को स्वयं प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत प्रयासों से विदेशों तक पहुंचाया और कई विदेशी हस्तियों को इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित किया. कई शहरों में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, रिवर-पीपल कनेक्ट जैसी गतिविधियों से पर्यटन की संभावनाएं बढ़ीं.

नदी एक तंत्र हैं, जिसके आधार पर नदी अपनी प्राकृतिक प्रक्रियाओं पूर्ण करते हुए सतत अपनी अमूल्य सेवाएं (इकोलॉजिकल सर्विसेज) प्रदान करती रहती है. अब मिशन नदियों को उनका खोया हुआ सामर्थ्य दोबारा लौटाने की दिशा में कार्यरत है. समर्थ गंगा अभियान के पांच स्तंभ हैं- निर्मल गंगा, अविरल गंगा, अर्थ गंगा, ज्ञान गंगा और जन गंगा. छह विशाल नदियों के बेसिन प्रबंधन के लिए 12 तकनीकी संस्थाओं को अनुबंध पत्र सौंपने के समारोह में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस काम को उपनिषद के सूत्र 'एकोहम बहुस्याम' (एक से अनेक की ओर) से संदर्भित किया. उन्होंने कहा कि नये केंद्रों की स्थापना स्वागतयोग्य हैं और उम्मीद जतायी कि ऐसे प्रयास देश को जलसमृद्ध बनायेंगे. देश में संचालित नदी पुनर्जीवन अभियान में प्रशासनिक और अकादमिक सामंजस्य के चलते नदी विज्ञान रूपी ज्ञान की नयी शाखा उभर रही है. यह कहना निराधार नहीं होगा कि नदी विज्ञान और प्रबंधन के क्षेत्र में भविष्य में भारत विश्व को नेतृत्व देने में अपना दायित्व निभायेगा.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

राजनीतिक इच्छाशक्ति के बगैर किसी व्यापक मिशन पर काम करना और आवश्यक संसाधनों को जुटाना संभव नहीं है. प्रधानमंत्री मोदी ने इस मिशन में व्यक्तिगत स्तर पर रुचि ली और वे मिशन की प्रगति के बारे में निरंतर जानकारी लेते रहे. इससे मिशन को आगे बढ़ाने में प्रेरणा और सहयोग प्राप्त हुआ.

साहित्य संवर्द्धन में साहित्य अकादमी का महत्वपूर्ण योगदान

गोविंद मिश्र
प्रख्यात साहित्यकार एवं सदस्य
कार्यकारिणी मंडल, साहित्य अकादेमी
govindmishra1939@gmail.com

साहित्य अकादमी के 70 वर्ष

साहित्य अकादमी नयी पीढ़ी के रचनाकारों को स्थान देने के लिए प्रयासरत है. उदाहरण के लिए, अकादमी में हिंदी भाषा का संयोजक होने के नाते मैंने यह तय किया है कि जहां भी कार्यक्रम हों, उनमें युवा पीढ़ी के साहित्यकारों को रचना पाठ या वक्तव्य के लिए आमंत्रित किया जाए.

भारत सरकार ने स्वायत्त साहित्यिक संथा के रूप में साहित्य अकादमी (नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स) की स्थापना का आधिकारिक निर्णय दिसंबर 1952 में लिया था और 12 मार्च, 1954 को इसका उद्घाटन तत्कालीन उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था. इस वर्ष हम इस महत्वपूर्ण संस्था की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं. साहित्य अकादमी को आधिकारिक रूप से इस प्रकार परिभाषित किया गया है- 'भारतीय साहित्य के सक्रिय विकास के लिए कार्य करनेवाली एक राष्ट्रीय संस्था, जिसका उद्देश्य उच्च साहित्यिक मानदंड स्थापित करना, भारतीय भाषाओं में साहित्यिक गतिविधियों को समन्वित करना एवं उनका पोषण करना तथा उनके माध्यम से देश की सांस्कृतिक एकता का उन्नयन करना होगा.' इस संस्थान की प्रमुख विशिष्टता यह है कि इसका प्रबंधन और संचालन लोकतांत्रिक ढंग से साहित्यकारों द्वारा किया जाता है. भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में जितनी भाषाएं शामिल हैं, उनसे संबंधित रचनाओं का पाठ होता है, सेमिनार होते हैं तथा पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है. बिना किसी भेदभाव के सभी भाषाओं के लिए पुरस्कार दिये जाते हैं. अगर हिंदी के लिए पुरस्कार की राशि एक लाख रुपये है, तो कोंकणी के लिए भी इतनी ही राशि दी जाती है.

साहित्य अकादमी में कई श्रेणियां हैं, जिनमें लेखकों को शामिल किया जाता है. सामान्य परिषद सबसे शक्तिशाली इकाई है, जिसमें लगभग सौ सदस्य होते हैं. ये सदस्य सभी प्रांतों से आते हैं. राज्य सरकारें तीन नाम भेजती हैं, जिनमें से एक को पिछली सामान्य परिषद द्वारा अगले पांच वर्षों के लिए चुना जाता है. इसके अलावा विश्वविद्यालयों, भाषाओं की सेवी संस्थाओं, प्रकाशकों, केंद्र सरकार और विभिन्न अकादमियों आदि के प्रतिनिधि भी सामान्य परिषद में होते हैं. साथ ही, एक प्रतिष्ठित साहित्यकार को भी चुना जाता है. सामान्य परिषद से ही कार्यकारी मंडल को बनाया जाता है. यह मंडल मुख्य रूप से संस्थान को संचालित करता है. पुरस्कारों की विभिन्न श्रेणियां हैं. प्रतिष्ठित साहित्यकारों को सीनियर फेलोशिप दी जाती है. ऐसे साहित्यकार समय-समय संस्थान को सलाह देते हैं. इस प्रकार बिना किसी नौकरशाही के साहित्यकार ही भारतीय साहित्य के संवर्द्धन का कार्य करते हैं. कोई भी स्वायत्त संस्था हो, चाहे निर्वाचन आयोग हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, कार्यपालिका यानी शासन द्वारा उसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास हमेशा होता है. उन्हें लगता है कि पैसा सरकार का लग रहा है, तो निर्णय भी उन्हीं को करना चाहिए. साहित्य अकादमी संसद द्वारा पारित अपने संविधान से मार्गदर्शन लेती है. विभिन्न पद चुनाव द्वारा निर्धारित होते हैं. ऐसे में हस्तक्षेप की कोशिशें अभी तक काफी हद तक कामयाब नहीं हो पायी हैं. मेरे कहने का आशय यह नहीं है कि पूरी स्वायत्तता रहती है, पर बहुत स्वतंत्रता से काम होता है. दखल यह होता है कि संस्कृति मंत्रालय के बहाने सरकार कभी कभी कुछ काम सौंप देती है, जो अकादमी कर देती है.

साहित्य अकादमी नयी पीढ़ी के रचनाकारों को स्थान देने के लिए प्रयासरत है. उदाहरण के लिए, अकादमी में हिंदी भाषा का संयोजक होने के नाते मैंने यह तय किया है कि जहां भी कार्यक्रम हों, उनमें युवा पीढ़ी के साहित्यकारों को रचना पाठ या वक्तव्य के लिए आमंत्रित किया जाए. अभी इंदौर में उपन्यासों पर कार्यक्रम होना है, जिसमें सेमिनार के साथ-साथ रचना पाठ भी होगा. अकादमी की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली में जो एक सप्ताह का साहित्योत्सव आयोजित किया जा रहा है, उसमें भी युवा पीढ़ी की साहित्यकार अच्छी संख्या में भाग ले रहे हैं. यह अकाद.मी की नीति का हिस्सा है कि जिन रचनाकारों को पहले नहीं बुलाया जा सका है, उन्हें आमंत्रित किया जाए. इस आयोजन में हर भाषा में रचना पाठ के कार्यक्रम हैं. प्रादेशिक भाषाओं को समझने में श्रोताओं की परेशानी को देखते हुए यह भी छूट दी गयी है कि उन भाषाओं के रचनाकार अपनी रचना का कुछ हिस्सा मूल भाषा में सुना दें और फिर उनका अनुवाद हिंदी या अंग्रेजी में प्रस्तुत कर दिया जाए. अकादमी युवा साहित्यकारों को पुरस्कृत भी करती है. बाल साहित्य के लिए भी पुरस्कार हैं.

यदि साहित्य में नयी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी और प्रतिभाशाली रचनाकारों को प्रोत्साहित नहीं किया जायेगा, तो भारतीय साहित्य के लिए यह बहुत दुखद होगा. उनके आगे आने के लिए समुचित वातावरण और अवसर मिले, यह अकादेमी का प्रयास रहता है. इस बात को लेखक ही समझ सकते हैं, न कि राजनेता या ब्यूरोक्रेसी, कि किन रचनाकारों में प्रतिभा है, सृजन क्षमता है और किनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है. साहित्यकारों में अपने बाद की पीढ़ी के लिए एक स्वाभाविक स्नेह भी होता है, जिसकी वजह से वे संपर्क में रहते हैं. मेरी आयु 84 वर्ष की है, पर मैं पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले नये लेखकों और लेखिकाओं की रचनाओं से परिचित हूं. मेरी कोशिश होती है कि उनमें से अच्छा रचने वालों को अकादेमी की ओर से अवसर मिले. अकादमी ने सात दशकों की अपनी यात्रा में भारतीय भाषाओं के साहित्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है और आशा है कि यह प्रयास दीर्घकाल तक चलता रहेगा.

(बातचीत पर आधारित)

देश दुनिया

जापान को ब्रिटेन से बाल संरक्षण सीखने की जरूरत

ब्रिटेन में जब भी किसी बाल संरक्षण कानून या प्रणाली पर बहस होती है, तो कोई न कोई मामला अवश्य ही संदर्भ के लिए उठाया जाता है. वर्ष 1973 में, अपनी चाची द्वारा पाली जा रही एक सात वर्षीय लड़की की तब मृत्यु हो गयी जब वह अपनी जननी मां के साथ रहने के लिए वापस लौटी. उसे खाना देने से इनकार कर दिया गया और उसके सौतेले पिता ने उसे तब तक पीटा जब तक उसकी हड्डियां टूट नहीं गयीं. उसे जो भयानक दुर्व्यवहार सहना पड़ा उसने समाज को झकझोर कर रख दिया. ब्रिटिश सरकार ने एक जांच समिति की स्थापना की. समिति ने रिपोर्ट में खुलासा किया कि लड़की की अपनी चाची के साथ रहने की इच्छा को अनसुना कर दिया गया था और संबंधित एजेंसियों के बीच जो संचार हो रहा था, वह अपर्याप्त था. इस त्रासदी ने बाल संरक्षण नीतियों को फिर से बनाने के लिए प्रेरित किया ताकि बच्चों की इच्छाओं को प्राथमिकता देना सुनिश्चित किया जा सके. ब्रिटेन में बच्चों के विरुद्ध भयानक यौन शोषण और अन्य अपराधों के मामले सामने आने के बाद अक्सर नीतियों की समीक्षा की जाती है. वर्ष 2002 में, पास में रहने वाले एक स्कूल केयरटेकर ने दो 10 वर्षीय लड़कियों की हत्या कर दी थी. इससे एक आपराधिक पृष्ठभूमि जांच प्रणाली का निर्माण हुआ- जो वर्तमान की डिस्क्लोजर एंड बैरिंग सर्विस (डीबीएस) का अगुआ है. जापान में डीबीएस का अपना संस्करण स्थापित करने के लिए अध्ययन चल रहा है, यह स्कूलों और अन्य संगठनों के कर्मचारियों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच करने की आवश्यकता के लिए एक प्रणाली होगी. जापानी संविधान किसी को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देता है, परंतु यौन शिकारियों को बच्चों से दूर रखने के लिए भी एक प्रणाली की आवश्यकता है. यहां हमें ब्रिटेन से सीखने की जरूरत है.

The Asahi Shimbun
Asia & Japan Watch

बोधि वृक्ष

संतुष्टि-प्रसन्नता-प्रशंसा

संतुष्टि मानव जीवन का श्रृंगार है, इसीलिए कहते हैं कि जो चेहरे से चमके वह संतुष्टि है. संतुष्टि तीन प्रकार की होती है. एक, ईश्वर से संतुष्ट अर्थात जो, जितना, जैसा और जब भी ईश्वर ने दिया, उसमें संतुष्ट रहना. दूसरा, अपने आप से संतुष्ट अर्थात अपने आपको अपने गुण-अवगुणों के साथ स्वीकार करना और तीसरा, सर्व संबंध और संपर्क से संतुष्ट अर्थात हर आत्मा को उनके गुण-अवगुणों के साथ स्वीकार करते हुए हर एक के अंदर कोई न कोई सकारात्मकता खोजना. संतुष्टि की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी और इसी प्रसन्नता के आधार पर प्रत्यक्ष फल यह होगा कि ऐसी आत्मा की सदा स्वतः ही सर्व द्वारा प्रशंसा होगी. जन्म से लेकर मृत्यु तक की इस महायात्रा में हम सभी के समक्ष छोटी-बड़ी अनेक समस्याएं आती हैं, इसलिए हमें इस बात को अच्छी तरह याद रख लेना चाहिए की जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आवाहन करना. जब यात्रा पर चलना ही है, तो रास्ते में नजारे न हो क्या यह संभव है? फिर नजारों को देखते हुए आगे बढ़ते चलो, रुक नहीं जाओ. रुक जाते हैं इसलिए लक्ष्य दूर अनुभव होता है. अक्सर हम सभी नजारों को देखकर यह क्यों, यह क्या, यह ऐसे नहीं, वैसे नहीं जैसे बेकार मुद्दों को लेकर रुक जाते हैं और हर नजारे को सुधारने लगते हैं. परिणामस्वरूप, सर्व शक्तिमान ईश्वर के साथ हम अपना संपर्क तोड़ देते हैं और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हैं. परमात्मा को दोष देना शुरू कर देते हैं कि मेरे जीवन में ही क्यों इतनी सब समस्याएं आपने भेज दी? इन शिकायतों को करने में हम भूल जाते हैं कि 'सहन करना ही आगे बढ़ना है.' वास्तव में देखा जाए, तो सहन तो कुछ करना ही नहीं होता है, परंतु हमारी अपनी ही कमजोरियों के कारण हमें सहन करने की अनुभूति होती है. ठीक इसी प्रकार, हम सब अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का कारण न जानने की वजह से आगे बढ़ने के सुख के अनुभव के बजाय सहन करने का दुख अनुभव करते हैं.

-ब्रह्माकुमार निकुंज जी

कुछ अलग

इंस्टाग्राम के बेरोजगार

आलोक पुराणिक
व्यंग्यकार
puranika@gmail.com

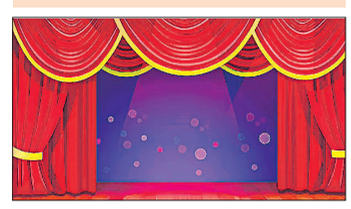

इंस्टाग्राम कुछ घंटों के लिए डाउन हुआ, तबाही जैसा नजारा हो लिया. पार्क में रील बना रहे बच्चों में बेचैनी छा गयी, रसोई में डांस कर रहीं आंटी इस ख्याल से बेहोश हो गयीं कि अब ये रील लोड कहां करूंगी. जुकरबर्ग अनंत अंबानी के विवाह पूर्व उत्सव में थोड़ा मौज-मस्ती करने क्या चले गये, दुनियाभर के इंस्टा वाले बेरोजगार परेशान हो लिये. दुनिया में दो तरह के बंदे हैं. एक जो नोट छापते हैं और बड़े लोगों की शादी अटेंड करते हैं. ऐसे लोग इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह के मालिक होते हैं. दूसरे वे बंदे हैं, जो अपने पराठों की फोटो छापते हैं और इंस्टाग्राम पर लोड करते हैं. बेरोजगार, जाहिर है, दूसरे वाले ही बंदे होते हैं. जामनगर में इतने उद्योगपति और अमीर लोग इकट्ठे हुए कि मानो वर्ल्ड बैंक या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक हो रही है. इतना भौकाल रहा गुजरात का कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी वापस लौटीं, तो पापा से कहा- आयेगा तो मोदी ही. पापा ट्रंप बोले- चुनाव यहां ट्रंप और बाइडेन के बीच में है, मोदी कैसे आ सकते हैं? इवांका ने कहा- मोदी है तो मुमकिन है.

संयोग जाने कैसे कैसे हो जाते हैं. भुलभुलैया-थ्री फिल्म की शूटिंग शुरु हुई, इस पर ट्विटर पर ट्रेंड चलने लगा. लोकसभा चुनाव के ठीक पहले भुलभुलैया थ्री शुरू, यह संयोग है या प्रयोग है या दुर्योग है? यह सवाल अपनी जगह बना हुआ है. चुनाव की तैयारी चल निकली है. टेंट वाले, माइक वाले, मिठाई वाले, कैटरिंग वाले, कार वाले, बेकार वाले, स्कूटर वाले, मैडम वाले, सर वाले, हर हाल में धंधा तलाशें ऐसे अवसर वाले, सब बिजी हो लिये हैं. खाली सिर्फ पब्लिक है, जो एक साथ क्रिकेट, भुलभुलैया और लोकसभा की तैयारियां देख रही है. इनमें से सबसे बड़ा तमाशा कौन सा है, यह कुछ महीने बाद पता लगेगा.

उद्धव ठाकरे ने कहा है कि भाजपा से गडकरी हमारी पार्टी में आ जायें. दरअसल उद्धव ठाकरे की पार्टी में उनकी विरोधी पार्टी भाजपा से बहुत पहले ही लोग आ चुके हैं, बस ठाकरे को पता ना चला है. संजय राउत लगातार उद्धव ठाकरे के जिस तरीके से डुबोते जा रहे हैं, उससे साफ होता है कि उद्धव की पार्टी ठीक वैसे ही चौपट हो रही है, जैसे उनकी विरोधी पार्टी भाजपा चाह सकती थी. बात में पता लग सकता है कि संजय राउत तो भाजपा के आदमी थे. समझ नहीं आता है वैसे आजकल कि कौन किसका आदमी है. इधर से निकल कर जाता है, बंदा उधर का निकल जाता है. पूरा का पूरा टोला इधर से उधर निकल रहा है. खैर, उम्मीद की जानी चाहिए कि इंस्टाग्राम के रीलबाजों को कुछ रोजगार मिल जायेगा, तीन तीन बड़े तमाशे सामने हैं.

आपके पत्र

इसरो प्रमुख सोमनाथ से लें प्रेरणा

देश-दुनिया लफ्फाजी से नहीं चलती है. इसके लिए कर्तव्यपरायण व जीवट व्यक्ति की जरूरत होती है. ऐसे ही व्यक्ति हैं वैज्ञानिक एस सोमनाथ. सोमनाथ को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हुई है, वे लंबी छुट्टी पर जा सकते थे. लेकिन, उन्होंने ऐसा नहीं किया. वे तीन दिनों के बाद ही अपने काम में लग गये. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के प्रमुख एस सोमनाथ को कैंसर का पता उस दिन चला, जिस दिन भारत का आदित्य-एल व मिशन अंतरिक्ष में लॉन्च हुआ था. इनसे सीख लेने की आवश्यकता है.

प्रसिद्ध यादव, बाबूचक (पटना)

ग्रीनफील्ड से होगा गांवों का विकास

बिहार सरकार को ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट पर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए. वे भू-भाग जो मुख्य मार्ग से दूर तथा तरक्की के दौर में भी पीछे छूटे हुए हैं. उन जगहों पर विकास की गति धीमी तथा जमीन के दाम बेहद कम होते हैं. इस प्रकार की जमीन को थोड़ी-सी अधिक कीमत देकर सरकार बड़ी आसानी से हासिल कर सकती है. इन जमीनों का उपयोग विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, विभिन्न प्रकार के कार्यालयों, खेल मैदान आदि बनाने में किया जा सकता है. ऐसा कर गांवों में विकास की गति को तेज किया जा सकता है.

सचिन झा, अगरौल (समस्तीपुर)

पोस्ट करें : प्रभात खबर, प्लॉट संख्या डी-9-10, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया, पटना (बिहार) - 800013, ■ **मेल करें :** patna @prabhatkhabar .in पर ■ ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है.

https://t.me/AllNewsPaperPaid

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । मुंबई । सोमवार, 11 मार्च 2024

सहयोगियों की तलाश

आंध्र प्रदेश में BJP, तेलुगू देशम पार्टी (TDP) और जनसेना पार्टी (JSP) का साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला अहम है। लोकसभा चुनावों में अपने लिए 370 और NDA के लिए 400 सीटों का जो लक्ष्य BJP ने घोषित कर रखा है, उसके मद्देनजर नए सहयोगियों का जुड़ाव तो महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी शर्तें भी कम मायने नहीं रखतीं।

बदल चुका है समीकरण | BJP की TDP पुरानी सहयोगी रही है। 1996 से लेकर 2018 तक यह NDA का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। अब छह साल बाद जब वह वापस लौटी है, तो यह देखना अहम है कि NDA के अंदर का शक्ति समीकरण पूरी तरह बदल चुका है।

AI Image

इस बार का NDA पहले से अलग

कोई हिचक नहीं | वाजपेयी और आडवाणी की अगुआई में जब NDA बना था, तब TDP जैसे सहयोगी दलों के बगैर BJP सरकार नहीं बना सकती थी। यही वजह थी कि इन दलों के दबाव में उसे अपने तीन मूल मुद्दों – राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और कॉमन सिविल कोड – को अस्थायी तौर पर छोड़ने की घोषणा करनी पड़ी थी। आज की स्थिति यह है कि तीन में से दो मांगें पूरी हो चुकी हैं और उत्तराखंड से कॉमन सिविल कोड को लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जाहिर है, अपने मूल सिद्धांतों पर किसी भी तरह का संकोच दिखाने की BJP को न तो कोई जरूरत है और न उसकी ऐसी कोई मंशा।

अपने दम पर बहुमत | 2014 में अपने दम पर बहुमत हासिल करने के बाद BJP की NDA के सहयोगी दलों पर निर्भरता नहीं रह गई। जाहिर है सहयोगी दलों को लेकर उसके रुख में भी बुनियादी बदलाव आया। यह खास तौर पर महाराष्ट्र और बिहार में दिखा, जहां वह अलायंस में 'छोटे भाई' से 'बड़े भाई' की भूमिका में आ गई। लिहाजा शिवसेना और JDU दोनों के नेतृत्व ने NDA से बाहर की राह पकड़ ली। अकाली दल जैसे अन्य सहयोगी दल भी उससे अलग हो गए।

फिर से विस्तार | बदले माहौल में यह प्रक्रिया एक बार फिर रिवर्स मोड लेती नजर आ रही है। न सिर्फ बिहार में JDU फिर से NDA का हिस्सा बन चुका है और आंध्र प्रदेश में TDP से गठबंधन हो गया है बल्कि ओडिशा में BJD के साथ भी बातचीत चल रही है। जाहिर है, BJP नेतृत्व एक बार फिर सहयोगी दलों की संख्या बढ़ाना जरूरी मान रहा है।

टारगेट से उपजा दबाव | टारगेट हासिल करना है तो BJP को उत्तर के राज्यों में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखते हुए दक्षिण के राज्यों में सांसदों की संख्या बढ़ानी होगी। ऐसे में सहयोगी दलों को साथ लाने की जरूरत है तो यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर पार्टी खुद लड़े। आखिर 370 सीटों तक पहुंचने के लिए उसे 67 सीटें और जीतनी होंगी। जाहिर है, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए BJP को इस विरोधाभास से भी पार पाना होगा।

चक्र-व्यू

कागा उड़ भागा

राहुल पाण्डेय

होली को अभी पखवाड़ा भर है, मगर अवध में अभी से फगुआ बरस रहा है। सुल्तानपुर से लेकर महोबा तक ढोल, नगाड़े और मंजीरा लेकर फाग टोली गांव-गांव जुटने लगी है। उधर शाम हुई, इधर गांव के मंदिर वाले चबूतरे पर नगाड़े को आग दिखनी शुरू। कहीं मंदिर ना हुआ तो किसी शहराती बाबू साहब का दालान हुआ, जहां जाजिम बिछाकर टोली व्यवस्था बैठाने में जुटी है। इधर नगाड़ा गर्म हुआ, उधर फगुआ बेशर्म हुआ। क्या सास क्या ससुर, क्या ननद क्या ननदोई, क्या दोस्त और क्या दुश्मन, और क्या देवी-देवता, फगुआ के रंग से कोई बच नहीं सकता। महोबे के मोहनिया गांव में कल फाग रंग घोलते-घोलते राम रतन मौर्या ने हांक लगाई, *'सरजू मैया के तीरा, अवध मा होरी खेलैं रघुबीरा। केकरे हाथै कनक पिचकारी, केकरे हाथै अबीरा।'* यह जोगीरा सीरीज का फाग है, जिसमें छंद पूरा होने के बाद टोली जोर से *'जोगीरा सा-रा-रा-रा'* बोलती है।

फगुआ में वास्तविक रंग कम और शाब्दिक रंग ज्यादा चलते हैं। यहां तक कि होली के दिन मेरे गांव में बाबू काली सहाय के यहां जो सबसे बड़ी मंडली जुटती थी, उसमें भी रंग के नाम पर तिलक से ज्यादा कुछ नहीं होता था। आमतौर पर रोली वाले लाल पर टिका रहने वाला तिलक फगुआ टोली में आकर नीला, पीला, हरा या गुलाबी हो जाता है। ऐसे ही एक और फाग याद आ रहा है जो कभी काली सहाय के दालान में गाया जाता था, *'सवरिया से कागा उड़ भागा मोरा सइयां अभागा न जागा।'* यहां सइयां की जगह फगुआ टोली हर उस शख्स का नाम लेती है, जिससे कुछ नेग मिलने की उम्मीद है। देखने वाली बात है कि इस एक लाइन में भी कितने ढेर सारे रंग हैं। बसवरिया यानी बांस की झाड़, जिसमें गाढ़े हरे से लेकर धानी और पीला तक मौजूद है। कागा, यानी कौव्वा, यानी काला रंग। सइयां के रंग कितने हैं, यह सजनी से पूछा जाना चाहिए और नींद का रंग वो बताएंगे, जो करवट बदलते हुए उसके इंतजार में रातें काली करते हैं।

कहते हैं कि होली मन का मैल धोने का भी त्योहार है। फगुआ में मन का मैल ठीक वैसे ही रगड़-रगड़कर धोया जाता है, जैसे होली के बाद हम चेहरे पर लगा हरा रंग धोते हैं। फगुआ टोली गाती है, *'धरे मोहन रूप जनाना, चलैं बेचैं चुरिया शहर बरसाना।'* इससे पहले कि बरसाना पर नगाड़े की फाइनल थाप लगे, श्रोताओं में से ही कोई उठकर इससे मिलती-जुलती नई लाइन में हर उस शख्स का नाम पिरोकर हांक लगाता है, जिसके लिए उसके मन में तनिक भी मैल जमा होता है। यह संकेत है कि हमने अपने मन का मैल धुल दिया है, अब आपकी बारी है। अब जिसका नाम पिरोया गया है, वह भी गाकर जवाब देता है। दोनों के मन धुल चुके हैं। दोनों पर फाग रंग चढ़ चुका है। दोनों मिलकर गाते हैं, *'होरी के हुड़दंग मा भइया करौ ना केहू झगरा, चहंटा (कीचड़) लैइके भउजी दौड़ीं, भूल गवा सब रगरा। जोगीरा सा-रा-रा-रा।'*

एकदा

सांकृत्यायन पर हमला

1942 में जेल से छूटने के बाद राहुल सांकृत्यायन हुंकार के संपादक बने। हुंकार उस समय की साप्ताहिक पत्रिका थी जो पटना से निकलती थी। यह पत्रिका किसानों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाती थी। जमींदार किसानों का शोषण करते थे। जमींदारों को रजवाड़ों और रजवाड़ों को अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त था। ये जमींदार उन किसानों को जमीन से बेदखल करते थे जो मालगुजारी नहीं भर पाते थे। इसी बेदखली को रोकने के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार में किसान सभा का गठन किया था। किसान सभा और

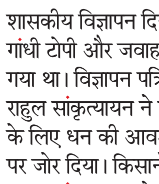

हुंकार दोनों किसानों को जमींदारों के चंगुल से छुड़ाने के लिए कार्य कर रही थी। जेल जाने से पहले राहुल सांकृत्यायन किसान सभा में सक्रिय थे और छूटने के बाद पत्रिका के माध्यम से उसी प्रयोजन की सिद्धि में लग गए। उनके इस प्रयास से जमींदारों, रजवाड़ों और अंग्रेजों को खतरा नजर आने लगा। पत्रिका को कमजोर करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने उसे शासकीय विज्ञापन दिया। इस विज्ञापन का शीर्षक था 'गुंडों से लड़िए'। इसमें गांधी टोपी और जवाहर बंडी पहने एक व्यक्ति को आग लगाते हुए दिखाया गया था। विज्ञापन पत्रिका के उद्देश्यों के अनुकूल नहीं था। इसलिए संपादक राहुल सांकृत्यायन ने उसे छापने से इनकार कर दिया। लेकिन पत्रिका चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी। इसलिए सहजानंद ने विज्ञापन को छापने पर जोर दिया। किसानों की दुर्दशा के लिए अंग्रेजों को जिम्मेदार मानने वाले राहुल सांकृत्यायन ने सहजानंद सरस्वती से विवाद किए बगैर संपादक पद से त्यागपत्र दे दिया और सीधे किसानों के आंदोलन में सक्रिय हो गए। जमींदारों और रजवाड़ों के गुंडे बदला लेने की फिराक में थे। अवसर पाकर एक दिन उन लोगों ने राहुल सांकृत्यायन पर उस समय हमला किया जब वह खेत में गन्ना काट रहे थे। वह संयोग से बच गए। लेकिन तमाम खतरों के बावजूद सच सामने लाने का अपना अभियान बंद नहीं किया।

संकलन : हरिप्रसाद राय

रिपब्लिकन प्रत्याशी अमेरिका की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा

ट्रंप के आने की तैयारी कर ले भारत

स्वामीनाथन एस अंकलेसरिया अय्यर

अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव आठ महीने दूर हैं। 6 राज्य ऐसे हैं, जहां डॉनल्ड ट्रंप और जो बाइडन, दोनों के लिए बराबर समर्थन मौजूद है। ऐसे राज्यों को स्विंग स्टेट कहते हैं। जनमत सर्वेक्षणों के अनुसार, इन 6 में से 5 में ट्रंप आगे हैं और यही स्टेट चुनाव परिणाम का फैसला करेंगे। लेकिन अब जनमत सर्वेक्षण विश्वास के लायक नहीं रहे। पिछले हफ्ते 15 राज्यों में Super Tuesday primaries में ट्रंप ने निकी हेली को हरा दिया। हालांकि सर्वे में जो अंतर बताया गया था, उसके मुकाबले बहुत कम अंतर से। 2016 में ऐसे ही सर्वेक्षणों में हिलेरी क्लिंटन की आसान जीत की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन ट्रंप जीत गए।

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव

- नौकरशाही में अपने लोग चाहते हैं ट्रंप
- फिर चुनाव जीते तो बदल देंगे नीतियां
- WTO नियमों में बंधे नहीं रहना चाहते

ट्रंप का बदला | बहरहाल, भारत को ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए तैयार रहना चाहिए। उनके आसपास की ताकतवर मंडली ने अमेरिकी नेतृत्व में पूरी विश्व व्यवस्था को बदलने के लिए विस्तृत खाका पहले ही तैयार कर लिया है। भारत को इसी के अनुसार चाल बदलनी होगी। ट्रंप की टीम का लक्ष्य है अधिकांश प्रशासनिक अफसरों को बर्खास्त करना और उनकी जगह अपने लोगों को बैठाना। इसका मकसद सिर्फ एक स्वतंत्र सिविल सर्विस को कुचलना ही नहीं, बल्कि उन लोगों पर मुकदमा भी चलाना है, जिन्होंने ट्रंप के लिए पहले कार्यकाल में बाधाएं खड़ी की थीं।

शक्ति बढ़ाने पर जोर | नए लोग ट्रंप के प्रति वफादार होंगे, न कि संविधान के प्रति। उनका लक्ष्य है अमेरिकी व्यवस्था के चेक एंड बैलेंस को खत्म करना, जिसने ट्रंप के पहले कार्यकाल में आमूल-चूल परिवर्तन को इतना मुश्किल बना दिया था। ट्रंप का लक्ष्य है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति में भारी विस्तार करना। अगर अदालतें उनका समर्थन करती हैं, तो राष्ट्रपति अमेरिकी संसद, राज्य सरकारों, रेगुलेटरी एजेंसीज और न्यायपालिका के दायरे से बाहर निकल जाएंगे।

नियम बदले जाएंगे | सभी रेगुलेटरी एजेंसीज में ट्रंप के बैठाए लोग होंगे। वे ट्रेड से लेकर इमिग्रेशन और पर्यावरण से लेकर औद्योगिक नीति तक, हर चीज पर नियम बदल देंगे। इससे नया जटिल कानून गैर-जरूरी हो जाएगा क्योंकि नियमों को बाहरी मंजूरी के बिना आंतरिक रूप से बदला जा सकेगा।

नई व्यापार नीति | वैश्विक स्तर पर ट्रंप उन बहुपक्षीय नियमों को खारिज करते हैं, जो पूरी दुनिया पर लागू हो रहे। उनका मानना है कि इन नियमों के चलते अन्य देशों को अमेरिकी खर्च पर समृद्ध होने का मौका मिला है। वह विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन करते हुए सभी वस्तुओं पर 10 प्रतिशत और चीन की वस्तुओं पर 60 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाने की बात कह चुके हैं।

WTO से परेशानी | अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने रिक्त पदों पर जजों की नियुक्ति को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। इस तरह से WTO appellate authority पंगु बन गई। वह WTO या अन्य किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था के नियमों में बंधे नहीं रहना चाहते। उनका लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश सौदे करना है, जहां अमेरिका दूसरों पर अधिक रियायतों के लिए धौंस जमा सके सके।

अमेरिका फर्स्ट | उनकी नीति 'अमेरिका फर्स्ट' है। उन्हें वैश्विक नियमों पर आधारित 20वीं सदी के वैश्वीकरण से कोई मतलब नहीं है, जिसने दुनिया को समृद्ध बनाने में मदद की। ट्रंप सोचते हैं कि वैश्वीकरण अमेरिका की तुलना में दूसरों के लिए बेहतर था।

NATO पर सवाल | इसका विदेश नीति पर बहुत असर पड़ता है। ट्रंप नैटो छोड़ सकते हैं। वह नैटो में तभी बने रहेंगे, जब यूरोप के सहयोगी अपने रक्षा योगदान में भारी इजाफा करें या फिर सुरक्षा देने के लिए अमेरिका को भुगतान करें। ट्रंप को डील करना पसंद है। कुछ एनालिस्ट यूक्रेन के मसले पर ट्रंप के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पूतिन के साथ समझौता करने पर विचार कर रहे हैं। कुछ लोग ताइवान को लेकर चीन के साथ समझौते का सुझाव दे रहे हैं।

अपनी रक्षा खुद करिए | इस तरह के कदम अमेरिकी विदेश नीति पर 20वीं सदी की आम सहमति को खत्म कर देंगे। जापान और कोरिया के साथ अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था को ट्रंप यह कहते हुए छोड़ सकते हैं कि अपनी रक्षा खुद कीजिए। वह शायद चीन को रोकने के लिए इस बात में सहज होंगे कि जापान और कोरिया परमाणु ताकत हासिल कर लें।

भारत के लिए अर्थ | भारत के लिए इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो हमें ट्रेड वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। ट्रंप के 10 फीसदी टैरिफ से भारत प्रभावित होगा। साथ ही, उसे अमेरिकी लॉबी द्वारा मांगे गए अतिरिक्त टैरिफ के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत हाल ही में कई आयातों पर टैरिफ लगाकर आत्मनिर्भर रास्ते पर चला गया है। ट्रंप का 'अमेरिका फर्स्ट' भी आत्मनिर्भरता की ही मुहिम है।

कृषि उपज को लेकर दबाव | ट्रंप इस बात पर जोर देंगे कि फल, मेवे और सोयाबीन समेत अन्य अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत के बाजार में आसानी से पहुंचें। ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका ने स्टील और एल्युमीनियम पर टैरिफ लगाया, तो भारत ने अमेरिकी वस्तुओं पर कुछ टैरिफ लगाकर जवाबी कार्रवाई की। कई विवाद WTO में गए और बाद में आपसी सहमति से सुलझाए गए। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में व्यापार की यह लड़ाई और बड़ी होगी। वीजा पर पंगा । ट्रंप इमिग्रेशन का विरोध करते हैं, चाहें वैध हो या अवैध। वह चाहते हैं कि सभी IT काम अमेरिका में हों। अमेरिका में काम करने वाले भारतीयों के लिए वह H1B वीजा का विरोध करते हैं। इससे भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर प्रगति में अड़चन आएगी।

Quad पर संशय | ट्रंप विदेश में सैन्य अभियानों का विरोध करते हैं। तो क्या वह Quad को छोड़ देंगे या कमजोर कर देंगे? वह चीन के घोर विरोधी हैं और भारत के साथ खड़े होने का यह एक बड़ा कारण है। वह खुशी-खुशी भारत को अत्याधुनिक हथियार बेचेंगे। अमेरिका ने भारत के रूस से S-400 मिसाइल खरीदने का विरोध किया था। लेकिन, अब इस तरह की डील पर ट्रंप की ओर से प्रतिक्रिया नहीं आएगी। ट्रंप अस्थिर हैं। वह आर्थिक वैश्वीकरण और वैश्विक सुरक्षा पर 20वीं सदी की आम सहमति को छोड़ना चाहते हैं।

AI Image

एक बात याद रखिए! भूल जाना कोई गलती नहीं

याददाश्त से कितनी शिकायत रहती है हमें। कि, दिमाग ठीक से कुछ सहेज कर नहीं रख पाता। कि, चीजें भूल जाती हैं, चेहरे भूल जाते हैं, नाम याद नहीं रहते। और कि, अब तो बातें भी जेहन से छूटने लगी हैं, पता नहीं क्या कहा था पिछली बार! याददाश्त पर इतना जोर रहता है हमारा कि सोचते हैं हर वह चीज दिमाग में छप जाए, जो सामने से होकर गुजरी है। लेकिन, दिमाग क्या कोई मेमरी कार्ड है और क्या भूलना इतना ही बुरा है?

कहा जाता है कि वक्त हर जख्म भर देता है। वक्त को यह ताकत इसलिए हासिल है, क्योंकि वह यादों पर धूल डालने में माहिर है। जब एक खास याद का धुंधला जाना बुरा नहीं, तो किसी आम याद का दिमाग से उतर जाना बुरा कैसे? अब बताइए कि अगर दिमाग पिछली गलतियों से सबक लेकर गलती करना भूल जाए तो क्या बुरा है? अगर वह भूल जाए बुरे लोगों को, बुरी यादों को, सिर पर चढ़ चुके सफलता के नशे को और नाकाम इश्क को, तो इसमें भी क्या बुराई? पुराना भूले बिना कोई भी नई शुरुआत नहीं हो सकती। बीते समय की बातें कई बार बेड़ियां बन जाती हैं पैरों की। कुछ लोग भी बेड़ियों की तरह ही होते हैं। उनकी याद जब भी आती है, तो केवल बुरी याद के रूप में। ऐसी सारी मेमरी अगर इरेज हो जाए तो बेहतर ही है।

भूलना इस मामले में भी नेमत है कि भूलकर ही किसी को माफ किया जा सकता है। क्षमा एक वरदान है, जिसे देना हर किसी के बस की बात नहीं। किसी को दी हुई एक माफी आपमें इतना संतोष भर सकती है, जितनी हजार लोगों को दी गई सजा भी नहीं। भूलना मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो सकता है। कुछ स्टडी का कहना है कि निगेटिव मेमरी को भूलने से अवसाद में कमी आ सकती है, बेवजह की चिंता नहीं रहती और मूड अच्छा बन सकता है। साथ ही, नई चीजें सीख सकते हैं, खुद को नए

AI Image

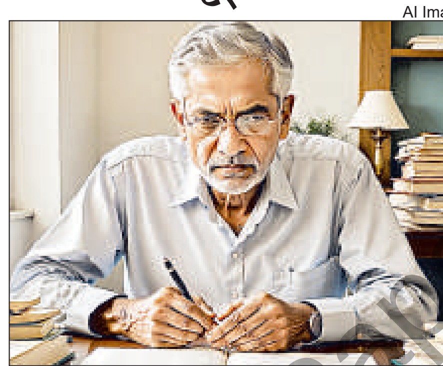

जीवन आनंद

सिरे से तैयार कर सकते हैं।

भूलना एक आदत है, जो सभी में होती है। बस कहीं कम, कहीं ज्यादा। लेकिन, जिन आदतों को बिना सुनवाई के गलत मान लिया गया, उनमें यह भी है। और उस पर भी जुल्म यह कि इसे जोड़ दिया गया उम्र से। लेकिन, उम्र को मात देते किसी वकील की दलीलें, किसी अभिनेता का अभिनय, किसी क्रिकेटर का शॉट उदाहरण हैं इस बात का कि उम्र कानून नहीं भुलाती, न एक्टिंग और न बैट पकड़ना। कोई लेखक लिखना नहीं भूलता। किसानों को अपने खेत हमेशा याद रहते हैं और कारीगरों को अपना हुनर। बल्कि उम्र के साथ इनकी चमक और बढ़ती ही जाती है। हां, ये लोग दूसरी तमाम चीजें भूल सकते हैं। और यह भी हो सकता है कि वे चीजें फिर किसी समय याद भी आ जाएं। दरअसल, भूलने और याद करने का यह खेल धूप-छांव जैसा है। इसका आना-जाना लगा रहता है। दिक्कत यह है कि हम भूलने और विस्मृत करने को एक ही मान लेते हैं। भूले हुए कि वापसी हो सकती है, लेकिन जो स्मृतियों से खो जाए, उसकी वापसी बहुत मुश्किल है।

लेखक चरन रंगनाथ की किताब 'वाय वी रिमेंबर' बताती है कि जिस भूलने को हम अपने दिमाग की कमी मानते हैं, वह असल में फीचर है इसका। इंसानी दिमाग हर चीज को याद करने के लिए नहीं बना। उसकी अपनी प्राथमिकताएं हैं, जिसके आधार पर वह तय करता है कि क्या भूले और क्या याद रखे। यह 'क्या' तय होता है अनुभवों से। अनुभव ही उसे सिखाते हैं और अनुभव ही चलाते-आगे बढ़ाते हैं। किसी याददाश्त को जमाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है दिमाग को। उसके कई सारे हिस्से सक्रिय होते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं और तब जाकर कोई मेमरी तैयार होती है। अब बताइए कि जिन बातों को लेकर इतना परेशान रहते हैं आप, क्यों वे सभी इस काबिल हैं कि उसके लिए मगजमारी करनी पड़े।

धन्यवाद दीजिए कि आप कुछ भूल गए और इस तरह से बेकार की जानकारी से बच गए। हो सकता है कि जो अभी आपको याद नहीं आ रहा, वह याद आने के काबिल ही नहीं। उसका दिमाग से चले जाना ऐसा है, जैसे सिस्टम के रिसाइकल-बिन का साफ हो जाना। बस इतना याद रखिए कि किसी को यादों में बसाना इतना आसान नहीं होता।

शेयर करें अपने अनुभव

जीवन की दिनचर्या के अनुभवों में आप कैसे आनंद महसूस करते हैं, हमें बताएं **nbtreader@timesgroup.com** पर, और सब्जेक्ट में लिखें-**'जीवन आनंद'**

हीटवेव के खतरों से मत बनिए अनजान

मृत्युंजय राय

क्लाइमेट जर्नलिस्ट जैफ गूडेल (Jeff Goodel) की किताब **'The Heat Will Kill You First'**, में बताया गया है कि धरती का तापमान बढ़ने से लोगों को किस तरह की आपदा से गुजरना पड़ रहा है।

हीटवेव का सितम | लांसेट प्लैनेटरी हेल्थ मैगजीन के मुताबिक, साल 2000 से 2019 तक दक्षिण एशिया में गर्म मौसम के चलते सालाना औसतन एक लाख 10 हजार लोगों की जान गई। वहीं, वर्ल्ड वेदर एट्रिब्यूशन के वैज्ञानिकों का कहना है कि क्लाइमेट चेंज के कारण भारत और पाकिस्तान में हीटवेव का खतरा 30 गुना तक बढ़ गया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, साल 2000 से 2019 के बीच हर साल औसतन 24 दिन हीटवेव वाले रहे। इससे पहले के 20 वर्षों में यह आंकड़ा 10 दिनों का ही था। वहीं, साल 2010 से 2019 तक गर्म मौसम से करीब 30 प्रतिशत ज्यादा मौतें हुईं।

AI Image

विचार विंडो

कामकाज में परेशानी | दिक्कत की बात यह है कि भारत जैसे देशों में यह समस्या और विकराल रूप लेने जा रही है। अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक, दिल्ली में गर्मी के मौसम में तापमान जब बहुत बढ़ जाता है, तब हर घंटे कम से कम 15-20 मिनट के कामकाज का नुकसान होता है। वहीं, भारत में हर साल गर्मी के चलते 101 बिलियन मैन आवर का नुकसान होता है। मैकिंजी ग्लोबल इंस्टिट्यूट की स्टडी के मुताबिक, 1980 में अगर इसके चलते 10 पर्सेंट वर्किंग आवर का नुकसान हो रहा था, तो अब यह आंकड़ा 15 प्रतिशत हो चुका है।

जॉब लॉस का खतरा | अनुमान है कि साल 2030 तक बेहद गर्म मौसम के चलते वर्किंग आवर का नुकसान भारत में और बढ़ जाएगा। नतीजा यह होगा कि देश के कुल GDP को 2.5% के आसपास की चपत लग सकती है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में वर्कफोर्स का 75 प्रतिशत हिस्सा ऊंचे तापमान वाली जगहों पर काम करता है। ऐसे में गर्मी और बढ़ने से लेबर प्रोडक्टिविटी घटेगी। वहीं, साल 2030 तक दुनियाभर में हीट स्ट्रेस के चलते 8 करोड़ जॉब लॉस की नौबत आएगी। इसमें से करीब साढ़े 3 करोड़ जॉब लॉस अकेले भारत में होगा।

जिंदगी पर असर | गूडेल लिखते हैं कि गर्मी बड़ी खामोशी से लोगों की जान लेती है। उनका दावा है कि अमेरिका में किसी अन्य मौसम की तुलना में हीट सबसे अधिक जिंदगियों पर असर डाल रही है। वह लिखते हैं कि कुछ नीति-निर्माताओं की ओर से इस सिलसिले में पहल शुरू हुई है। वे नए हीट वॉर्निंग सिस्टम बना रहे हैं और जिस तरह से तूफानों को नाम दिया जाता है, वैसा ही हीटवेव को लेकर भी किया जा रहा है।

गरीब चुका रहे कीमत | गूडेल इस बात की ओर भी ध्यान दिलाते हैं कि हीटवेव की सबसे अधिक कीमत वंचित तबके और गरीब देशों को चुकानी पड़ती है। इस सिलसिले में वह एयर कंडिशनिंग का जिक्र करते हैं। वह कहते हैं कि इस वजह से दो तरह का समाज बना है। एक जो गर्मी से बचने के लिए एयर कंडिशनिंग की पनाह लेता है, जबकि दूसरा वर्ग इससे महरूम है क्योंकि वह इसका खर्च नहीं उठा सकता।

हीटवेव पर पहल | गूडेल की किताब में सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। वह हीटवेव से प्रभावित लोगों के साथ क्लाइमेट चेंज को लेकर अवेयरनेस फैलाने वालों का भी रोचक ढंग से जिक्र करते हैं। वह बताते हैं कि ये लोग किस तरह की पहल कर रहे हैं। वे किस तरह से क्लाइमेट चेंज से प्रभावित लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। बर्फ पिघलने से दुनिया पर क्या असर हो रहा है, इसे समझने के लिए वह चिली से अंटार्कटिका तक नाव से यात्रा करते हैं।

विकास का मॉडल | हकीकत यह है कि समूची दुनिया इस समस्या से दो-चार हो रही है और लीडरों के पास कोई समाधान नहीं है। उन्हें शहरों के विकास के मॉडल पर भी मौसम के हिसाब से गौर करना होगा। कंक्रीट के जंगल शहरी इलाकों का तापमान आसपास के ग्रामीण इलाकों के मुकाबले 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देते हैं। इसके चलते AC, फ्रिज वगैरह का इस्तेमाल बढ़ता है। ज्यादा बिजली की खपत मौसम का संतुलन बिगाड़ती है। इसलिए इस विषय पर नीति-निर्माताओं को व्यापक नजरिये से गौर करने की जरूरत है।

लिबरल हैं लड़कियां

प्रणव प्रियदर्शी

Gender gap पर आजकल काफी चर्चा होती है, लेकिन Alice Evans इस पर नए ढंग से रोशनी डाल रही हैं। अमेरिका की स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फेलो Alice दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में Gender attitude पर पिछले कई वर्षों से काम कर रही हैं। उनका कहना है कि GenZ (यानी 2000 से 2010 के बीच पैदा हुई पीढ़ी) की लड़कियां और लड़के अपनी सोच में एक जैसे नहीं हैं। जहां लड़कियां ज्यादा लिबरल हो रही हैं, वहीं लड़कों का रुझान दक्षिणपंथी सोच की ओर बढ़ रहा है। Alice के मुताबिक लड़कियों की स्वतंत्र सोच और उनकी आत्मनिर्भरता लड़कों में कहीं न कहीं असुरक्षा का भाव बढ़ा रही है। उदाहरण के लिए, यूरोप में जहां वेतन कम हैं और जॉब टेंपरेरी, लड़के परेशान हैं कि वे मनचाही हैसियत हासिल नहीं कर पा रहे। उन्हें लगता है कि प्रवासी और लड़कियां उनके हिस्से की नौकरियों पर कब्जा करके उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। लड़कियों का संगठित रूप में सामने आना लड़कों की दुश्चिंताओं में इजाफा करता है।

Alice Evans

ये दुश्चिंताएं अक्सर अजीब और कभी-कभी खतरनाक रूप में सामने आती हैं। स्पेन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में मी टू मूवमेंट का ऐसा असर देखा गया। स्पेन में मी टू रैली के बाद अति दक्षिणपंथी पार्टी को पुरुषों के वोट में बढ़ोतरी देखी गई। दक्षिण कोरिया में भी मी टू मूवमेंट मजबूती से उभरा जिसने पुरुषों की खीझ बढ़ाई। वहां पब्लिक बाथरूम इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की चोरी-छुपे फिल्म बनाकर उसे महिला के पर्सनल डीटेल्स के साथ ऑनलाइन सर्कुलेट करने का ट्रेंड आम है। भारत की बात करें तो उत्तर के मुकाबले दक्षिणी राज्यों में महिलाओं का घरों से निकल कर काम करना आम है। लेकिन वहां भी मर्द शादी में अपना कंट्रोल बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। Alice के मुताबिक वहां इसकी झलक Gender violence के बढ़े हुए आंकड़ों में दिखती है। बहरहाल, ये प्रवृत्तियां जहां चिंता जगाती हैं वहीं यह भी बताती हैं कि लड़कियों का आगे बढ़कर यथास्थिति को चुनौती देना निरर्थक नहीं है। यह प्रतिक्रिया पैदा कर रहा है। अभी भले यह प्रतिक्रिया नेगेटिव हो, पर चुनौती के साथ संवाद की भी प्रक्रिया चलती रही तो आगे चलकर इसके पॉजिटिव मोड़ लेने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

आधी दुनिया

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

hindi.speakingtree.in

सुख की सीपियां आध्यात्मिकता के सागर में ही मिलेंगी

स्वामी अवधेशानंद गिरि

जब हम विकारों से ग्रस्त हो जाते हैं तो हमारा स्वभाव भी बदल जाता है। बदला स्वभाव हम में क्रोध, भय, द्वेष, घृणा जैसी दिक्कतें लाता है। जब इन दिक्कतों को हराया जाता है, तब हमारी आत्मा में क्षमा का शांत झरना बहने लगता है। आत्म विश्लेषण ऐसा हथियार है जो न केवल आपको ऐसी चर्चाओं से दूर रखने में मदद करता है, बल्कि आपकी तरक्की का रास्ता भी खोलता है। सब जानते हैं कि मनुष्य अच्छाइयों और बुराइयों का मिश्रण है। सद्गुण और दुर्गुण किसी न किसी अनुपात में हर किसी में होते हैं। अच्छा तो यह होगा कि हम दूसरों के सद्गुणों को समझें और उनको अपनाने की कोशिश करें। लेकिन याद रहे कि तरक्की के लिए खुद को टेस्ट करना और अपने दुर्गुणों को दूर करने के लिए लगातार कोशिश करते रहना बहुत जरूरी है। अध्यात्म ही सांसारिकता के बंधनों में जकड़े मनुष्य को ईश्वर की नजदीकी का आभास कराता है।

भौतिकता से हम थोड़ी देर का बाहरी आनंद तो आसानी से पा सकते हैं, पर यह स्थायी नहीं होता। अध्यात्म मनुष्य को स्थायी आंतरिक आनंद प्रदान करता है। सांसारिकता मनुष्य को पूरी तरह से भौतिकवादी बना देती है। आध्यात्मिक होने का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ ले। उसे अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करते हुए आध्यात्मिक आनंद पाने के लिए लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। हम कितना भी ज्ञान पा लें, पर जब तक हमें उन नियमों का पता नहीं है, जो मनुष्य के मनोवेग, भावनाओं और इच्छाओं पर कंट्रोल करते हैं तब तक हमारा ज्ञान अधूरा ही है। मनुष्य को बाहरी वस्तुओं में ज्यादा आनंद मिलता है, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन सबसे ऊपर उठकर आत्मिक खोज करने के लिए हमेशा कोशिश रहते हैं।

कुछ लोगों को भोजन में आनंद मिलता है, किसी को खूबसूरत वस्त्रों में आनंद मिलता है तो कोई संपत्ति के स्वामित्व में सुख का अनुभव करता है। इन सबसे हटकर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिन्हें आध्यात्मिक चिंतन में ही परम आनंद मिलता है। मनुष्य आध्यात्मिकता के सागर में जितना गहरा उतरेगा, उसे उतने ही सुख के सीप प्राप्त होंगे। मनुष्य भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। इसके लिए वह नैतिक-अनैतिक का भी ध्यान नहीं रखता। उसका एक ही टारगेट होता है, अधिक से अधिक भौतिक सुखों को प्राप्त करना। इसके उलट आध्यात्मिक आनंद, जो कि जीवन का असली आनंद है, उसकी प्राप्ति के प्रति वह इतना गंभीर नहीं होता। वह स्थायी सुख से ज्यादा महत्व क्षणिक सुख को देता है। भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए हम बाहर की ओर भागते हैं और आध्यात्मिक सुख के लिए अंदर की ओर। अध्यात्म की नाव पर सवार होकर ही मनुष्य संसार सागर को सफलतापूर्वक पार कर सकता है।

अज्ञानता के चलते पैदा होने वाले अनेक द्वंद्व मनुष्य को व्यथित करते हैं। अनेक बार किसी संशय के चलते बेचैनी दिखती है। हमारे अंतःकरण के लिए यह सही नहीं है, फिर भी ये चीजें वहां बसी रहती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है अविवेक और अज्ञान। इन सबसे मुक्ति के लिए अधिकारी बनना पड़ता है। हम सबको आदर्श के हिसाब से रहना चाहिए। वर्जनाएं टूटनी नहीं चाहिए। जो मना है, उससे निश्चित रूप से दूर रहना चाहिए। फिर वर्जनाओं के बारे में कौन बताएगा, यह ज्ञान कहां से आएगा? तो इसके लिए एक ही साधन है, आध्यात्मिक विचार।

प्रस्तुति : सुभाष चंद्र शर्मा

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ जमीन से पहचान

4 मार्च को 'जीवन आनंद' कॉलम में 'बहुत हसीन हैं पांव, जमीन पर जरूर रखिए' शीर्षक से प्रकाशित लेख पढ़ते ही फिल्म पाकीजा का यह डायलॉग याद हो आया- आपके पांव देखे, बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा मैले हो जाएंगे। लेकिन लेखक ने जमीन पर पैर टिके होने को महत्व दिया है। सफलता की उड़ान भरने वालों की निगाहें आसमान पर और कदम हवा में होते हैं। लेकिन हवा में उड़ने वालों को जमीन पर उतरना ही पड़ता है, क्योंकि यहीं पर उनकी पहचान बनती है। हवा में उड़ने वालों का हाल पतंग की तरह होता है, जब कटे तो आसरा जमीन का ही होता है।

मधुरिमा रावत, ईमेल से

■ सफर का साथी

19 फरवरी को प्रकाशित लेख 'पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाता है यात्रा को मजेदार' पढ़ा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो एक-दूसरे से जुड़ने का मौका मिलता है। कहते हैं, दुनिया की सैर करनी है तो पुस्तक पढ़ो। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा करते हैं, तो किताब से मिलने वाली कई जानकारियां बातों-बातों में ही आप पा सकते हैं। बस और हवाई जहाज के सफर में लोग एक-दूसरे से ज्यादा नहीं जुड़ पाते हैं। बैठने की व्यवस्था एक-दूसरे से जुड़ने नहीं देती। लेकिन अगर आप ट्रेन से लंबी यात्रा कर रहे हैं, तो सफर के बीच अजनबियों में भी मित्रता हो जाती है। उनसे एक जुड़ाव महसूस होने लगता है।

मोहित श्रीवास्तव, ईमेल से

■ संगति की खुशियां

हमारी संगति भी हमारे जीवन की खुशियों को निर्धारित करती है। हम जिस संगति में रहते हैं, उसका असर थोड़ा-बहुत हम पर जरूर पड़ता है। अगर हम भोग-विलास, लोभी-लालची लोगों की संगत करेंगे तो उनकी नकारात्मक बातें हमारे जीवन को प्रभावित करेंगी। वहीं हम देशहित, लोकहित, समाजसेवी सोच रखने वालों का संग करेंगे तो हमारी सोच भी उनके जैसी बनती जाएगी। हम भी अच्छे काम करेंगे। जब हम निःस्वार्थ भाव से कोई काम करते हैं तो उससे हमें मानसिक शांति मिलती है।

राजेश कुमार चौहान, ईमेल से

readersmail.nbt@gmail.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

खबरः मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता प्रधानमंत्री मोदी।

टिप्पणीः वैसे भी किसी का नाम लिए बिना खरी-खोटी सुनाने की कला तो कोई आपसे ही सीखे।

- नवीन सी. टेलर, ईमेल से

आर.एन.आई. पंजीयन नंबर 1613/1957 स्वत्वाधिकारी बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए आर. कृष्णमूर्ति द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 से प्रकाशित और उनके द्वारा (1) टाइम्स ऑफ इंडिया सबर्बन प्रेस, आकुर्ली रोड, निकट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली (पू.) मुंबई 400101 एवं (2) टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट सिटी, प्लॉट नं. 4, टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे बेलापुर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई-400708. फोन नं. (022) 2760 9999 ; फैक्सः (022) 2760 5275 । फोन मुंबईः (022) 66353535, 22733535 रिस्पांसः (022) 66353636, 22733636 फैक्सः (022) 22731889, 22731144, कांदिवली (022) 28872324 से मुद्रित। स्थानीय संपादक (मुंबई) : सुंदर चंद ठाकुर (पी. आर. बी. अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी) सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। सड़क व रेल परिवहन सेवा शुल्कः मुंबई, ठाणे व रायगड जिलों के बाहर 1.00 रुपया। विमान सेवा शुल्कः रायपुर, नागपुर, गोवा एवं वाया 2.00 रुपये, इंदौर, चेन्नै एवं वाया 3.00 रुपये, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, कोयम्बतूर, एरनाकुलम, हैदराबाद, कोझीकोड, मंगलूर, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वाइजग एवं वाया 4.00 रुपये, दिल्ली, कोलकाता, एवं वाया 5.00 रुपये।

कल्पमेधा

जो मैत्री महानता और उदार चेतना के बजाय धन से खरीदी जाती है, वह न चल सकती है और न कुछ लाभ दे सकती है।

– मैक्यावैली

रोजगार का संघर्ष

प्रलोभन देकर रूसी सेना में भर्ती कराए गए भारतीय युवाओं का मामला उजागर होने के बाद सरकार सतर्क हो गई है। जांच एजंसियां जगह-जगह छापे मार कर पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि अब तक कितने ऐसे भारतीय युवाओं को धोखे से रूस भेजा और वहां की सेना में भर्ती कर यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में तैनात किया गया है। अभी तक इसका वास्तविक आंकड़ा पता नहीं चल सका है, मगर सीबीआइ की जांच में खुलासा हुआ है कि कई एजंसियों ने बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को छात्र वीजा पर रूस भेजा और वहां उन्हें सेना में सहायक के रूप में तैनात कर दिया गया। यह मामला तब सामने आया, जब वहां से कुछ युवाओं के मारे जाने की खबरें आईं। अब सरकार उन एजंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और धोखे से रूस भेजे गए भारतीय युवाओं को मुक्त कराने का प्रयास कर रही है। हालांकि यह कोई पहली घटना नहीं है, जब युवाओं ने रोजगार की तलाश में दूसरे देश का रुख किया। एजंटों की मदद लेकर गलत तरीके से दूसरे देश में प्रवेश पा गए। अक्सर खाड़ी देशों से भी इसी तरह भारतीय युवाओं के बंधक बनाए जाने की खबरें आती हैं, जो नौकरी दिलाने वाले एजंटों की मदद से वहां जाते हैं। पिछले वर्ष एजंटों की मदद से चोरी-छिपे अमेरिकी सीमा में प्रवेश करने की कोशिश करते कई नौजवान मारे गए थे।

करीब दो महीना पहले ही जब इजराइल ने भारत से मजदूरों की मांग की और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि की सरकारों ने वहां जाने के लिए युवाओं की भर्ती खोली, तो भीड़ उमड़ पड़ी। भारतीय युवाओं में विदेश जाकर नौकरी करने की ललक कुछ अधिक देखी जाती है। यही वजह है कि ब्रिटेन, कनाडा आदि ऐसे देशों में जाने के लिए युवा और उनके परिजन मुंहमांगी रकम देने को तैयार नजर आते हैं, जहां जाना आसान और रोजगार के अवसर अधिक हैं। मगर गलत तरीके से रूस भेजे गए युवाओं के मामले से एक बार फिर रेखांकित हुआ है कि यह केवल विदेश जाकर नौकरी करने और बस जाने की ललक का मामला नहीं है। दुनिया के बहुत सारे देश जानते हैं कि भारत में श्रम सस्ता है, इसलिए भी वे भारतीय नौजवानों को अपने यहां काम का मौका देते हैं। फिर भारतीय युवा जब विदेश में मिलने वाले मेहनताना की तुलना भारत में मिलने वाले मेहनताने, वेतन, भत्तों आदि से करते हैं, तो उन्हें बहुत कम समय में अधिक बचत नजर आती है।

हालांकि नौकरी आदि के लिए विदेश जाने वालों के लिए पंजीकरण कराने का प्रावधान है, ताकि सरकार के पास उन लोगों को आंकड़ा रहे। मगर फिर भी बहुत सारे युवा नियम-कायदों के मुताबिक काम न मिल पाने की वजह से एजंटों के जरिए दूसरे देशों में प्रवेश कर जाते हैं। वहां उन्हें तरह-तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। यह स्थिति इसलिए है कि अपने देश में उन्हें उनके हुनर के मुताबिक काम के अवसर उपलब्ध नहीं हैं। जिन्हें काम मिल भी जाता है, उन्हें गुजारे लायक पैसा भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। मगर सरकार का दावा है कि बेरोजगारी की दर लगातार घट रही है। स्टार्टअप, मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों से युवाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है। अगर ऐसा होता, तो शायद इतने सारे युवाओं को रूस जाकर जोखिम वाली स्थितियों में काम न करना पड़ता।

महंगा आहार

कुछ समय पहले हरी सब्जियों की कीमतों में आई नरमी की वजह से महंगाई से उपजी परेशानी से जो राहत दिखने लगी थी, अब वह फिर से सिर उठाने लगी है। बाजार में खुदरा वस्तुओं के दाम में तेजी ने कई लोगों की थाली पर असर डालना शुरू कर दिया है। यों खाने-पीने के सामान की कीमतों में आई उछाल ने बीते महीने ही लोगों को आने वाले दिनों के संकेत दे दिए थे। 'क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस' की ताजा रपट के मुताबिक महंगाई की मार का ज्यादा असर शाकाहारी थाली पर पड़ा है। खासकर प्याज और टमाटर के दाम में सालाना आधार पर क्रमशः 29 फीसद और 38 फीसद की बढ़ोतरी हो गई। इसकी वजह से शाकाहारी थाली सात फीसद तक महंगी हो गई। स्वाभाविक ही कीमतों में इस बढ़ोतरी ने लोगों में इनके उपयोग को लेकर हिचक पैदा की है। चूंकि भोजन में प्याज और टमाटर की खासी भूमिका रहती है, इसलिए मांसाहारी थाली पर भी इसका असर पड़ा है। हालांकि इस अवधि के दौरान मांसाहारी भोजन में कुछ कमी दर्ज की गई।

दरअसल, आम उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें ऊंची होती हैं तो लोग उनकी खरीदारी को लेकर कई बार प्राथमिकता का निर्धारण करने लगते हैं। कम जरूरी चीजों की खरीदारी बाद के लिए टाल दी जाती है, मगर खाने-पीने सहित कुछ अनिवार्य चीजों की कीमतें कई बार घर के बजट को असंतुलित कर देती हैं। आमतौर पर शाकाहार के अभ्यस्त लोगों के खानपान में प्याज-टमाटर एक जरूरी हिस्सा होता है, जो उनकी थाली की सब्जियों में स्वाद भरता है। मगर इनके साथ-साथ अब अन्य हरी सब्जियों के दाम ने भी शाकाहार के सामने चुनौती पेश की है। यों ठंड के मौसम में आमतौर पर हरी सब्जियों का उत्पादन और आपूर्ति ठीकठाक होने की वजह से बाजार में उसकी कीमतें भी काफी नरम रहती हैं। मगर इस वर्ष लगभग सभी हरी सब्जियों के दाम जिस स्तर पर स्थिर रहे, उसे इनका सस्ता होना नहीं कहा जा सकता। अगर खासी तादाद में लोग सब्जी खरीदते हुए हाथ खींचने लगते हैं, तब इसका मतलब है कि बाजार में कीमतों को लेकर सरकार को जरूरी कदम उठाने की जरूरत है।

पक्षी प्रजातियों पर मंडराता खतरा

पिछली एक शताब्दी में तस्करी, शिकार और पारिस्थिकी-तंत्र के असंतुलन की वजह से अनेक दुर्लभ पक्षी धरती से हमेशा के लिए गायब हो गए।

अखिलेश आर्येंदु

इस समय दस लाख से अधिक वन्यजीव प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। वर्तमान में पक्षियों की तकरीबन दस हजार जीवित प्रजातियां हैं, जिनमें से एक हजार चार सौ अस्सी विलुप्त होने को हैं और दो सौ तेईस गंभीर स्थिति में हैं। 'स्टेट आफ इंडियाज बर्ड्स' के मुताबिक कुछ 'रैप्टर' और बतखों की तादाद में सबसे ज्यादा कमी देखने को मिली है। इसी तरह भारतीय गौरैया और कठफोड़वा खत्म होने के कगार पर बताए जा रहे हैं। यों तो वन्य जीव-जंतुओं के विलुप्त होने का खतरा लंबे समय से मंडराता रहा है, लेकिन पिछली एक शताब्दी में विज्ञान के विकास के साथ वन्यजीवों पर खतरा बहुत तेजी से बढ़ा है। आज के बदलते हालात में ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसों से बढ़ती चुनौतियों की वजह से पक्षियों का संरक्षण बेहद मुश्किल होता जा रहा है। तरह-तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं।

वन्यजीवों को विलुप्त होने या शिकार से बचाने के लिए भारत में 1873 में वन्यजीव संरक्षण कानून बनाए गए थे, लेकिन उनसे भी वन्यजीवों, खासकर पक्षियों को शिकार से बचाने में मदद नहीं मिल पाती थी। जब देश आजाद हुआ तो 1952 में वन्यजीव बोर्ड की स्थापना की गई। फिर उसका पुनर्गठन 1991 में किया गया। बोर्ड के गठन के बाद वन्यजीवों के संरक्षण की कोशिशें तेज हुईं, फिर भी जीव-जंतुओं की तस्करी और शिकार पर पूरी तरह रोक नहीं लग पाई।

पिछली एक शताब्दी में तस्करी, शिकार और पारिस्थिकी-तंत्र के असंतुलन की वजह से अनेक दुर्लभ पक्षी भी धरती से हमेशा के लिए गायब हो गए। इसमें डोडो, कैरोलिना, तोता, यात्री कबूतर, हंसता हुआ उल्लू, लैब्राडोर बतख और दूसरे कई दुर्लभ पक्षी शामिल हैं। ज्यादातर पक्षियों के खत्म होने के पीछे इंसान का हाथ है। मसलन, दुनिया का इकलौता 'राब्स फ्रीज-लिब्ड ट्री फ्राग-टफी' मेढक 2016 में मर गया। उसे अटलांटा बोटेनिकल गार्डेन में रखा गया था। मगर उसके प्रजनन के लिए उसकी प्रजाति का कोई मेढक नहीं था। अब उसकी पीढ़ी धरती पर नहीं है। अफ्रीका में जेब्रा की एक उप-प्रजाति थी, जिसका नाम था क्वाग्गा। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक शिकारियों ने इनका इतना शिकार किया कि ये हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। 1971 में इक्वाडोर में खोजा गया पिंटा आइलैंड टारटाय यानी कछुआ भी खत्म हो चुका है। दुनिया का आखिरी थाईलैसीन, जिसका नाम बेंजामिन था, जिसे तस्मानिया टाइडर कहते थे, वह भी 1936 में खत्म हो गया।

विलुप्त जीव-जंतुओं में पक्षी-वर्ग की विशेष प्रजातियां शामिल हैं। सबसे अधिक प्रजातियां अफीका और दक्षिण एशिया के देशों में लुप्त हुई हैं। भारत में एक समय था, जब चिड़ियों की बारह सौ प्रजातियां पाई जाती थीं, लेकिन अब इनमें से पचास से अधिक प्रजातियां लुप्त हो गई हैं। एक अध्ययन के अनुसार पिछले पचास वर्षों में पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियां धरती से लुप्त हो गईं और कई लुप्त होने के कगार पर हैं। गिद्ध और कठफोड़वा जैसे पक्षियों की प्रजातियां लुप्त हो गई हैं या लुप्त होने के कगार पर हैं। विकास संबंधी अस्थायी नीतियों और

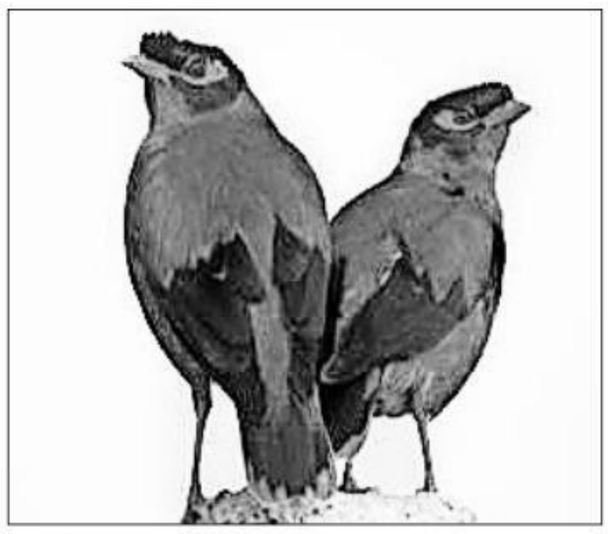

प्रकृति के प्रति बढ़ती असंवेदशीलता इसकी वजह बताई जा रही है। आज भी भारत के कई पक्षीवास खतरे में हैं। इससे पक्षियों के लुप्त होने का खतरा बढ़ गया है। 'बांबे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी' के ताजा अध्ययन में कहा गया है कि भारत के कम से कम दस जैव विविधता वाले इलाकों पर हमेशा के लिए लुप्त हो जाने का खतरा मंडरा रहा है। पक्षियों के महत्त्वपूर्ण वास-स्थानों को दुनिया भर में 'आइबीए' कहा जाता है। इनका संरक्षण भी चुनौतीपूर्ण हो गया है।

> **दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर वन्यजीवों की दुर्लभ प्रजातियों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार समवाय भी बनाया गया है, जिसका कार्य संकटापन्न प्रजातियों के अवैध अंतरराष्ट्रीय व्यापार को रोकना है। भारत भी इसका सदस्य है। भारत ने इस बाबत अनेक जीव-जंतुओं की तस्करी पर रोक लगाने के लिए बड़े स्तर पर कदम उठाए हैं, लेकिन वे नाकाफी रहे हैं, क्योंकि पक्षियों और दूसरे वन्यजीवों की घटती संख्या और लुप्त होती पक्षी प्रजातियों के संरक्षण को मुकम्मल नहीं किया जा सका है।**

हिमालय के तलहटी क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय के ऊंचे क्षेत्र, पूर्वी हिमालय का क्षेत्र, दक्षिण भारत तथा गंगा बेसिन क्षेत्र, भारतीय मरुस्थल थार रेगिस्तान, इंडोमलाया उपखंड जैसे क्षेत्रों में पाए जाने वाले अनेक पक्षियों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया है। गोल्डन ईगल, बाज, गौर, गोडावन, सारस, तिलोर, हाक, निकोबारी कबूतर के अस्तित्व पर खतरा दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश भारत का ऐसा हरियाली संपन्न प्रदेश है, जहां जैव विविधताएं मौजूद हैं। यहां पक्षियों की अनेक प्रजातियां निवास करती हैं। इनका संरक्षण लगातार चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। यहां पौंग बांध में हर साल मध्य एशिया और यूरोप की चौवन पक्षी प्रजातियां आती हैं। हिमालयी क्षेत्र में आने के कारण यहां का वातावरण हमेशा ठंडा बना रहता है। मगर बदलते मौसम, लोगों का कृत्रिमता की ओर अधिक झुकाव, प्रकृति के प्रति असंवेदनशीलता तथा चोरी-छिपे शिकार के कारण यहां के उद्यान के दुर्लभ पक्षियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। राज्य सरकार इस ओर जागरूक जरूर है, लेकिन समस्या लोगों का पक्षियों के प्रति घटता प्यार है, जो इनके लिए संकट का कारण बन रहा है। इसलिए आम आदमी में हिंसा के बजाय अहिंसा और और क्रूरता के बजाय करुणा जैसे मूल्यों के प्रति जागरूक करना बेहद जरूरी है।

इसी प्रकार पक्षियों के संरक्षण के लिए केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना वन्यजीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत 1992 में की गई। इसका मकसद चिड़ियाघरों के कामकाज को देखना है। यह बारह सदस्यों वाली संस्था है। राज्य स्तर पर भी तकरीबन ऐसे ही संरक्षण बोर्ड बने हुए हैं, लेकिन इनकी सक्रियता के बारे में समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं।

दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर वन्यजीवों की दुर्लभ प्रजातियों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार समवाय भी बनाया गया है, जिसका कार्य संकटापन्न प्रजातियों के अवैध अंतरराष्ट्रीय व्यापार को रोकना है। भारत भी इसका सदस्य है। भारत ने इस बाबत अनेक जीव-जंतुओं की तस्करी पर रोक लगाने के लिए बड़े स्तर पर कदम उठाए हैं, लेकिन वे नाकाफी रहे हैं, क्योंकि पक्षियों और दूसरे वन्यजीवों की घटती संख्या और लुप्त होती पक्षी प्रजातियों के संरक्षण को मुकम्मल नहीं किया जा सका है। ऐसे में सवाल उठता है कि पक्षियों की घटती संख्या को कैसे रोका जा सकता है? क्या संरक्षण वाली परियोजनाओं को और सुधारने की जरूरत है या दूसरे स्तर पर भी कदम उठाए जाने चाहिए?

इसमें राष्ट्रीय स्तर के वन्य अभ्यारण्यों और उद्यानों के निर्धारित क्षेत्रफल को बढ़ाना और पक्षियों के संरक्षण के लिए बजट में और अधिक व्यय का प्रावधान, अवैध शिकार, सुरक्षा क्षेत्र को और बेहतर करना, दुर्लभ पक्षियों के संरक्षण पर और ध्यान देना, पर्यावरण को पक्षियों के अनुकूल बनाना, विकास की अंधी दौड़ में पक्षी उद्यानों के आसपास की रिहायशी बस्ती को हटाना या दूसरे स्थानों पर उद्यानों को स्थानांतरित करना, जल, भोजन और अन्य वातावरणीय समस्याओं को खत्म करके पक्षियों के वास के अनुकूल बनाना और शिकारियों को कठोर दंड देने के लिए मुफीद कानून बनाने से लेकर पक्षियों के प्रति लोगों में प्यार बढ़ाने जैसे कदम शामिल किए जाने चाहिए। पक्षियों को बचाने की चुनौती जानवरों से ज्यादा है। इसकी वजह उनका एक ठिकाना न होना है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

नैतिकता के तकाजे

चंद्रकुमार

हाल ही में एक चौंकाने वाली खबर आई कि जापान के एक शहर में उच्च विद्यालय के एक प्रधानाध्यापक को इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया कि वह काफी के लिए कम पैसे का भुगतान कर ज्यादा पैसे वाला कप भरता हुआ पकड़ा गया। मौका ताड़ कर पिछले साल भर से कई दफा वह ऐसा कर चुका था। एक दिन उस दुकान के कर्मचारी ने उसे ऐसा करते देखा, जिसकी शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। उसका न केवल शिक्षण लाइसेंस रद्द कर दिया गया, बल्कि उसे सेवानिवृत्ति के सारे परिलाभों से भी वंचित कर दिया गया। प्रधानाध्यापक ने सभी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से माफी मांगी कि शिक्षक होने के नाते समाज में नेतृत्व देने और खुद मिसाल बनने की जगह उसने एक गलत उदाहरण प्रस्तुत किया। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने उस पर इस मामले में मुकदमा करने से मना कर दिया। शायद उसे अपनी गलती की सजा मिल ही चुकी है।

ऐसे भी समाज होते हैं जहां नैतिकता के तकाजे इतने ज्यादा सुदृढ़ होते हैं। जानबूझ कर ऐसा कृत्य करना निस्संदेह बेईमानी है, पर इसे इतनी बड़ी गलती माना गया जिसकी सजा नौकरी से बर्खास्तगी हो! दरअसल, हम अपने परिवेश की वजह से इस पर सवाल उठा सकते हैं, पर जिन समाजों में नैतिकता सबसे बड़ा मानवीय मूल्य हो, वहां अनैतिक कार्यों के लिए ऐसी ही नजीर सामने रखी जाती है। गाहे-बगाहे सोशल मीडिया पर कुछ देशों की स्कूलों में सिखाए जा रहे स्वच्छता, सार्वजनिक जीवन में अपेक्षित व्यवहार और नैतिकता के वीडियो देख कर यही लगता है कि जो समाज इन मूल्यों को पोषण कर उनकी रक्षा करते हैं, उनके लिए यह वाकई बड़ी घटना होगी कि उनका शिक्षक जानबूझ कर किसी अनैतिक कृत्य में शामिल हो। इन्हीं मानवीय मूल्यों से किसी स्थान विशेष की सभ्यता और संस्कृति निर्मित होती है। इसलिए वे अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए बहुत छोटी उम्र से ही ऐसे पाठ पढ़ाते हैं कि ये मूल्य उनकी जीवन शैली का हिस्सा बन जाते हैं। जहां ऐसे मूल्यों को महज कागजी और आदर्शवादी मान लिया जाता है, वहां उक्त घटना के परिणाम से अचंभित होना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए।

जिसे हम संस्कृति कहते हैं वह दरअसल मूल्य-आधारित जीवन शैली ही होती है। सभ्यताओं के विकास में जो समाज अपनी संस्कृति और उसमें निहित मानवीय सरोकारों को बनाए और बचाए रखता है, वही सर्वांगीण विकास का लक्ष्य प्राप्त कर पाता है। जापान न केवल औद्योगिक रूप से उन्नत देश है, बल्कि मानवीय मूल्यों के संरक्षण, परंपरा और आधुनिकता के सहज मेल और संवेदनशील समाज के रूप में अपनी अलग पहचान रखता है। मानव-मूल्यों के संरक्षण और विकास के लिहाज से दुनिया के बेहतरीन देशों में शामिल जापान का सांस्कृतिक विरासत और आधुनिकता का मेल भी अनुकरणीय है। 'उगते सूरज' की लालिमा से वहां के नागरिकों का जीवन यों ही प्रकाशमान नहीं है। वे इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं।

यों हमारी और जापान की सामाजिक परिस्थितियां एक जैसी नहीं है, लेकिन हम नैतिकता की कसौटी पर खुद को देखें तो अभी हमें इस दिशा में बहुत कुछ करना बाकी है। हमने सहज मानवीय मूल्यों और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता को सिरे से खारिज भले ही न किया हो, लेकिन उन्हें समग्रता में अंगीकार भी नहीं किया है। भ्रष्टाचार रूपी दानव हमारे समाज में हर स्तर पर मुंह बाए खड़ा दिखता है। अक्सर ऐसे वाक्यांश हमें परेशान करते हैं कि 'हमाम में सब नंगे हैं'। कई बार इसे स्वीकार्यता के लिए भी कहा जाता है। नैतिकता और मानवीय मूल्य दरअसल हमारी पाठ्यपुस्तकों तक ही सिमट कर रह गए लगते हैं। सार्वजनिक जीवन में, खासकर राजनीति में, बड़े से बड़े गलत आचरण को हम आखिर स्वीकार कर भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ाते हैं। जिन्हें अपने आचरण के कारण समाज से डरना चाहिए, कई बार वे अपने धन-बल और दुराचरणों से समाज को ही डराते हैं। अपने आसपास घट रही घटनाओं को देखें तो पग-पग पर अनैतिक और गलत आचरण की गहरे तक फैली बेलें हमें दिख जाएंगी। दुर्भाग्यवश, जीवन में सफल होने के लिए साम-दाम-दंड-भेद के रूप में हमने एक ऐसी वृत्ति स्वीकार कर ली है, जिसमें अनैतिक कुछ भी नहीं माना जाता!

दुनिया मेरे आगे

> **हमने सहज मानवीय मूल्यों और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता को सिरे से खारिज भले ही न किया हो, लेकिन उन्हें समग्रता में अंगीकार भी नहीं किया है। भ्रष्टाचार रूपी दानव हमारे समाज में हर स्तर पर मुंह बाए खड़ा दिखता है।**

अमेरिका में एक राष्ट्रपति को शपथ लेकर झूठ बोलने के कारण महाभियोग तक की नौबत आ गई थी। सार्वजनिक मंचों से लफ्फाजी और झूठबयानी हमारे यहां अक्सर कौशल समझ लिया जाता है। ऐसे में और क्या अपेक्षा की जाए! विश्व की प्राचीनतम और समृद्ध सभ्यता का दंभ भरते हुए हम यहां तक आ पहुंचे हैं कि गलत आचरण की किसी घटना से हम विचलित नहीं होते। हमारे स्वीकार के कारण ही समाज में जलकुंभी की तरह फैली बीमारी बन गई है और हमें फर्क नहीं पड़ता। किसी-न-किसी बहाने से हम आखिर इसे सामाजिक स्वीकृति दे रहे हैं। मगर धर्म-अधर्म के फेर में हम कहीं संवेदनहीनता की तरफ तो नहीं बढ़ रहे? सबसे बड़ा धर्म मानवीयता है जो नैतिकता और शुचिता की बुनियाद पर ही टिका है। उसे बचा कर ही सभ्यता और संस्कृति को अक्षुण्ण रखा जा सकता है। यह हमें समझने की जरूरत है।

चौपाल

पत्थर होती संवेदनाएं

'मानवीयता के विरुद्ध' (संपादकीय 4 मार्च) का विवरण शांति और सद्भाव के प्रतिकूल कृत्य में इजराइल की क्रूरता का नमूना है। हमास आतंकियों के अंत के बहाने निर्दोष, भूखे, लाचार लोगों और अबोध शिशुओं के लगातार कत्लेआम की दारुण स्थिति में संयुक्त राष्ट्र की चुप्पी और इजराइल के समर्थक देशों की सिर्फ घड़ियाली आंसू घोर निंदनीय है। घुटने के बल पर रेंगती अंतरराष्ट्रीय कानून सहित संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की प्रासंगिकता को बेमानी कर दिया गया है। वीटो के हथियार से लैस चंद देशों की दादागिरी ने दुनिया को विध्वंस के मुहाने पर खड़ा कर रखा है। विश्व के युद्ध इतिहास के पन्ने साक्षी हैं कि आखिर में युद्धरत देशों को कभी न कभी समझौते के सिंहासन पर बैठकर हाथ मिलाना पड़ता है, लेकिन तब तक भीषण तबाही और असंख्य जीवन लीला के अंत हुए अवशेष वापस नहीं होते। संपादकीय का यह चित्रण मार्मिक है कि गाजा के अस्पतालों, स्कूलों, शरणास्थली जैसे जगहों में भी इजराइल द्वारा जनसंहार किया जाना मानवीयता के विरुद्ध है।

– अशोक कुमार, पटना, बिहार

एक कदम और

फ्रांस में बीता 4 मार्च वहां के महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा दिन था। फ्रांस दुनिया का ऐसा देश बन गया है, जब वहां के सांसदों ने संसद के संयुक्त सत्र में एक विधेयक को मंजूरी दे दी, जो फ्रांस के संविधान में गर्भपात के अधिकार को सुनिश्चित करता है। एक अरसे बाद फ्रांस में इस संयुक्त सत्र के दौरान लंबे समय तक के लिए हाल तालियों के गड़गड़ाहट के साथ गूंजता रहा। ये संवैधानिक गारंटी फ्रांसीसी महिलाओं के लिए बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि पूरे यूरोप में रूढ़िवादी राष्ट्रवाद का उभार हो रहा है। आने वाले वक्त में अगर कोई ऐसी सरकार सत्ता में आ जाए जो महिलाओं के इस अधिकार को पलट दे, तो हैरानी नहीं होगी। जैसा प्रतिक्रियावाद उभार पर है, उसमें कल को यह दलील भी दी जा सकती है कि कि 'जान लेने का हक किसी को नहीं है' और ऐसा कहते हुए महिलाओं को उसके अधिकार से वंचित किया जा सकता है। एक उदाहरण अमेरिका का ही है, जहां अदालत ने गर्भपात को अवैध घोषित कर दिया था। कम से कम फ्रांस में ऐसा करना अब फिलहाल संभव नहीं होगा।

– जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

हल के बजाय

आत्याधुनिक तकनीक जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनती जा रही है। इसके उपयोग ने सुविधाएं तो दी हैं, मगर उनके बाधित होते ही तमाम व्यवस्था ठप हो जाती है, जिसका खमियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। इंटरनेट तमाम जरूरतों का घर बैठे समाधान करने में सक्षम है, मगर जब भी देश के किसी भी हिस्से में आंदोलन, हिंसा या अराजक स्थिति पैदा होती है तो व्यवस्था कायम करने के लिए प्रशासन इंटरनेट सेवा बंद कर देता है। यह कार्यवाही जायज तो लगती है, मगर जो आम जनता इसमें पिसती है, वह निर्दोष को सजा के समान है। सरकार को बजाय इंटरनेट बंद करने के ऐसे असामाजिक तत्त्वों से कड़ाई से निपटना चाहिए जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। त्वरित और सख्त कदम ही उचित समाधान है।

– अमृतलाल मारू 'रवि', इंदौर

सख्ती की जरूरत

झारखंड के दुमका में बेलगाम अपराधियों ने स्पेन की एक महिला से सामूहिक बलात्कार किया और उसके पति के साथ काफी मारपीट और लूटपाट भी की। 'बेखौफ अपराधी' (संपादकीय, 5 मार्च) में सही कहा गया है कि यहां विदेशी महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। पर्यटकों की सुरक्षा के प्रति शासन और प्रशासन उदासीन ही रहा। यों किसी भी महिला के खिलाफ ऐसे अपराधों को लेकर शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जानी चाहिए, मगर अब इस तरह के अपराध को सर्वाधिक गंभीर श्रेणी में रखा जाए और दोषियों को कठोरतम दंड भी दिया जाए। गनीमत है कि स्पेनी दंपति ने केवल अपराधियों को ही दोषी बताया और झारखंड और देश की जनता के बारे में कोई राय नहीं बनाई। जरूरत इस बात की है कि इस घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाए, ताकि दूसरे अपराधियों को एक ठोस सबक मिले।

– बीएल शर्मा 'अकिंचन', तराना, उज्जैन

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

कोशिका संवाद

हमारा शरीर कोशिकाओं का समूह है और कोशिकाएं परस्पर संवाद करती हैं, यह धारणा पुरानी है और अब वैज्ञानिक इस धारणा का वैज्ञानिक आधार भी सुनिश्चित करने की दिशा में पुख्ता तौर पर आगे बढ़ चले हैं। *नेचर* में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, हमारे शरीर में मौजूद प्रतिरक्षा और स्ट्रोमल कोशिकाओं के बीच परस्पर संवाद होता है, जिसे समझने की विधि का और विकास हुआ है। प्रतिरक्षा कोशिकाएं स्ट्रोमल कोशिकाओं का सहयोग करती हैं और स्ट्रोमल कोशिकाएं भी प्रतिरक्षा या इम्यून कोशिकाओं के साथ मिलकर काम करती हैं। इम्यून कोशिकाएं, मतलब रोग प्रतिरोधक कोशिकाओं के बारे में हम ज्यादा जानते हैं, पर स्ट्रोमल कोशिकाओं के बारे में जानना दिलचस्प है। ये ऐसी कोशिकाएं हैं, जो सहज शब्दों में अगर समझें, तो ये शरीर में मरम्मत के काम करती हैं। ये अंग संयोजक कोशिकाएं हैं और पूरे शरीर में पाई जाती हैं और कुछ ऐसे अंगों में, जहां कोशिकाओं के निर्माण की लगातार जरूरत है, ये ज्यादा रहती हैं। स्ट्रोमल कोशिकाओं के काम को हम समझें, तो त्वचा को देखना उपयोगी होगा। नई त्वचा नीचे से स्वतः ही ऊपर आकर ऊपरी त्वचा का स्थान लेती है, यह कार्य मुख्यतः स्ट्रोमल कोशिकाओं के मार्फत होता है।

अनेक अमेरिकी विश्वविद्यालयों के संयुक्त प्रयास से यह शोध संभव हुआ है और इसमें सबसे प्रमुख भूमिका रॉकफेलर यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों की है। वैज्ञानिकों का एक पूरा समूह कोशिकाओं के बीच संवाद को समझने की कोशिश में लगातार जुटा हुआ है और नित नए रहस्योद्घाटन हो रहे हैं। बहरहाल, इम्यून और स्ट्रोमल कोशिकाओं के संवाद से शरीर में जरूरी कोशिकाओं के निर्माण को बल मिलता है। विशेष रूप से सूजन या जलन होने पर इनका संवाद बहुत बढ़ जाता है और स्ट्रोमल कोशिकाएं कुछ ज्यादा ही सक्रियता से अपने काम को अंजाम देने लगती हैं। प्रतिरक्षा-विज्ञानी हालिया खोज से काफी खुश हैं। होमोस्टैसिस में और रोग की प्रगति के दौरान, इन सभी अंतःक्रियाओं को रेखांकित करने वाले तंत्र को पहचानने से प्रतिरक्षा विकारों के लिए नए, अत्यधिक प्रभावकारी उपचारों को सामने लाने में मदद मिल सकती है। त्वचा, आंत, जोड़ों और फेफड़ों की सूजन संबंधी बीमारियों में नवीन चिकित्सीय क्षमता को बल मिलेगा। हालांकि, रोगों हर चरण में मापने के पैमानों की अभी कमी है, जिससे उपचार में समस्या बनी रहती है। कोशिकाओं का अध्ययन और उनके परस्पर व्यवहार को समझना इसलिए भी जरूरी है, ताकि किसी रोग में होने वाले बदलावों और शरीर के अंदर रोग या विषाणुओं से होने वाली प्रतिरोधक कोशिकाओं की लड़ाई को समझने और हार-जीत को मापने में सुविधा हो। निश्चित ही इससे उपचार पद्धतियों को बल मिलेगा।

हमारे शरीर में मौजूद प्रतिरक्षा या इम्यून और स्ट्रोमल कोशिकाओं के बीच परस्पर संपर्क-संवाद होता है, जिसे समझने की विधि का सुखद परिष्कार हुआ है।

साफ तौर पर इस जरूरी शोध का मकसद स्ट्रोमल कोशिकाओं और न्यूरॉन्स द्वारा प्रतिरक्षा तंत्र में हमारे ज्ञान का विस्तार करना है। हम अगर कोशिकाओं के बारे में सब कुछ जान पाते हैं, तो इससे चिकित्सा की दुनिया में उपचार के नए तरीकों के सृजन के साथ ही, पुराने तरीकों को बदलने-सुधारने में पर्याप्त मदद मिलेगी। वैज्ञानिक तरह-तरह की कोशिकाओं की पहचान करने में जुटे हुए हैं। उनके हाथ एक ऐसी वैज्ञानिक विधि लग गई है, जिसे 'युलिपस्टिक' कहा जा सकता है, यह मोटे तौर पर एक ऐसी उपयोगी तकनीक है, जिससे अलग-अलग जैविक तंत्र में कोशिकाओं के परस्पर संवाद को समझना संभव है।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 11 मार्च, 1949

औद्योगिक नीति

हिन्द की पार्लियामेण्ट में उद्योग और रसद मंत्री डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की औद्योगिक नीति और उद्योगों की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला। यह आशावर्द्धक है कि देश का औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है। सन् १९४८ की तुलना में उद्योगों के उत्पादन में १२ से १६ प्रतिशत तक वृद्धि हो जायेगी, ऐसी आशा की जाती है। यह सन्तोष का ही विषय माना जायेगा; क्योंकि इस समय हमारी सबसे जरूरी मांग देश का उत्पादन बढ़ाना है, जिससे आवश्यक वस्तुओं का अभाव दूर किया जा सके और लोगों को जिस अभूतपूर्व संकट का सामना करना पड़ रहा है, उससे वह मुक्त हो जायेंगे। वस्तुओं के अभाव के कारण ही महंगाई का जन्म हुआ। और महंगाई ने लोगों में असन्तोष और बेचैनी को बढ़ाया है। वेतन, मजदूरी और महंगाई भत्ते बढ़ाने की पुकार भी इसीलिए उठ रही है। इसीलिए हमारे नेताओं और सरकार का ध्यान देश के उत्पादन को बढ़ाने की ओर लगा हुआ है। इस राष्ट्र-हित के कार्य में सभी वर्गों से सहयोग देने की अपील की जा रही है। उद्योगपतियों और मजदूरों दोनों ने मिलकर देश के उत्पादन को बढ़ाने में सहयोग किया है। किन्तु इस परिणाम पर सन्तोष मानकर बैठे रहने से काम न चलेगा। इस दिशा में निरन्तर जागरूकता और क्रियाशीलता आवश्यक होगी।

उद्योग मंत्री ने हमको बताया है कि सरकार ने औद्योगिक कारखाने खोलने की नीति अपनाई हुई है। दो कारखानों की योजना मंजूर की जा चुकी है और अनेक कारखानों की योजनायें विचाराधीन हैं, जिनके लिए २०० से ३०० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। यह धनराशि कहां से जुटाई जायेगी, इस बारे में अभी कुछ नहीं सोचा गया है। इसका यह अर्थ है कि सरकार की योजनायें अभी कागज पर सीमित हैं। उद्योग मंत्री ने जिन योजनाओं पर प्रकाश डाला है, उनमें खाद उत्पादन करने वाला कारखाना उल्लेखनीय है जो सिन्दरी में खोला जायेगा और जो एशिया का इस किस्म का सबसे बड़ा कारखाना होगा। आज हम विदेशों से खाद मंगा रहे हैं और वह काफी महंगा पड़ता है। हम अपने कारखाने में बने खाद पर सौ रुपये प्रति टन बचत कर सकेंगे। नये कारखाने शुरू करने के लिए हमें मशीनों के लिए विदेशों पर निर्भर करना पड़ता है, किन्तु सरकार देश में नये उद्योग शुरू करने की कोशिश कर रही है।

क्या हमेशा के लिए बदल जाएंगे चुनाव

यहां स्कैन करें

हरजिंदर | वरिष्ठ पत्रकार

एक बार चुनाव में एआई का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर शुरू हो गया, तो इसका इस्तेमाल सभी करने लगेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा, जब मशीनें ही मशीनों के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी।

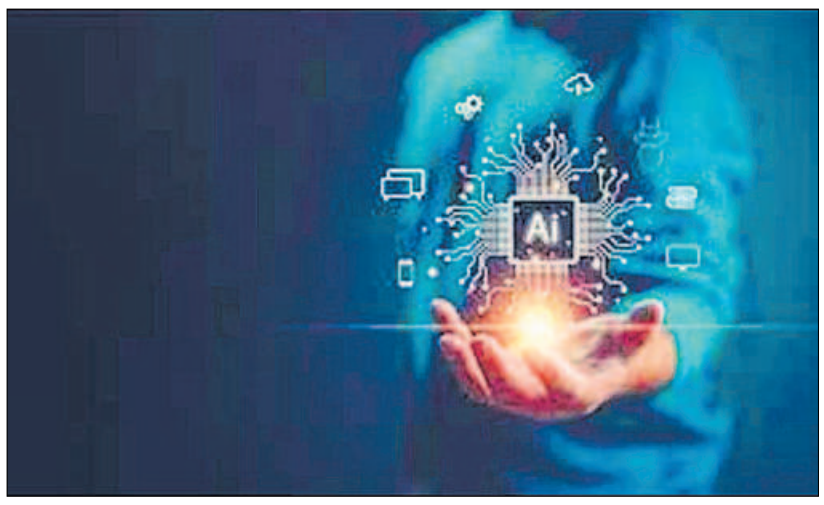

नवंबर महीने की शुरुआत में एक ई-मेल इनबॉक्स में आया। यह मेल एक वेबसाइट का था, जो एआई वॉयस जेनरेटर है, यानी कृत्रिम बुद्धि से तरह-तरह की आवाजें तैयार करने वाली वेबसाइट। इस मेल में दो लिंक थे- एक वेबसाइट का और दूसरे में नाम लिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जब इस दूसरे लिंक को क्लिक किया, तो वहां पंजाबी का एक गाना मिला- *तू मेरी हीर लगदी...*। 45 सेकंड के इस गाने की खासियत यह थी कि इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हूबहू आवाज में तैयार किया गया था। यह दरअसल एक नमूना था यह बताने के लिए कि वह वेबसाइट क्या कमाल कर सकती है? दूसरे लिंक को क्लिक करने पर जब हम वेबसाइट पर पहुंचे, तो वहां बताया गया कि आप 399 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेकर किसी की आवाज में कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोई भी बात किसी के मुंह से कहलवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 399 रुपये का यह सब्सक्रिप्शन ज्यादा है, तो इंटरनेट पर यही काम कराने के मुफ्त विकल्प भी मौजूद हैं।

अभी चंद रोज पहले जब पाकिस्तान के चुनाव में इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर उभरी, तो पार्टी ने इमरान खान की आवाज में एक धन्यवाद संदेश जारी किया। इमरान खान जेल में बंद थे और वहां इस तरह की किसी रिकॉर्डिंग की सुविधा उनके पास नहीं थी। साफ है, वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी एआई से तैयार आवाज थी, जो बिल्कुल उसी तरह की थी, जैसी इमरान खान की आवाज है। 2024 को चुनावों का साल कहा जा रहा है। इस साल दुनिया के कई बड़े और महत्वपूर्ण देशों में चुनाव होने हैं। पाकिस्तान का चुनाव इस साल का पहला महत्वपूर्ण चुनाव था और इस चुनाव में ही एआई ने दस्तक दे दी।

ऐसा नहीं है कि एआई का इस्तेमाल इसके पहले के चुनावों में नहीं हुआ है। अगर हम भारत का ही उदाहरण लें, तो दिल्ली विधानसभा के पिछले चुनाव में इसका इस्तेमाल सीमित स्तर पर हुआ था। *एमआईटी टेक्नोलॉजी रिव्यू* की एक रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी की बीजेपी को वोट देने की अपील के कुछ वीडियो जारी हुए थे। जो मूल वीडियो रिकॉर्ड हुआ, उसमें तो वह हिंदी में दिल्ली के मतदाताओं से वोट देने की अपील करते हैं। एआई की एक वीडियो तकनीक डीपफेक से इसके कई संस्करण तैयार हुए, जिनमें किसी में वह हरियाणवी में वोट देने की अपील कर रहे हैं, तो किसी वीडियो में भोजपुरी में और किसी में पंजाबी में। ये वीडियो इतनी अच्छी तरह तैयार किए गए थे कि किसी में कोई लब-ओ-लहजा गलत नहीं लग रहा था।

एआई का इस तरह का इस्तेमाल आपत्तिजनक नहीं है। समस्या वास्तव में इसके आपत्तिजनक इस्तेमाल को लेकर ही है, जिसके संकेत दिखने लग गए हैं। इसी साल के अंत में अमेरिका में भी राष्ट्रपति चुनाव हैं। पिछले दिनों वहां राष्ट्रपति जो बाइडन का एक वीडियो हर जगह दिखाई देने लगा, जिसमें वह कह रहे थे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ते हैं, तो लोगों को वोट ही नहीं डालने चाहिए। जाहिर है, यह फर्जी वीडियो था, जो डीपफेक से तैयार किया गया था। इस नए रुझान को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीपफेक को लेकर देश और अपनी पार्टी के लोगों को एक से अधिक बार आगाह कर चुके हैं।

ऐसा नहीं है कि झूठ हमारी राजनीति में इससे पहले नहीं था। यह हमेशा से रहा है और सोशल मीडिया के आगमन के बाद पिछले एक दशक में फेक न्यूज के रूप में इसने बहुत उथल-पुथल मचाई है। इसने तनाव पैदा किए हैं, दंगे करवाए हैं और यह मॉब लिंचिंग का कारण भी बनी है। इसने अतीत की महान हस्तियों पर कीचड़ उछाला है, प्रतिष्ठित महिलाओं का चरित्र हनन किया है और तमाम तरह के झूठे इतिहास लोगों के दिमागों में ठूंस दिए हैं। फेक न्यूज के इन तौर-तरीकों ने हमारे चुनावों के नैरेटिव बदल डाले हैं। मगर एआई इससे कहीं आगे की चीज है।

फेक न्यूज के झूठ की देर-सबेर कलई खुल ही जाती थी, लेकिन एआई के झूठ से पार पाना शायद इतना आसान नहीं होगा। एआई झूठ को तैयार करने, परोसने का काम इतनी कुशलता से कर सकती है कि किसी को भी इस पर संदेह न हो सके। एआई की कुशलता इतनी ज्यादा है कि वह एक ही झूठ अलग-अलग तरह के लोगों के सामने अलग-अलग तरीके से पेश कर सकती है। सोशल मीडिया के फेक न्यूज वाले जमाने में हमने देखा है कि किस तरह फोटोशॉप के जरिये तस्वीरों से छेड़छाड़ करके उनको मनमाफिक फसाने में बदला जाता है। हालांकि, फोटोशॉप से इसे अंजाम देने के लिए जो कौशल चाहिए, वह हर किसी के पास नहीं होता। एआई में ऐसे कौशल की जरूरत भी खत्म हो गई है। ऐसी बहुत सी वेबसाइट हैं, जहां आपको सिर्फ यह लिखना है कि आप तस्वीर में क्या चाहते हैं और कुछ ही सेकंडों में आपको तस्वीर तैयार मिल जाती है।

एआई का चुनावी सिरदर्द सिर्फ सफेद झूठ तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ चुनावों में हमने देखा है कि किस तरह से बिग डाटा का इस्तेमाल चुनावी रणनीति को तैयार करने और विरोधी को परास्त करने के लिए किया जाता रहा है। इसके आगे बिग डाटा से मतदाताओं की सोच बदलने की कोशिश भी की जाती रही है। एआई इन सारे कामों को ज्यादा कुशलता से अंजाम दे सकती है। साल 2023 में अमेरिकी सीनेट की एक सुनवाई के दौरान ओपेन एआई नाम की कंपनी के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने क्लॉगर नामक एक मशीन की अवधारणा दी थी। ऑल्टमैन का कहना था कि चुनाव के दौरान यह सुपर एआई मशीन किसी के भी जीतने की संभावनाओं को अधिकतम कर सकती है।

हमें पता नहीं कि ऐसी कोई मशीन है या नहीं? कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है या नहीं? यदि कोई इस्तेमाल कर भी रहा होगा, तो वह इसे गोपनीय ही रखेगा। यह तय है कि एक बार चुनावों में एआई का इस्तेमाल इतने बड़े पैमाने पर शुरू हो गया, तो कुछ समय बाद इसका इस्तेमाल सब दल करने लगेंगे। यानी, एक वक्त ऐसा आएगा, जब मशीनें ही मशीनों के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। क्या हम अपने लोकतंत्र का भविष्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाली मशीनों के हवाले करने को तैयार हैं?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

सब्र, नेक अमल, इंसानियत यानी रोजा और रमजान

यहां स्कैन करें

अजहर हाशमी | साहित्यकार व सूफी विचारक

मजहब-ए-इस्लाम में पवित्र रमजान के महीने का आला मुकाम है। इसे यूं समझिए कि अगर साल के बारहों महीने की 'मेरिट लिस्ट' बनाई जाए, तो पवित्र रमजान का महीना 'टॉपर' है, नंबर वन। इसकी वजह यह है कि रमजान के मुबारक माह में ही इस्लाम धर्म की पाकीजा किताब *कुरआन* का नुजूल (अवतरण) हुआ। पवित्र *कुरआन* की कई आयतों में 'स्याम' अर्थात रोजा और 'शहरे-रमजान' यानी संयम का जिक्र है। रोजा ईमान की रोशनी है, क्योंकि यह सब्र और संयम का पैगाम देता है। यह भूख, प्यास और शहवत (वासनाओं) पर नियंत्रण का नाम है। सब्र की सड़क पर संयम का मुसाफिर है रोजेदार, जिसकी मंजिल है, अल्लाह की इबादत। इबादत में दिखावा नहीं होना चाहिए। बुराइयों से दूर रहकर रखा हुआ रोजा दरअसल ऐसा चिराग है, जिसमें अल्लाह की इबादत की लौ से ईमान की रोशनी फैलती है।

ईमान की यह रोशनी तभी फैलेगी, जब बंदा नेकी पर रहे। नेकी की नाव है रोजा। नेक अमल नाव की पतवार है। इसका खेवनहार है रोजेदार। नाव तभी किनारे पर पहुंच सकती है, जब पतवार मजबूत हो और खेवनहार में काबिलियत हो, और ताकत भी। खेवनहार की काबिलियत से मतलब है कि उसे दिशा का ज्ञान हो, वह हवा का रुख पहचानता हो और मौसम का मिजाज समझता हो। जबकि, ताकत का मतलब है कि वह गुणों की ताकत रखता हो और सेहत की ताकत भी। हां, इसमें अल्लाह की मेहरबानी की भी दरकार होती है। मगर अल्लाह भी उन्हीं की मदद करता है, जो अपनी मदद आप करते हैं। खुलासा यह है कि रोजा रूपी नेकी की नाव को नेक अमल की पतवार से खेने के लिए रोजेदार में दूरंदेशी की काबिलियत हो, यानी आखिरत (मृत्यु के बाद का भविष्य) की फिक्र हो और नेक नीयत, नेक चलन, नेक सिफत, नेक कोशिश, यानी गुणों की ताकत हो। गुस्से, लालच, बेईमानी से बचकर अल्लाह की इबादत करना ही सच्चा रोजा है। हजरत मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का इरशाद है कि रोजा नेकी का पैगाम है। पवित्र *कुरआन* की दूसरी सूरह की आयत नंबर-195 में जिक्र है- बेशक, अल्लाह नेकी करने वालों को दोस्त रखता है।

बुराइयों से दूर रहकर रखा हुआ रोजा दरअसल वह चिराग है, जिसमें अल्लाह की इबादत की लौ से ईमान की रोशनी फैलती है।

नेकी करने से तात्पर्य है, सब्र करना और रहम करना। पवित्र *कुरआन* में पच्चीसवें पारे (अध्याय 25) की 42वीं सूरह की आयत नंबर- 43 में जिक्र है- जो लोग सब्र करते हैं और रहम करते हैं, बहुत ही अजमत वाले हैं। अभिप्राय यह है कि नेकी वाले कार्य करना रोजा-रमजान की पहचान है। कलह-क्लेश से दूर रहना भी इसी में आता है। कलह-क्लेश से तभी दूर रह सकेंगे, जब शांति का माहौल हो। यह माहौल तभी आ सकता है, जब हिंसा न हो। रोजा और रमजान इस प्रकार शांति का संदेशवाहक है। एक वाक्य में यह कि देशों को युद्ध करने से बचना चाहिए। चूंकि रोजा और रमजान इंसानियत का पैगाम देते हैं, यह इंसानियत रमजान के रूप में युद्ध नहीं करने में है।

रोजा और रमजान के बारे में यह भी जानना प्रासंगिक है कि जैसे छाता बारिश से हिफाजत करता है, साफा/पगड़ी आदि तेज धूप से बचाता है, स्वेटर/ शॉल/ कंबल सर्दी से रक्षा करता है, ठीक वैसे ही रोजा रोजेदार की हिफाजत करता है। शर्त यह है कि रोजा सलीके और तरीके से रखा जाए। रोजे का सलीका है, सब्र, संयम व सदाचार। और रोजे का तरीका है, तौहीद, ईमानदारी और मधुर व्यवहार। रोजा अल्लाह से रोजेदार की मगफिरत (मोक्ष) के लिए सिफारिश भी करता है।

कुल मिलाकर, खयाल और अमल की पाकीजगी का पैगाम है रोजा। खयाल का मतलब है विचार। अमल के मायने हैं कार्य। जो शख्स रोजा रखता है, उसके जिस्म, दिल, दिमाग, बातचीत और अमल में पाकीजगी (पवित्रता) होनी चाहिए। रोजेदार अगर नीयत में खोट रखता है, वादा करके मुकरता है, मां-बाप और बुजुर्गों की बेअदबी करता है, महिलाओं को बुरी नजर से देखता है, परिंदों-बेजुबान जानवरों को सताता है, अमानत में खयानत करता है, तो ऐसे तमाम कार्य उसे नापाक बनाते हैं, जबकि रोजेदार के लिए पाकीजगी शर्त है। 'मुस्लिम शरीफ' की हदीस है- हजरत मोहम्मद (सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम) का इरशाद है कि जो शख्स रोजा रखकर भी अपने जाहिर और बातिन को रोजेदार न बनाए, तो अल्लाह को उसकी परवाह नहीं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

मनुष्य होने की गरिमा

महादेव का प्रतीक भारतीय मनीषियों की एक अनूठी खोज है, जिसमें पूरा अंतर-विज्ञान समाया हुआ है, पर महादेव की बाह्य प्रतिमा की ही पूजा-अर्चना की जाती है, उनके गहरे रहस्यों को समझना सामान्य लोगों के बस में नहीं है। अभी-अभी महाशिवरात्रि गुजरी है। इस दिन लोग उपवास करते हैं, शिव जी की आरती उतारते हैं। यह प्रतीक बहुत ही वैज्ञानिक है। विज्ञान की भाषा में शिव एक मूल शक्ति हैं, जो विश्व को चलाती है। शिव हैं संहार की ऊर्जा। इसीलिए उनकी प्रतिमा के जो पहलू हैं, वे बड़े विचित्र बनाए गए हैं।

सबसे बेबूझ हैं उनकी तीन आंखें। शांडिल्य ऋषि ने भक्ति सूत्र में तीन आंखों का रहस्य खोला है। उनके सूत्रों पर बोलते हुए ओशो ने कहा, 'महादेव के तीन नेत्र तुम्हारी ही कहानी है। वह प्रत्येक व्यक्ति की कहानी है। तुम्हें पता नहीं कि तुम महादेव हो। तुम्हें ज्ञात नहीं कि तुम्हारे भीतर भगवान विराजमान हैं। वे तीन आंखें क्या हैं? शांडिल्य ऋषि कहते हैं कि 'वे तीन आंखें हैं-शब्द, लिंग और अक्ष।' ये तीनों बातें समझने जैसी हैं। शब्द का अर्थ होता है : शास्त्र, शास्ता। दूसरे से जो मिले, वह शब्द। शब्द 'पर' से आता है। स्वभावतः खोज 'पर' से शुरू होती है। तुमने पढ़ी *गीता* और तुम्हारे भीतर एक उमंग आई; तुमने सुना किसी को *कुरान* की आयतों को दोहराते हुए और तुम्हारे भीतर कोई तरंग उठी।

दूसरी आंख है- लिंग। लिंग का अर्थ होता है : अनुमान, विचार, मनन, चिंतन। पहली आंख 'पर' से उपलब्ध होती है, दूसरी आंख 'स्व' से। सुना दूसरे से, मगर सुनने से क्या होगा? गुनोगे, तो कुछ होगा। मनन करोगे, तो कुछ होगा। चिंतन करोगे, तो कुछ होगा। पहली से दूसरी बात ज्यादा गहरी जाएगी, क्योंकि पहली बात दूसरे से आई थी, दूसरी बात तुम्हारे निज की प्रक्रिया होगी, आत्म-चिंतन पैदा होगा।

फिर तीसरा है, अक्ष। अक्ष यानी प्रत्यक्ष; साक्षात्कार, अनुभव, सिद्धि। सिद्धि 'स्व' और 'पर', दोनों से मुक्त है। वहां न तो मैं बचता, न तू बचता। वहां सिर्फ परमात्मा बचता है। तो ये तीन आंखें हैं। एक आंख, जो सद्गुरु से मिलती है। कहो, श्रवण से मिलती है। दूसरी आंख, जो मनन से मिलती है, स्वयं से मिलती है। और तीसरी आंख, जो निदिध्यासन, ध्यान से मिलती है। इनमें योग के तीन सूत्र पूरे हो जाते हैं- श्रवण, मनन, निदिध्यासन!'

शिव एक संभावना हैं हरेक मनुष्य की। वह मनुष्य ही है, जो विकास की सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने भीतर छिपे हुए शिवत्व को उपलब्ध हो सकता है। मनुष्य की इससे अधिक गरिमा क्या हो सकती है?

तो महादेव की पूजा करने के साथ-साथ महादेव होने की कोशिश करना ही शिवरात्रि मनाना है। महादेव जैसा कोई व्यक्ति आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा। वह एक संभावना हैं हर मनुष्य की। वह मनुष्य ही है, जो विकास की सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने भीतर छिपे हुए शिवत्व को उपलब्ध हो सकता है। मनुष्य की इससे अधिक गरिमा क्या हो सकती है?

अमृत साधना

एंटोनियो गुटेरस | संयुक्त राष्ट्र महासचिव

गाजा के युद्ध पीड़ित परिवारों के सदस्यों ने आज जो तफसील सुनाई, उसने मुझे बुरी तरह झकझोर दिया है। इनमें से कुछ ने तो अपने सौ से अधिक रिश्तेदारों और दोस्तों को खो दिया है। यह आतंक अब रुकना चाहिए।

सरकार के प्रयासों का दिखता असर

भारत में उसे गरीब माना जाता है, जो भोजन, आश्रय, कपड़े, शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों से जूझता रहता है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि आजादी के साढ़े सात दशक के बाद भी देश में गरीबी है और माना जाता है कि कुल आबादी का करीब ढाई फीसदी हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहा है। मगर इस सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि भारत गरीबी उन्मूलन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऐसे तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, जिनसे लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है। इसका सुखद नतीजा भी निकला है। जैसे, साल 2022 में जहां 4.69 करोड़ भारतीय आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रही थी, वह अब नवीनतम आंकड़ों के अनुसार घटकर 3.44 करोड़ हो गई है। कहा तो यह भी जाता है कि पिछले दस वर्ष में शासन की नीतियों के चलते 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं।

दरअसल, अपने देश में गरीबी के बने रहने की कई वजहें हैं। सबसे बड़ा कारण तो बढ़ती जनसंख्या है। इस वजह से संसाधनों को उचित बंटवारा नहीं हो पाता है और सामाजिक व आर्थिक असमानता में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा, औद्योगिकीकरण अब भी शहरों तक सिमटा हुआ है। इसका विस्तार अगर ग्रामीण भारत तक हो, तो गांवों में विकास की गंगा तो बहेगी ही, गरीबी कम करने में भी मदद मिलेगी, जिसका बड़ा लाभ हमारे देश को होगा। अनियोजित शहरीकरण को भी गरीबी की एक बड़ी वजह मान सकते हैं। जलवायु परिवर्तन, जनहितकारी योजनाओं का लक्षित तबकों तक पूरी तरह न पहुंच पाना, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आदि भी गरीबी बढ़ाने का काम करती हैं। बीमारी, विशेषकर कोरोना ने भी हमें गहरी चोट पहुंचाई है। माना जाता है कि कोरोना के कारण एक बड़ी आबादी फिर से गरीबी रेखा के नीचे चली गई है, जबकि शासकीय नीतियों और योजनाओं के कारण वह इस रेखा से बाहर निकलने में सफल हुई थी।

स्पष्ट है, सरकार की नीतियों का काफी फायदा हुआ है। इसके कारण गरीबों की स्थिति में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। गरीबी उन्मूलन के लिए चलाई जा रही योजनाएं काम कर रही हैं। खेती-किसानी पर ध्यान देने, नई तकनीकों को आत्मसात करने, नौकरियों के अवसर बढ़ाने जैसे अन्य उपायों से भी गरीबी कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसका फायदा समाज के वंचित तबकों को हो रहा है। उम्मीद है कि सरकार अपने इन प्रयासों को आगे भी जारी रखेगी, ताकि भारत में गरीबी उन्मूलन की संकल्पना साकार हो सके।

सुमन सिंह, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

गरीबी उन्मूलन

करोड़ों लोग अब भी वंचितों में शामिल

महज हफ्ते भर पहले अमेरिकी थिंक टैंक ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट में बताया गया कि हमारे देश में गरीबी कम हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की असमानता भी कम हुई है। यह हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन गरीबी उन्मूलन की दिशा में अब भी काफी काम किए जाने की जरूरत है। हमको यह भी सोचना होगा कि सरकारें गरीबी उन्मूलन के लिए भरसक प्रयास करती हैं, कई तरह की योजनाएं भी अमल में लाती हैं, फिर भी देश में करोड़ों लोग गरीबी की खाई में क्यों पड़े हैं?

अगर देश में निष्पक्ष और उचित सर्वेक्षण करवाया जाए, तो ऐसे लाखों-करोड़ों गरीब बच्चे मिल जाएंगे, जिन्हें दो वक्त की रोटी तक नहीं मिल पाती। सरकारी योजनाओं का हाल यह है कि वे अमूमन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं या फिर फाइलों में सिमटकर रह जाती हैं। अगर सही मंशा से काम हो, तो भारत में गरीबी उन्मूलन में समय नहीं लगेगा, लेकिन यहां मुफ्त की योजनाओं या रेवड़ी संस्कृति को बढ़ावा देकर गरीबी दूर करने के उपाय किए जाते हैं, जिनका कोई खास असर नहीं होता। उल्टे, इससे देश के खजाने को नुकसान हो सकता है, हम कर्जदार बन सकते हैं और विकास का पहिया थम सकता है। रेवड़ी संस्कृति का एक नुकसान यह भी है कि लोग इस 'अतिरिक्त कमाई' के चक्कर में ज्यादा बच्चे पैदा करने लगते हैं। इससे उनकी कितनी कमाई बढ़ती है, यह तो हमें नहीं पता, लेकिन आबादी का बोझ देश को जरूर उठाना पड़ता है, जिससे प्रति व्यक्ति आय में कमी आ जाती है।

अगर भारत में गरीबी उन्मूलन को संभव बनाना है, तो हमें कुछ काम जरूर करने चाहिए। मिसाल के तौर पर, देश में बढ़ती जनसंख्या को थामने का गंभीर प्रयास करना होगा, ताकि संसाधनों पर दबाव न पड़े। इसके अलावा, मुफ्तखोरी या रेवड़ी संस्कृति पर अंकुश लगाना होगा, ताकि लोग काम करने को लेकर प्रेरित हों। हमें रोजगार के अवसर भी बढ़ाने होंगे। हर हाथ को यदि काम मिलेगा, तो परिवार की आमदनी बढ़ेगी, जिससे देश में समृद्धि आएगी। 1950 के दशक में जब पहली पंचवर्षीय योजना को हरी झंडी दी गई थी, तब विनोबा भावे ने कहा था कि सरकार की सभी राष्ट्रीय योजनाओं का मकसद रोजगार बढ़ाना भी होना चाहिए। जाहिर है, समग्र प्रयास की जरूरत है। अगर ऐसा हो सका, तो भारत में गरीबी उन्मूलन संभव है। अन्यथा, देश में गरीबों की दुर्दशा से कहां कोई अनजान है!

राजेश कुमार चौहान, टिप्पणीकार

https://t.me/AllNewsPaperPaid

नैतिक मूल्यों से विमुख जीवन का कोई औचित्य नहीं

कांग्रेस को एक और आघात

तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने बंगाल की सभी 42 सीटों से जिस तरह अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए और उनकी परेड भी करा दी, वह कांग्रेस और विपक्षी दलों के मोर्चे आइएनडीआइए के लिए एक और झटका है। इसके पहले वाम दलों ने केरल में कांग्रेस को ऐसा ही झटका दिया था। वाम दलों ने तो राहुल गांधी की वायनाड सीट से भी यह कहकर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था कि यदि उन्हें भाजपा का मुकाबला करना है तो वह उत्तर भारत जाकर चुनाव लड़ें। वाम दल बंगाल में तो कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन केरल में इसके लिए तैयार नहीं। बंगाल में वाम दलों की ऐसी हैसियत नहीं कि वे कांग्रेस की कोई बहुत अधिक मदद कर सकें। ममता ने अपने सभी प्रत्याशियों के नाम जारी कर भले ही आइएनडीआइए से अलग होने की घोषणा न की हो, लेकिन बंगाल में अब इस गठजोड़ का कोई महत्व नहीं रह गया है। कांग्रेस का अभी तक उत्तर प्रदेश में सपा और दिल्ली के साथ कुछ और राज्यों की चुनिंदा सीटों पर आम आदमी पार्टी से ही सीटों का तालमेल हो सका है। इन राज्यों में पंजाब नहीं, जहां आम आदमी पार्टी मजबूत है। जम्मू-कश्मीर में भी यह गठबंधन बिखर गया। यह ठीक है कि तमिलनाडु, झारखंड, बिहार आदि में कांग्रेस सहयोगी दलों से मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन ये दल पहले से ही उसके साथ रहे हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना से तालमेल बने रहने के आसार तो दिख रहे हैं, लेकिन वहां सीटों के बंटवारे को लेकर तनातनी बढ़ती जा रही है। पिछले वर्ष जुलाई में जब आइएनडीआइए का गठन हुआ था तो यह लगा था कि भाजपा को चुनौती देने वाले एक मजबूत गठजोड़ ने आकार ले लिया है, लेकिन कांग्रेस की सुस्ती और सहयोगी दलों के अपनी राजनीतिक जमीन न छोड़ने वाले रवैये के चलते वह आगे नहीं बढ़ सका। वह तब कमजोर और बिखरा हुआ दिखने लगा, जब पहले नीतीश कुमार और फिर जयन्त चौधरी ने उसका साथ छोड़ दिया। इसमें संदेह नहीं कि वाम दलों और तृणमूल कांग्रेस ने इस गठबंधन को और कमजोर करने एवं कांग्रेस की समस्या बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के समक्ष एक संकट यह भी है कि उसके नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला कायम है। इससे अच्छा संदेश नहीं जा रहा है, क्योंकि ऐसे अधिकांश नेता भाजपा में जा रहे हैं। कांग्रेस के साथ आइएनडीआइए के कमजोर दिखने के लिए एक बड़ी हद तक उसके रणनीतिकार ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने अपने गठबंधन को मजबूती देने और सहयोगी दलों से सामंजस्य बैठाने के लिए वैसे जतन नहीं किए, जैसे आवश्यक थे। कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति को धार देने के बजाय राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने पर अधिक ध्यान दिया और उसमें भी सहयोगी दलों को निमंत्रित नहीं किया।

जरूरी पहल

स्वच्छता सर्वेक्षण में भले ही प्रदेश के प्रमुख शहरों को सम्मानजनक रैंक नहीं मिली हो, लेकिन साल दर साल रैंकिंग में सुधार हो रहा है। पटना नगर निगम को गार्बेज फ्री सिटी का दर्जा मिला है। प्रदेश के अन्य शहरों जैसे भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया की रैंकिंग में भी सुधार हो रहा है। इसी कड़ी में निर्णय लिया गया कि राज्य के शहरों की सफाई व्यवस्था बेहतर करने के लिए अब वरीय अधिकारी खुद सड़कों पर उतरेंगे। सभी नगर आयुक्तों और कार्यपालक पदाधिकारियों को प्रतिदिन एक बार फील्ड विजिट करने का निर्देश दिया गया है, ताकि वह सफाई कार्यों का जायजा ले सकें। राज्य स्तर पर प्रत्येक सप्ताह वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सफाई कार्यों की समीक्षा होगी। हर सप्ताह स्वच्छता कार्य का मूल्यांकन होगा। पदाधिकारियों के बीच वार्डवार जिम्मेदारी बांटी जाएगी। अच्छा करने वाले पदाधिकारियों व कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार मिलने से स्वच्छता को लेकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धी माहौल बनेगा। सबसे महत्वपूर्ण निर्देश यह दिया गया कि शहरी निकायों में अगर कोई भी कूड़ा केंद्र है, तो इसके लिए 15 दिनों का अभियान चलाकर उसे समाप्त कराया जाएगा। यह बहुत जरूरी है। राजधानी पटना में काफी हद तक कूड़ा प्वाइंट को मुक्त करा लिया गया है। इसके साथ जहां पर सब्जी मंडी लगती है या खाद्य पदार्थों के ठेले लगते हैं, वहां डस्टबिन रखे जाएंगे और प्रतिदिन कूड़ा उठाव होगा। अपने शहर और आसपास के इलाके को स्वच्छ रखने में सरकार, विभाग के साथ आमजन की महती भूमिका होती है। विभाग की ओर से दिए गए निर्देश व निर्णय का यदि अनुपालन पूरी तरह हो जाएगा तो निश्चित रूप से शहरों को स्वच्छ बनाने का संकल्प साकार हो जाएगा।

शहरों में स्वच्छता अभियान के तहत दिए निर्देशों की निष्पक्ष मानीटरिंग होगी तो हर हाल में सुखद परिणाम अवश्य मिलेंगे।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या रसोई गैस सिलेंडर के बाद पेट्रोल-डीजल के दाम भी घटाए जाने चाहिए?

आज का सवाल

तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची आइएनडीआइए और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है?

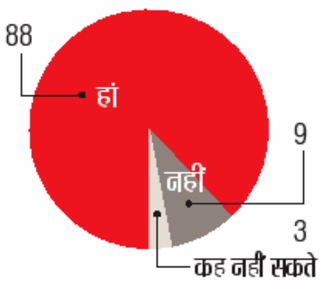

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती

हृदयनारायण दीक्षित

द्रमुक नेता ए. राजा ने जैसे बयान दिए, वैसे शूल की तरह चुभते हैं। उच्चतम न्यायालय को ऐसे बयानों का स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करनी चाहिए

राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती असहनीय अपराध है। यह संविधान का भी उल्लंघन है। यह सब जानते हुए भी द्रमुक सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए. राजा ने राष्ट्रीय संप्रभुता पर हमला किया है। उन्होंने भारत माता के प्रति श्रद्धा को भी चुनौती दी है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम को अपशब्द कहे हैं। भारत के अस्तित्व से इन्कार किया कि भारत राष्ट्र ही नहीं है। यह एक उपमहाद्वीप है। इसके भीतर तमिल और मलयालम जैसे देश हैं। इसके पहले द्रमुक नेता उदयनिधि ने सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया आदि कहा था। राजा के बोल पहली बार नहीं बिगड़े। उदयनिधि वाले विवाद के बीच उन्होंने सनातन धर्म की तुलना एचआइवी और कुष्ठ जैसी बीमारियों से की। उन्होंने तमिलनाडु को अलग देश बनाने के लिए आंदोलन की धमकी दी थी। राष्ट्र और संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाने, श्रीराम और भारत माता को अपमानित करने जैसे कृत्य संविधान का अपमान है। संविधान की मूल प्रति में श्रीराम का चित्र है। श्रीराम के प्रति श्रद्धा काल्पनिक नहीं है। यह सांस्कृतिक है और संवैधानिक भी है। उन्होंने सांसद के रूप में ली गई शपथ का उल्लंघन किया है। राष्ट्र क्षुब्ध है।

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी विख्यात पुस्तक 'डिस्कवरी आफ इंडिया' में 'भारत माता' के संदर्भ में लिखा है-मैं सभाओं में जाता हूं। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। भीड़ 'भारत माता की जय' बोलती है। मैं पूछता हूं, यह 'भारत माता' कौन हैं?' एक व्यक्ति कहता है, 'यह भारत की पवित्र धरती।' मैं कहता हूं, 'आप ठीक सोचते हैं। यही भारत माता हैं, किंतु भारत माता इससे भी ज्यादा हैं। ये पर्वत, नदियां, वन, हम, आप, सब भारत माता हैं।' पंडित नेहरू से लेकर नरेन्द्र मोदी तक पूरा देश भारत माता के प्रति श्रद्धालु है। इन्हीं भारत माता की आराधना राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' में की गई है। देश की धरती को माता कहना वैदिक काल से भी पुराना है। वंदे मातरम् स्वाधीनता संग्राम में राष्ट्र जागरण का बीज मंत्र रहा है। ए. राजा की तरह मुस्लिम लीग ने भी भारत माता का विरोध किया। संविधान के मूल कर्तव्यों के अनुसार, 'संविधान और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करें। आगे लिखा है कि, 'राष्ट्रीय संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें।' जबकि यहां संप्रभुता और अखंडता को ही दुत्कारा जा रहा है।

भारत के भीतर कई देश नहीं हैं। भारत अमेरिक जैसा नहीं, जो राज्यों के परस्पर अनुबंध से अस्तित्व में आया था। भारत राज्यों के समझौते का परिणाम भी नहीं है। राज्य भारतीय संविधान का परिणाम हैं।

अवधेश राजपूत

राष्ट्र राज्य राज्यों के आकार में परिवर्तन के लिए अधिकृत है। यहां का संघीय ढांचा अमेरिकी संघीय ढांचे से भिन्न है। राज्यों को देश कहना संविधान का उल्लंघन है, मगर ए. राजा राज्यों को राष्ट्र बता रहे हैं। स्वाधीनता संग्राम और उसके बाद भी कुछ वामपंथी तत्वों ने भारत को राष्ट्र नहीं माना। कुछ लिबरल तत्वों ने राष्ट्र बनाने का श्रेय अंग्रेजों को दिया था। गांधी जी ने प्रतिवाद में कहा, 'भारत अंग्रेजी सत्ता के पहले भी राष्ट्र था।' ऋग्वेद में सप्तसिंधु का उल्लेख है। मैकडनल और कीथ ने भी इस भूभाग को देश बताया है। पुसालकर ने भी नदी नामों के आधार पर प्राचीन देश की रूपरेखा बनाई है। उन्होंने अफगानिस्तान, पंजाब, अंशतः सिंध, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश सिंध और कश्मीर एवं सरयू तक का पूर्वी भारत इस देश में शामिल बताया है। भारत एक विशेष संस्कृति के कारण एक राष्ट्र था और है। यह दुनिया का प्राचीनतम राष्ट्र है।

भाषा और संस्कृति की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने संतोष बनाम मानव संसाधन मंत्रालय (1994) मामले में स्पष्ट किया कि सामासिक संस्कृति का आधार संस्कृत भाषा और साहित्य है। न्यायालय की टिप्पणी है, 'यद्यपि इस देश के लोगों में अनेक भिन्नताएं हैं। वे गर्व करते हैं कि वे एक सामान्य विरासत के सहभागी हैं। वह विरासत संस्कृत की है।' उल्लेखनीय है कि संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राजभाषा बनाया था। गांधी जी गुजराती और अंग्रेजी के जानकार थे। उन्होंने लिखा है कि, 'मेरी हिंदी कमजोर है, लेकिन मैं हिंदी को राजभाषा बनाने का समर्थक हूं।' तमिल, मलयालम, उड़िया आदि भाषाएं भारत का गौरव हैं। सभी भारतीय भाषाओं में संप्रेषण की शक्ति है। भाषा को लेकर विवाद नहीं होने चाहिए, लेकिन ए. राजा ने सारी हदें तोड़ दी हैं। राजा के बयान के एक दिन पहले ही सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि को अनुचित बयानों के लिए फटकार लगाई थी। इस लिहाज से ए. राजा ने कोर्ट का भी अपमान किया।

सनातन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। सत्य सनातन है। ब्रह्मांड सनातन है। प्राकृतिक नियम सनातन हैं। सनातनता शाश्वत गुण है। जिस तत्व पर समय का प्रभाव पड़ता है वह शाश्वत नहीं है और सनातन भी नहीं। उसमें सुधार की संभावनाएं बनी रहती हैं। सत्य और शिव पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। भारतीय समाज के उत्कृष्ट तत्व सनातन निरंतरता से आए हैं, लेकिन रोग पुराना है। तमिलनाडु के रामास्वामी नायकर ने द्रमुक की स्थापना की। रामास्वामी से लोहिया की मुलाकात हुई। लोहिया ने उनसे राष्ट्र विरोधी रुझानों को छोड़ने की बात कही। लोहिया ने कहा, 'वह शूद्रों और गरीबों के हित में आंदोलन के समर्थक हैं, लेकिन वे उत्तर भारत का विरोध, द्रविड़ स्थान की मांग, हिंदी विरोध, गांधी जी की तस्वीर जलाना एवं ब्राह्मणों के प्रति हिंसा का त्याग करें।' भाषा के बारे में लोहिया ने कहा कि मैं उनसे तमिल में बोलूं और वह मुझे हिंदी में जवाब दें। इन सब बातों का कोई लाभ नहीं हुआ।

लोकसभा चुनाव आसन्न हैं। कांग्रेस सहित कई दलों ने आइएनडीआइए नाम का मोर्चा बनाया है। कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह राजा के बयानों के साथ है? क्या वह सनातन के विरुद्ध है? क्या वह राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रुभता को चुनौती देने वाले राजा के साथ है? इस स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है। वैसे राहुल गांधी ने भी कुछ समय पहले राजा की ही तर्ज पर भारत को देश नहीं, बल्कि 'राज्यों का संघ' बताया था। ऐसे बयान शूल की तरह चुभते हैं। उच्चतम न्यायालय इस मामले का स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करे तो स्वागतयोग्य होगा।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

शिक्षा नीति में है पर्चा लीक का समाधान

जगमोहन सिंह राजपूत

शिक्षा व्यवस्था में बढ़ रहीं भ्रष्ट प्रवृत्तियां व्यवस्था की साख को दीमक की तरह नष्ट कर रही हैं

भारत को अपने युवाओं पर गर्व है। सारा विश्व उनकी सृजनात्मकता, बुद्धिमत्ता और प्रतिभा का लोहा मानता है। देश की तकनीकी शिक्षा, प्रबंधन शिक्षा, संचार तकनीकी तथा वैज्ञानिक शोध के संस्थान अनेक देशों के लिए ईर्ष्या के कारण बने हैं। यह सब भारत के भविष्यद्रष्टा नेतृत्व के कारण ही संभव हो सका है। हालांकि कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं, जो देश के लिए अत्यंत चिंताजनक स्थिति निर्मित कर रहे हैं। आज शिक्षा व्यवस्था में असामाजिक तत्व और भ्रष्ट प्रवृत्तियां लगातार बढ़ रही हैं और व्यवस्था की साख को दीमक की तरह नष्ट कर रही हैं। इस पर विमर्श और त्वरित निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक हो गया है। अन्यथा स्थिति हाथ से निकलती जाएगी।

पिछले दिनों हरियाणा के नूंह जिले में परीक्षा में नकल की योजनाबद्ध घटना सामने आई। राजस्थान में भर्ती में पर्चा लीक के एक मामले में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 14 पुलिस कर्मचारियों को मिलाकर 40 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। राजस्थान में 2019 के बाद प्रतिवर्ष तीन पर्चे लीक हुए, जिसमें 40 लाख युवा प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पर्चा लीक के कारण 48 लाख युवाओं का निराश होकर ठगे से रह जाना किसी भी देश के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति ही कही जाएगी। उत्तर प्रदेश की पुलिस नियुक्ति व्यवस्था ने एक झटके में अपनी अक्षमता दिखा दी। इसके बावजूद लाखों युवाओं और परिवारों पर भारी आर्थिक और मानसिक बोझ के लिए जिम्मेदार किसी भी सरकारी अधिकारी के बर्खास्त होने की खबर न उत्तर प्रदेश से आई, न हरियाणा या राजस्थान से। इस अपराध के लिए कितने लोग सजा काट रहे हैं या जेलों में हैं या उनकी संपत्ति जब्त हुई है? इनमें से अनेक तो लगातार नकल और पर्चा लीक में शामिल बताए जा रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 15 राज्यों में पिछले पांच वर्षों के दौरान 1.4 करोड़ युवा पेपर लीक के शिकार हुए हैं। यह चिंताजनक स्थिति है।

परीक्षाओं को कदाचार मुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक माडल अधिनियम बनाया है। राजस्थान सहित कुछ राज्यों ने भी इसके लिए कुछ ऐसा ही रास्ता अपनाया है। समस्या यह है कि किसी को इनके लागू होने के बाद भी स्थिति सुधरने का

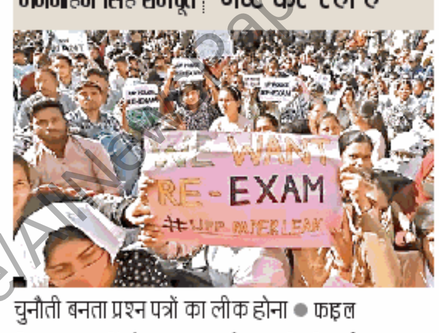

चुनौती बनता प्रश्न पत्रों का लीक होना ● फाइल

विश्वास नहीं है। नकल और पर्चा लीक के प्रकरण साल-दर-साल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सवाल है कि आज तक ऐसी किसी व्यवस्था की आवश्यकता क्यों नहीं समझी गई कि नकल और पर्चा लीक में बर्खास्तगी तुरंत होगी। ऐसे हर प्रकरण के लिए सर्वाधिकार संपन्न विशेष न्यायालय की स्थापना की जाएगी और अपराधियों को दंड छह महीने के अंदर दे दिया जाएगा। आज भी पर्चा लीक में संलग्न अपराधी 'अधिकारी' अपनी जगहों पर विद्यमान हैं, जनता के पैसों पर पल रहे हैं। अगर उनके अधिकार हैं तो जिन युवाओं के साथ धोखा हुआ है, उनके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा?

अपराध की गंभीरता को समझना, देश के भविष्य पर उससे घातक परिणामों की चिंता करना सरकार का ही नहीं, समाज का भी उत्तरदायित्व है। परीक्षा में अपनी जगह किसी अन्य को धनराशि देकर बैठाने की तिकड़म लंबे अर्से से चल रही है। विकास, प्रगति या प्रगतिशीलता का यह कैसा उदाहरण है कि मेडिकल की प्रवेश परीक्षा में कोई डाक्टर ही 'साल्वर' बनकर बैठे और किसी को कोई सजा न मिले। दूसरे के लिए परीक्षा में बैठने वाला और उसे बैठाने वाला परिवार समाज के बराबर के अपराधी हैं। ये ऐसी सजा के अधिकारी हैं, जो वह जीवनपर्यंत भोगें। आज तक परीक्षा का पर्चा खरीदने के लिए धन उपलब्ध कराने वाले किसी पालक को शायद ही कभी कोई कठोर दंड मिला हो? इन सभी समस्याओं के संपूर्ण समाधान का रास्ता राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में नजर आता है। इसमें देश के युवाओं के लिए नई आशा का संचार करने की अनेक संभावनाएं निहित हैं। वह देश की शिक्षा व्यवस्था में नैतिकता ला सकती है। सारे सामाजिक परिदृश्य को बदल सकती है। हालांकि इसके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती इसके सफल क्रियान्वयन और अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने की है।

वर्ष 1968 तथा 1986/92 में बनी शिक्षा नीतियों के क्रियान्वयन के अनुभव यह स्पष्ट इंगित करते हैं कि नीति कितनी भी सशक्त क्यों न हो उसकी सफलता उन व्यक्तियों पर निर्भर करती है, जो हर स्तर पर उसके क्रियान्वयन के उत्तरदायित्व निभाते हैं। नई शिक्षा नीति में 2012 में गठित न्यायमूर्ति जेएस वर्मा आयोग के उस निष्कर्ष को दोहराया गया है कि 'देश में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान अध्यापक शिक्षा के प्रति लेशमात्र भी गंभीरता से प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके स्थान पर ऊंचे दामों पर डिग्रियां बेच रहे हैं।' नोबेल पुरस्कार विजेता गुन्नार मिर्डल ने भी अपनी पुस्तक 'एशियन ड्रामा' में लिखा है कि भारत जैसे सभी विकासशील देशों में हर क्षेत्र में गुणवत्ता-वृद्धि का स्रोत एक ही है-उनके अपने शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता।

यदि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में नैतिकता, संस्कृति बोध, कर्तव्यनिष्ठा, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण, सेवा के प्रति सम्मोहन और कार्यसंस्कृति अनुकरणीय होंगे तो देश के स्कूलों के अध्यापक बनने के लिए प्रशिक्षित हो रहे युवा भी इनको ग्रहण और अनुसरण करेंगे। वे बाद में स्कूलों में वैसी ही कार्यसंस्कृति निर्मित करने में सफल होंगे। यहीं से देश को हर कार्यक्षेत्र में वैसे ही लोग मिलेंगे। यह कोई दूर की कौड़ी नहीं है, केवल राष्ट्र द्वारा निर्णय लेने की देरी है। जापान ने अपने पुनर्निर्माण में प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों पर विश्वास कर देश में कार्यनिष्ठा तथा कार्यसंस्कृति के नए आयाम स्थापित कर दिए। भारत भी इसे अपने ढंग से कर सकता है।

(लेखक शिक्षा, सामाजिक सद्भाव और पंथक समरसता के क्षेत्र में कार्यरत हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

प्रतिबोध

आज हर आदमी सुख की खोज में खड़ा है। ऐसे थके-हारे इंसान को प्रतिबोध देते हुए जाने-माने विद्वान खलील जिब्रान लिखते हैं कि 'मैं भी कहता हूं कि जीवन सचमुच! अंधकारमय है, यदि आकांक्षा न हो। सारी आकांक्षाएं अंधी हैं, यदि ज्ञान न हो। सारा ज्ञान व्यर्थ है, यदि कर्म का ज्ञान न हो। जब आप प्रेम से प्रेरित होकर कर्म करते हैं तब स्वयं से बंधते हैं, एक-दूसरे से बंधते हैं, और फिर भगवान से बंधते हैं।' यहां प्रेम का अर्थ संकल्प है। प्रेम में, ज्ञान में और सौंदर्य में कभी अति नहीं होती, जब ये गुण पूर्ण शुद्ध अर्थ में समझे जाएं। तभी हम वह सब कर सकते हैं, जो हम करना चाहते हैं। आप तभी अच्छे बन सकते हैं यदि आपमें आत्मविश्वास है। दृढ़ निश्चय है। निर्णयन क्षमता है। आशावादी दृष्टिकोण है। सकारात्मक सोच और उत्साही मन है। अगर आप दुख में से सुख खोज लेना चाहते हैं तो सचमुच सुख खोज लेंगे। इसके लिए ऐसा सोचते हुए बस आपको संकल्पित होना होगा। जो स्थिति आपके दिमाग की है, वही आपकी खोज की है। यानी आप जिस चीज की इच्छा करेंगे, वह पा लेंगे।

सोचना यह है कि हम गहरे में जमे अपने संस्कारों को कैसे सुधारें? जड़ तक कैसे पहुंचें? बिना जड़ के सिर्फ फूल-पत्तों का क्या मूल्य? पतझड़ में फूल-पत्ते सभी झड़ जाते हैं, मगर वृक्ष कभी इस वियोग पर शोक नहीं करता। उसके पास जड़ की सत्ता सुरक्षित है, जिससे वसंत आने पर पुनः वृक्ष फूल-पत्तों से लहलहा उठता है। अंधेरा तभी तक डरावना है, जब तक हाथ दीये की बाती तक न पहुंचे। अपने आप को अपना भविष्य निर्माता मानिए और फिर कार्य की शुरुआत कर दीजिए। अपने भविष्य की कल्पना कीजिए। सोचिए कि आज से एक वर्ष बाद, दो वर्ष बाद या पांच वर्ष बाद आप कहां पहुंचना चाहते हैं। जहां आपको मनचाही सफलता और जिंदगी हासिल हो। इसीलिए सुकरात का कथन है कि वैसा जीवन जिसमें परीक्षाएं न ली गई हों, जीने योग्य नहीं है।

ललित गर्ग

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

विकसित भारत में बाधक वंशवाद

गिरीश्वर मिश्र का 'राजवंश सरीखी राजनीति' विषयक आलेख उन राजनीतिक लोभियों को आईना दिखाता है जिन्होंने राजनीति को धन उगाही का साधन और अपना खानदानी पेशा बना दिया है। भारतीय लोकतंत्र में वंशवादी राजनीति के हस्तक्षेप से इसकी जड़ें कमजोर होंगी। इस संदर्भ में प्राचीन राजशास्त्र के मानक ग्रंथों ने प्रभावी लोकतंत्र के लिए बड़ा आदर्श स्थापित कर रखा है। कौटिल्य के अनुसार राजा का काम स्वार्थ साधना और सत्तासुख भोगना नहीं है। वर्तमान परिदृश्य में राजा का स्थान जनप्रतिनिधियों ने ले लिया है जिन्हें आम जनता शासकीय व्यवस्था चलाने का दायित्व देती है। कौटिल्य की बातें इसलिए उन पर प्रासंगिक मानी जाएंगी, क्योंकि वे जनता के हित साधने के लिए जनप्रतिनिधि बनने की बात करते हैं। दुर्भाग्य से आजकल समाज में उन लक्ष्यों की पूर्ति विरले जनप्रतिनिधि ही करने की सोचते हैं। सम्राट अशोक के शिलालेखों में 'सभी मेरे पुत्र हैं' प्रमुखता से अंकित किया गया है। वैदिक राजतंत्र में राजपद के संदर्भ में 'जानराज्य' और 'स्वाराज्य' जैसे शब्दों का प्रयोग प्रमुखता से मिलता है, जो एक राजा के नेतृत्व में प्रजा की स्वतंत्रता और समग्र जनता की सहभागिता को द्योतित करता है। लेखक का यह मंतव्य कि 'आज के राजनेता जनसेवक होने की जगह खुद अपने लिए जनसेवा कराने लगे हैं', जो चिंता का विषय है। यह भारत के परंपरागत सामाजिक दर्शन के एकदम विपरीत है, जो पद का उपयोग-उपभोग शुचिता से करने को प्रेरित करता है। किसी भी सार्वजनिक पद पर बने रहने के लिए यह आवश्यक है कि पदधारी अपने कार्यों के लिए नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करने के साथ उत्तरदायित्व भी स्वीकार करने के लिए तैयार हो। अपरिपक्व राजनीतिक उत्तरदायित्व का दुष्परिणाम बहुत भयानक हो सकता है, जो राष्ट्रीय हितों को अनदेखा करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित धोखाधड़ी जैसी भयानक समस्याओं का कारण बन सकता है। वर्तमान भारतवर्ष जिस दौर से गुजर रहा है वहां उच्च नैतिक आदर्श युक्त अनुभवी लोग ही पद पर अपेक्षित और उपादेय हैं। यह तभी संभव है जब वंशवाद और खानदानी तौर पर राजवंश सरीखी राजनीति से ऊपर उठकर सामाजिक परिवर्तन के लिए कदम उठाए जाएं। पारिवारिक हितों को सर्वोपरि और राष्ट्रहित को पृथक देखने वालों के हाथ में शासन होने से विकसित भारत का लक्ष्य अप्राप्य हो जाएगा।

डा. धनंजय मणि त्रिपाठी, जामिया-मिलिया-इस्लामिया, नई दिल्ली

कम पानी वाले अनाज उपजाएं

संपादकीय आलेख एक उपयोगी योजना (नौ मार्च) पढ़ा। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन देश के अधिकांश किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर पंजाब के किसान एमएसपी की गारंटी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा धान की जगह दाल, मक्का एवं कपास की फसल पर एमएसपी योजना लागू करने का निर्णय स्वागत योग्य है। अब आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है। धान की व्यापक पैमाने पर खेती के कारण पंजाब का भूमिगत जल स्तर गिरता जा रहा है। भूमिगत जल स्तर को बनाए रखने के लिए कम पानी वाले अनाज को उपजाने की आवश्यकता है।

ई हिमांशु शेखर, केसपा, गया

नेताओं व अपराधियों का गठजोड़

'राजनीति के अपराधीकरण की बीमारी' शीर्षक आलेख में संजय गुप्त ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली की घटना में नेताओं व अपराधियों के गठजोड़ की तथ्यात्मक व्याख्या की है। यह स्पष्ट हो गया है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी में बाहुबलियों का जमावड़ा है, जिसके बल पर पार्टी येन-केन प्रकारेण अपनी सरकार चला रही है। इन बाहुबलियों के करतूतों की जानकारी देश को तब होती है, जब पानी सिर से ऊपर पानी बहने लगता है। शाहजहां शेख व अन्य गुर्गों को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक बेनकाब हो चुकी हैं, इससे बदतर स्थिति और क्या हो सकती है? सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस मामले को न्यायपालिका ने संज्ञान ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि टीएमसी सरकार महिलाओं की सुरक्षा करने में विफल है, जबकि भाजपा सरकार ने बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के लिए उम्र कैद की सजा का प्रविधान किया है। महिलाओं की शिकायतों के आसान पंजीकरण के लिए, 'महिला हेल्पलाइन' की व्यवस्था है, लेकिन टीएमसी सरकार इसे पश्चिम बंगाल में संचालित नहीं होने दे रही है। गत दिनों आरोपित शाहजहां शेख की अकड़ तब दिखी, जब वह पुलिस हिरासत में विक्ट्री साइन दिखा रहा था। नरेन्द्र मोदी को संदेशखाली की पांच पीड़ित महिलाओं ने आपबीती भी सुनाई। पीएम मोदी ने कहा कि यह मोदी की गारंटी है कि किसी को छोड़ूंगा नहीं।

युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

X पोस्ट

सब कहते हैं नरेन्द्र मोदी को हराने के लिए सभी विपक्षी दलों को साथ आना होगा, लेकिन कोई नहीं कहता कि मोदी को हराने के लिए मोदी से बेहतर करके दिखाना होगा। मुकेश पाठक @MukeshPathakji

कांग्रेस ने संदेशखाली के मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी और महुआ मोइत्रा का भी पुरजोर समर्थन किया, लेकिन ममता बनर्जी ने बंगाल में कांग्रेस पर कोई ममता नहीं दिखाई। वहां गठबंधन को लेकर कांग्रेस की उम्मीदें तृणमूल की सूची के साथ ही ध्वस्त हो गईं। पल्लवी घोष @_pallavighosh

यदि तृणमूल कांग्रेस ने बंगाली अस्मिता और बंगाली उप-राष्ट्रवाद का मुद्दा छेड़ा तो गुजराती यूसुफ पठान और बिहारी शत्रुघ्न सिन्हा के अलावा कीर्ति आजाद को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उस रणनीति को धार देना अब मुश्किल होगा। शीला भट्ट @sheela2010

झीलों के शहर बेंगलुरु में भूजल सूख गया है। पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद, सूरत, इंदौर, दिल्ली आदि सारे बड़े और मझोले शहरों का यही हाल है। नदियों को पीकर गंदे नालों में बदलने वाले शहर न एक बूंद पैदा करते हैं न जमा। फिर पानी आएगा कहां से? जब तक पानी जमा और रिसाइकल नहीं करेंगे, तब तक स्थितियां सुधरेंगी नहीं। शिव कांत @shivkant

जनपथ

गठबंधन 'इंडी' गजब रहा आज फल फूल,
बना रहे हैं लोग सब इक-दूजे को 'फूल'।
इक-दूजे को 'फूल' उमर-महबूबा भिड़ते,
ममता संग अधीर जुबानी कुश्ती लड़ते।
उद्धव जी का कांड और निरुपम का क्रंदन,
ऐसे ही फल फूल रहा 'इंडी' गठबंधन!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प.बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073

E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 24 अंक 327

****

यदि आप दूसरों से ताकतवर हैं, तो आपको दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए। - सरोजिनी नायडू

भारत और ईएफटीए देशों के बीच हुआ समझौता इसलिए ऐतिहासिक है कि मुक्त व्यापार समझौतों के इतिहास में संभवत: यह पहली बार है कि इसके लक्ष्यों को लेकर बाध्यकारी प्रतिबद्धता जताई गई है। उम्मीद है कि इससे दूसरे देशों के साथ विचाराधीन एफटीए का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

ऐतिहासिक समझौता

भारत का यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) भले ही अब तक अंतिम रूप न ले पाया हो, लेकिन चार यूरोपीय देशों के अंतर-सरकारी संगठन ईएफटीए के साथ निवेश और वस्तुओं व सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हुआ एफटीए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। वर्तमान समझौता, जिसे व्यापार एवं आर्थिक सहयोग समझौता (टीईपीए) कहा गया है, दोनों पक्षों के बीच करीब 16 वर्षों की बातचीत के बाद संभव हुआ है, जिससे इसके महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह इसलिए भी ऐतिहासिक है कि मुक्त व्यापार समझौतों के इतिहास में यह संभवतः पहली बार है कि इसके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बाध्यकारी प्रतिबद्धता जताई गई है। उल्लेखनीय है कि भारत और ईएफटीए, जिसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन शामिल हैं, पारस्परिक आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए 2008 से ही इस समझौते की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। 14 अध्यायों वाले इस समझौते से ईएफटीए देशों को भारत के रूप में एक बड़े बाजार तक पहुंच मिलेगी, वहीं भारत के प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों को भी अंतरराष्ट्रीय बाजार मिलेगा। समझौते का सबसे बड़ा फायदा भारत को यह होगा कि इसके तहत ईएफटीए देश समझौते के क्रियान्वयन के बाद अगले दस साल में भारत में 50 अरब डॉलर और फिर उसके अगले पांच साल में 50 अरब डॉलर का निवेश करेंगे और इन निवेशों के जरिये भारत में दस लाख नौकरियां पैदा करेंगे। समझौते में सेवाओं व निवेश को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों को आसान बनाने और सीमा शुल्क को काफी कम रखने या खत्म करने की बात भी शामिल है। हालांकि चारों देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों में सीमा शुल्क पहले से ही शून्य या काफी कम है। इसके अलावा, ईएफटीए में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार स्विट्जरलैंड को होने वाला 98 फीसदी निर्यात औद्योगिक वस्तुओं का है, जिन पर पहले ही शून्य सीमा शुल्क लागू

होता है। इसके बावजूद, समझौते का महत्व इस तथ्य में है कि यह न केवल भारत में एफडीआई और नई तकनीकों के प्रवाह को बढ़ाएगा, जो विनिर्माण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी है, बल्कि द्विपक्षीय व्यापार में भारत के लिए नए क्षेत्र भी खोलेगा। वर्ष 2027 तक शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की चुनौती को पूरा करने की दिशा में यह समझौता एक कदम भर नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है। उम्मीद है कि इससे दूसरे देशों के साथ विचाराधीन मुक्त व्यापार समझौतों का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

पाकिस्तान में हालात आज भी वही

पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने भले 44 साल बाद ही सही, लेकिन मान लिया कि जुल्फिकार अली भुट्टो को दी गई फांसी में उचित न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ था। लेकिन सेना की जिस तानाशाही की वजह से ऐसा हुआ, वह आज भी पाकिस्तान की राजनीति पर हावी है।

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में काली सलवार-कमीज और काले कोट पहने खड़े थे। उनकी कोट की जेब में विशुद्ध सिंधी रंगों वाला एक प्रिंटेड रूमाल था। बिलावल अपनी कानूनी टीम के साथ दिवंगत नाना यानी पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के मामले में फैसले का इंतजार कर रहे थे। यह अदालत की लाइव कार्यवाही थी और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लोग इसे देख रहे थे।

प्रधान न्यायाधीश ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए कहा, 'जुल्फिकार अली भुट्टो के मामले की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई और न ही संविधान की उचित न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया गया। लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा मुकदमे की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट में अपील की कार्यवाही के दौरान निष्पक्ष सुनवाई के मौलिक अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 4 एवं 9 में निहित उचित प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया, जबकि संविधान के अनुच्छेद 10ए में उचित प्रकिया के तहत एक अलग और मौलिक अधिकार के रूप में निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी दी गई है।'

मरिआना बाबर
वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार

फैसला सुनते ही बिलावल रो पड़े और जेब से रूमाल निकालकर अपने आंसू पोछे। उनकी टीम के सदस्यों और समर्थकों की आंखों में भी आंसू थे। बाद में मीडिया से बात करते हुए उनकी आवाज कांप रही थी। जब उनकी मां बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई थी, तब भी मैंने छोटे से बिलावल को सार्वजनिक रूप से रोते हुए नहीं देखा था। अब बिलावल बड़े हो गए हैं और पीपीपी के अध्यक्ष हैं। वह न केवल अपने नाना, बल्कि पीपीपी के पहले अध्यक्ष जुल्फिकार अली भुट्टो के मामले की सुनवाई देख रहे थे। मैंने हमेशा कहा है कि सैन्य तानाशाह और भ्रष्ट व अनैतिक सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुल्फिकार अली भुट्टो को दी गई फांसी एक 'न्यायिक हत्या' थी। जैसा कि किसी ने टिप्पणी की कि इतिहास ने पहले ही जुल्फिकार अली भुट्टो

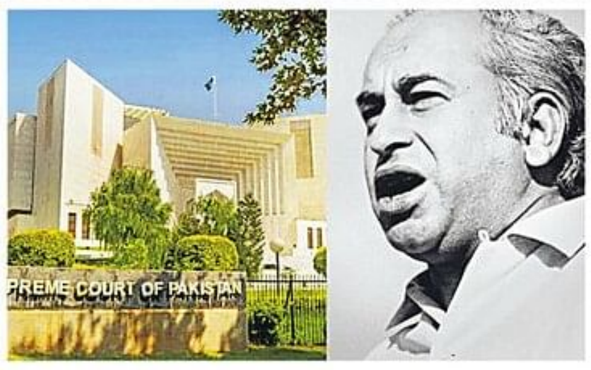

को दोषमुक्त कर दिया है। भुट्टो के मुकदमे की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ताजा रुख स्वागतयोग्य है। लेकिन शीर्ष अदालत को अपनी नाक के नीचे होने वाली सुनवाई की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना चाहिए। देर से न्याय होना न्याय नहीं होने के समान है।

सुप्रीम कोर्ट ने जब भुट्टो को फांसी देने का फैसला सुनाया था, तब बिलावल का जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला आसिफ अली जरदारी द्वारा भुट्टो की फांसी के खिलाफ 2011 में दायर मुकदमे के संदर्भ में था। इस ताजे ऐतिहासिक फैसले की पृष्ठभूमि यह है कि वर्ष 2011 में राष्ट्रपति रहते हुए आसिफ अली जरदारी ने संविधान के अनुच्छेद 186 के तहत भुट्टो की मौत के फैसले पर फिर से विचार करने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट के इस ताजा फैसले का अनेक राजनेताओं एवं वकीलों ने स्वागत करते हुए इसे 'ऐतिहासिक' बताया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा, 'इतिहास की गलतियों को सुधारना मुमकिन तो नहीं है, लेकिन उस गंभीर गलती को स्वीकार करना नया इतिहास है और इससे नई परंपरा स्थापित हुई है। उन्होंने आगे कहा कि पिछली गलतियों को सुधारकर और दुश्मनी को खत्म करके ही राष्ट्रीय एकता और विकास को बढ़ाया जा सकता है।'

इस बीच बिलावल की बहन आसिफा भुट्टो ने कहा कि आखिर भुट्टो की 'न्यायिक हत्या' के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई से वंचित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि उनकी न्यायिक हत्या के 44 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, जो मुल्क के लिए एक बड़ी उम्मीद थे, को एक क्रूर एवं षड्यंत्रकारी तानाशाह द्वारा इस दुनिया से खत्म कर दिया गया। आसिफा बेनजीर भुट्टो की सबसे छोटी संतान हैं और हाल ही में एक दूसरे कारण से चर्चा में थीं।

उनके पिता आसिफ अली जरदारी और भाई बिलावल भुट्टो हाल में हुए चुनाव में सिंध से दो सीटों से चुनाव लड़े थे और दोनों सीटों पर जीत गए। उम्मीद है कि उनमें से एक सीट खाली होने के बाद आसिफा वहां से चुनाव लड़कर सांसद बनेंगी। यह एक अनूठी बात होगी कि जरदारी, बिलावल एवं आसिफा एकसाथ निचली सदन में उपस्थित होंगे। मुल्क के इतिहास में ऐसी कोई मिसाल नहीं है, जब कोई पिता और उनकी दो संतान एक ही समय में सांसद हों। आसिफा भुट्टो ने आगे कहा, 'शीर्ष अदालत के ताजा फैसले ने जुल्फिकार अली भुट्टो को सही साबित किया है। मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लिए सिर्फ दुआ कर सकती हूं, जिन्होंने जीवन भर अपने पिता की बेगुनाही साबित करने के लिए अथक संघर्ष किया। चार दशकों के बाद आखिरकार न्याय की जीत हुई है।' जुल्फिकार भुट्टो की दूसरी नातिन फातिमा भुट्टो, जो प्रसिद्ध लेखिका हैं, ने कहा, 'यह पाकिस्तान के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री के खिलाफ किया गया ऐतिहासिक अन्याय था। हम अदालत के सर्वसम्मत फैसले का स्वागत करते हैं और दुआ करते हैं कि ऐसा अन्याय दोबारा कभी न दोहराया जाए।'

लेकिन वकील हसन ए नियाजी ने जो कहा, वह पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट और नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है- यह मानना कि जेडए भुट्टो को निष्पक्ष सुनवाई से वंचित रखा गया, एक स्वागतयोग्य निर्णय है, लेकिन जिन संरचनात्मक मुद्दों ने ऐसा घोर अन्याय होने दिया, वे पाकिस्तान की राजनीतिक और कानूनी व्यवस्था का हिस्सा बने हुए हैं। एक निर्दोष राजनेता को एक ताकतवर सैन्य तानाशाह और उससे प्रभावित अदालत ने फांसी पर लटका दिया। इसी वजह से प्रधान न्यायाधीश ईसा ने टिप्पणी की कि हमारे न्यायिक इतिहास में कुछ ऐसे मामले हैं, जिन्होंने लोगों को मन में यह धारणा बनाई है कि या तो भय या पक्षपात ने कानूनी ढंग से न्याय देने की प्रक्रिया को बाधित किया है। इसलिए हमें आत्म-जिम्मेदारी की भावना से, विनम्रता के साथ अपनी पिछली गलतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और यह सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में कानून के प्रति अटूट निष्ठा के साथ न्याय दिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जब तक हम अपनी पिछली गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक खुद को सुधार नहीं सकते और न ही सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

ब्रह्मकुमारी शिवानी

परमपिता परमात्मा से संबंध जोड़ने अथवा उनसे योग युक्त होने का अर्थ भी मन को उनकी लगन में मगन करना अथवा बुद्धि को उनकी स्मृति में स्थित करना है।

जो मन परमात्मा की लगन में मगन है

जब हम सांसारिक संबंधों पर विचार करते हैं, तो पता चलता है कि संबंध जोड़ने का पहला साधन है-परिचय, पहचान तथा ज्ञान। जब कोई बच्चा पैदा होता है, तो अपने पिता के साथ उसका संबंध तो जन्म-काल से ही जुड़ जाता है। बच्चे को यह बताया जाता है कि अमुक व्यक्ति उसका पिता है और अमुक नारी उसकी माता। यह ज्ञान अथवा पहचान प्राप्त किए बिना बच्चे का अपने माता-पिता के साथ संबंध जुड़ ही नहीं सकता। बचपन में तो केवल माता-पिता के नाम-रूप का ही परिचय मिलता है। उसमें निश्चय करने से ही बच्चे का संबंध अपने माता-पिता से जुड़ता है। परंतु वह बच्चा इस संबंध को बहुत गहराई से नहीं जानता, न ही यह संबंध उसके जीवन और व्यवहार में अभी गहरा उतरा ही होता है, तब भी वह बच्चा जब कभी अपने पिता के सम्मुख जाता है, अथवा जब भी उसे अपने पिता की स्मृति आती है, तो वह स्वयं को उनका पुत्र अनुभव करता है।

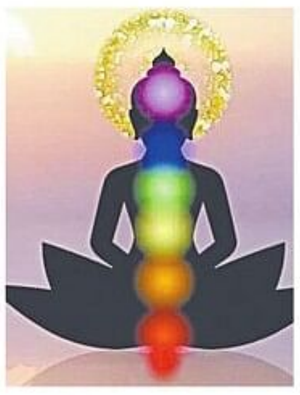

फिर जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसे अपने पिता के नाम और रूप के अलावा यह भी ज्ञान होता जाता है कि उसके पिता कौन-सा धंधा करते हैं और किस देश अथवा नगर के निवासी हैं। बाद में उसे यह भी परिचय मिल ही जाता है कि उसके पिता की पूंजी, संपत्ति अथवा आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, उनमें क्या गुण हैं, उनका कौन-सा कुल या धर्म है, आदि-आदि। अतः उस समस्त परिचय के आधार पर, उसकी बुद्धि में अपने पिता की स्मृति रहती है, तभी तो वह यह कोशिश करता है कि उतना ही खर्च करे, जितना कि पिता की आर्थिक स्थिति से संभव हो, वैसे ही कर्म करे, जो उसके कुल और धर्म के अनुकूल हों, वह ऐसे रीति-रिवाज अपनाए, जो उसके देश और वंश आदि के अनुसार हों।

इस प्रकार, उसके पिता का विस्तृत परिचय, उसकी स्मृति, उसके जीवन के समस्त कर्मों और व्यवहार को मर्यादित करता है। पुनश्च, जब कभी अपने पिता के साथ उसका लेन-देन व कार्य-व्यवहार होता है, तो वह पुत्र की तरह ही होता है। इसी तरह, उसका जिस किसी से घनिष्ठता का नाता होता है, उसकी ओर ही उसका मन लगा रहता है। उसके प्रेम और स्नेह में उसका मन डूबा रहता है। वास्तव में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध जुड़ने का मुख्य चिह्न ही एक की मन-बुद्धि का दूसरे के प्रेम में विभोर होना और स्नेह में स्थित होना है।

ठीक इसी प्रकार, परमपिता परमात्मा से संबंध जोड़ने का अर्थ भी मन को उनकी लगन में मगन करना अथवा बुद्धि को उनकी स्मृति में स्थित करना है। मनुष्य किसी की लगन में जितना मगन होता है, उतना ही उसे और सब कुछ फीका लगता है और अन्य सब तरफ से उसका मन उचटता जाता है। अतः बुद्धि द्वारा परमपिता परमात्मा की स्मृति का रसपान करने में लगी हुई आत्मा ही वास्तव में योग युक्त है, उसी का संबंध मानो परमात्मा से जुड़ा हुआ है।

ईश्वर के निमित्त...

सूत्र

परमात्मा से संबंध जोड़ने का भाव परमात्मा के प्रति अर्पणमय होकर रहना है। सभी कर्म करते समय भी स्वयं को परमात्मा ही के कार्य में निमित्त मानना और अपने तन-मन-धन को परमपिता परमात्मा का ही मानने से मनुष्य की ममता और आसक्ति मिटती है और वह अपने मन को किसी मायावी कार्य में नहीं लगाता।

दूसरा पहलू

इसके पर्याप्त साक्ष्य हैं कि कोविड मानसिक स्वास्थ्य को कई स्तरों पर प्रभावित कर रहा है। हालांकि अभी इसका कोई इलाज नहीं है।

क्या कोविड दिमाग को भी प्रभावित कर रहा है

कोविड की शुरुआत से ही यह माना जाने लगा था कि इसका मस्तिष्क पर गहरा असर पड़ता है, जिससे एकाग्र होने, याद रखने और स्पष्ट रूप से सोच पाने की क्षमता प्रभावित होती है। हालांकि सिरदर्द, दिल के दौरे, नींद की समस्या और नसों के निष्क्रिय होने को भी विशेषज्ञ कोरोना से जोड़ते हैं, लेकिन चार साल बाद शोधार्थियों के पास इसके पर्याप्त साक्ष्य हैं कि कोविड मानसिक स्वास्थ्य को कई स्तरों पर प्रभावित कर रहा है। फिलहाल चिकित्सा विज्ञान के पास इसका कोई समाधान भी नहीं है।

जायद-अल एली

शोधार्थियों ने पाया कि जो लोग पहले कोविड से संक्रमित हुए थे, उनकी स्मरण शक्ति घटी है, और जो काम उन्हें दिया जाता है, उसे वे सफाई से नहीं कर पाते।

हाल ही में *न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन* के शोध में बताया गया है कि कोविड संक्रमण मस्तिष्क को प्रभावित करता है। कुछ ऐसे मृतकों के पोस्टमार्टम से, जो कोविड संक्रमित थे पर महीनों बाद दूसरी बीमारियों से मरे, पता चला कि उनके मस्तिष्क में वायरस सक्रिय था। इससे स्पष्ट है कि सार्स-कोव-2 सिर्फ सांसों से संक्रमण नहीं फैलाता, बल्कि यह वायरस कुछ लोगों के मस्तिष्क में भी प्रवेश कर सकता है।

न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पिछले दिनों प्रकाशित एक दूसरी अध्ययन रिपोर्ट का निष्कर्ष भी इससे मिलता-जुलता है। जर्नल ने कुल 1,13,000 लोगों के कौशल और व्यावहारिक ज्ञान की परीक्षा ली। शोधार्थियों ने पाया कि जो लोग पहले कोविड से संक्रमित हुए थे, उनकी स्मरण शक्ति घटी है, और जो काम उन्हें दिया जाता है, उसे वे सफाई से नहीं कर पाते। यह कमी उन लोगों में ज्यादा देखी गई, जो बिल्कुल शुरुआती दौर में संक्रमित हुए थे। इस अध्ययन में यह भी पाया गया कि जिन्हें मामूली संक्रमण हुआ था, उनकी तुलना में गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों के सामान्य ज्ञान में ज्यादा कमी आई, जबकि अस्पतालों में इलाज करा चुके लोगों के सामान्य ज्ञान का स्तर और भी कम हो गया।

एक हालिया सर्वे में पाया गया कि कोविड के बाद से करीब 10 लाख कामकाजी लोगों को याद रखने में समस्या होने लगी है। यह समस्या 18-44 आयु वर्ग में ज्यादा है।

ऐसे ही, अमेरिका में आबादी से जुड़े एक हालिया सर्वे में पाया गया कि कोविड के बाद से करीब 10 लाख कामकाजी लोगों को याद रखने में समस्या होने लगी है। यह समस्या 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों में ज्यादा है। यूरोपीय संघ में भी वर्ष 2022 में 15 प्रतिशत लोगों ने स्मरण शक्ति से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताया। ज्यादातर शोधार्थी अब एकमत हैं कि कोविड-19 को ऐसे वायरस के रूप में देखना चाहिए, जिसका मस्तिष्क पर भीषण असर पड़ता है। लिहाजा गहरे अर्थ में कोविड बड़ी मानवीय आबादी और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है।

-द कन्वर्सेशन।

आंकड़े

मालदीव में पर्यटक

मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में कमी आई है, लेकिन पिछले वर्ष सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक ही वहां गए थे।

आंकड़े-मालदीव पहुंचने वाले पर्यटकों के प्रतिशत में | स्रोत : MoT, Maldives

प्रार्थना शुद्ध मन और विश्वास के साथ किए जाने से ही फलदायक होती है। भगवान निश्छल, निष्कपट व शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति की प्रार्थना जल्द सुनते हैं।

प्रार्थना की शक्ति

अंतर्यात्रा
शिवकुमार गोयल

सभी धर्मों में प्रार्थना को महत्व दिया गया है। हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, जैन व बौद्ध-सभी अपने-अपने ढंग से प्रार्थना करते हैं। गांधी जी प्रार्थना करने के बाद ही सोते थे। सभी धर्माचार्यों, संत-महात्माओं ने प्रभु प्रार्थना को प्रभावी माना है।

आध्यात्मिक विभूति दादा टीएल बासवानी ने प्रार्थना पर एक पुस्तक *लिटिल बुक ऑफ प्रेयर* भी लिखी है। उन्होंने प्रार्थना के कई प्रकार बताए हैं, जैसे निवेदनीय प्रार्थना, सामान्य प्रार्थना, शांति और साधना की प्रार्थना, आदि। वह लिखते हैं-प्रार्थना शुद्ध मन और विश्वास से करने से ही फलदायक होती है। भगवान निश्छल, निष्कपट व शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति की प्रार्थना जल्द सुनते हैं। जब आप प्रार्थना खत्म करते हैं, तो आपको विश्वास होना चाहिए कि आपने जो कुछ मांगा है, आपको दिया जा चुका है, तब आप इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं।

उड़िया बाबा कहते थे, निष्काम प्रार्थना ज्यादा प्रभावी होती है। संत सभी प्राणियों के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। गरीबों, अनाथों, अपाहिजों के कल्याण के लिए की गई प्रार्थना निष्काम होती है। वेदों में ईश्वर से *सर्वे भवन्तु सुखिनः* प्रार्थना की गई है। महर्षि अरविंद लिखते हैं, भगवान से सदबुद्धि मांगो-समझो सब मिल गया।

(अमर उजाला आर्काइव से)

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 1 मार्च, 1955

पहली बार बजट दस्तावेज हिंदी में

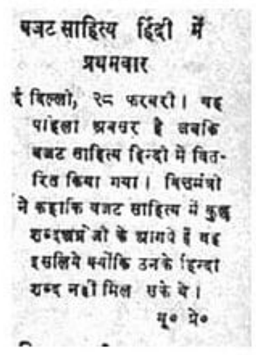
बजट साहित्य हिंदी में
प्रथमबार
नई दिल्ली, २८ फरवरी। यह पहला अवसर है जबकि बजट साहित्य हिन्दी में वितरित किया गया। वित्तमंत्री ने कहाकि बजट साहित्य में कुछ शब्द अंग्रेजी के आगये हैं यह इसलिये क्योंकि उनके लिये हिन्दी शब्द नहीं मिल सके थे।
यू० पी०

आज संसद में केंद्रीय बजट पेश किया गया और यह पहली बार है, जब हिंदी में बजट दस्तावेज सांसदों के बीच वितरित किया गया। वित्तमंत्री ने कहा कि बजट साहित्य में कुछ अंग्रेजी के शब्द आ गए, क्योंकि उनके लिए उपयुक्त हिंदी शब्द नहीं मिल सके।

बौद्धिक नवाचार आधारित व्यवस्था की ओर

बौद्धिक संपदा, शोध एवं नवाचार के क्षेत्र में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। पर अब भी तेज विकास के ऊंचे लक्ष्यों के लिए काफी कुछ करना बाकी है।

जयंतीलाल भंडारी | **उद्योग**

हाल ही में अमेरिकी उद्योग मंडल 'यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स' के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट में वैश्विक बौद्धिक संपदा (आईपी) सूचकांक 2024 में भारत दुनिया की 55 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से 42वें स्थान पर है। पिछले वर्ष भी भारत इसी क्रम पर स्थित था। आईपी सूचकांक के तहत शीर्ष क्रम पर जिन 10 देशों की अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें क्रमशः अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, जापान, नीदरलैंड, आयरलैंड, स्पेन तथा स्विट्जरलैंड हैं। बौद्धिक संपदा में आविष्कार, रचनात्मक व कलात्मक कार्य, डिजाइन, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क और शोध व नवाचार शामिल हैं।

हालांकि इस नई आईपी रिपोर्ट में भारत की बौद्धिक संपदा आधारित नवाचार गतिविधियों की प्रशंसा की गई है और कहा गया है कि भारत बौद्धिक नवाचार के जरिये अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाने की संभावनाओं वाला देश है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आईपी मापदंडों के मद्देनजर भारत का आकार और

आर्थिक रसूख वैश्विक पटल पर बढ़ रहा है। यदि हम बौद्धिक संपदा, शोध एवं नवाचार से जुड़े अन्य वैश्विक संगठनों की रिपोर्टों को देखें, तो पाते हैं कि भारत इस क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अब भी देश के तेज विकास के ऊंचे लक्ष्यों के लिए बौद्धिक संपदा शोध और नवाचार में भारत को काफी कुछ करना जरूरी है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) 2023 की रैंकिंग में 132 अर्थव्यवस्थाओं में भी भारत 40वें पायदान पर दिखाई दे रहा है। खास बात यह भी है कि इस सूचकांक में भारत 37 निम्न-मध्यम-आय समूह वाली अर्थव्यवस्थाओं के बीच अग्रणी बनकर उभरा है।

साथ ही, भारत नवाचार के संबंध में मध्य और दक्षिणी एशिया की 10 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ऊपर है। बौद्धिक संपदा शोध एवं नवाचार की दुनिया में भारत की रैंकिंग यह दर्शा रही है कि भारत इनोवेशन का हब बनता जा रहा है। भारत में शोध एवं नवाचार को बढ़ाने में डिजिटल ढांचे और डिजिटल सुविधाओं की भी अहम भूमिका है। भारत आइटी सेवा निर्यात और वेंचर कैपिटल हासिल करने के मामले में लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत के नवाचार दुनिया में सबसे प्रतियोगी, किफायती, टिकाऊ, सुरक्षित और बड़े स्तर पर लागू होने वाले समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। आज भारत में करीब 1.25 लाख स्टार्ट-अप हैं, जिनमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं।

गौरतलब है कि बौद्धिक संपदा, शोध एवं नवाचार के आधार पर ही विभिन्न देशों के उद्यमी और कारोबारी किसी देश में अपने उद्योग-कारोबार शुरू करने संबंधी निर्णय लेते हैं। हालांकि भारत के विकास में बौद्धिक संपदा, शोध एवं नवाचार से जुड़े तीन आधारों की बढ़ती भूमिका दिखाई दे रही है, लेकिन इन आधारों से विकास को ऊंचाई देने के लिए इस क्षेत्र में सरकार व निजी क्षेत्र को परिव्यय बढ़ाना होगा। इस समय भारत में आर ऐंड डी पर जीडीपी का करीब 0.67 प्रतिशत ही व्यय हो रहा है। भारत में शोध एवं नवाचार पर खर्च वैश्विक औसत 1.8 फीसदी से भी कम है। फिलहाल देश में निजी क्षेत्र का आर ऐंड डी पर खर्च जीडीपी का करीब 0.35 फीसदी है।

इसमें कोई दोमत नहीं है कि सरकार बौद्धिक संपदा, शोध एवं नवाचार की अहमियत को समझते हुए इस क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए दिखाई दे रही है। वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में वित्तमंत्री सीतारमण ने उभरते क्षेत्रों में नवाचार और शोध को प्रोत्साहन देने के लिए एक लाख करोड़ रुपये के कोष की स्थापना करने की घोषणा की है।

उम्मीद है कि सरकार अमेरिकी उद्योग मंडल, यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स की वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक रिपोर्ट, 2024 के तहत भारत सरकार बौद्धिक संपदा, शोध एवं नवाचार के वर्तमान ढांचे में मौजूद खामियों को दूर करने और भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए एक नया मॉडल बनाने की डगर पर आगे बढ़ेगी। इससे जहां ब्रांड इंडिया और मेड इन इंडिया की वैश्विक स्वीकार्यता सुनिश्चित की जा सकेगी, वहीं स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, कारोबार, ऊर्जा, शिक्षा, रक्षा, संचार, अंतरिक्ष सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकेगा। वर्ष 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और वर्ष 2047 तक विकसित देश बनने के बड़े लक्ष्य को हासिल करने के मद्देनजर सरकार और उद्योग-कारोबार जगत द्वारा बौद्धिक संपदा, शोध और नवाचार की भूमिका को और अधिक अहम एवं प्रभावी बनाए जाने की उम्मीद की जा सकती है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

चिंतन

नए एफटीए से निवेश और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा

मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के बीच भारत का चार देशों के समूह ईएफटीए के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) करना निवेश व ट्रेड को गति देने की दिशा में अहम कदम है। एफटीए के तहत ईएफटीए ने अगले 15 साल में भारत में 100 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। यह भारत का ऐसे समूह के साथ पहला आधुनिक व्यापार करार है, जिसमें विकसित देश शामिल हैं। किसी व्यापार करार में यह पहला मौका है, जब ईएफटीए अगले 15 साल में बड़ा निवेश करेगा। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के सदस्य देशों में आइसलैंड, लीशटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। इस समझौते में माल में व्यापार, उत्पत्ति के नियम, बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर), सेवाओं में व्यापार, निवेश प्रोत्साहन और सहयोग, सरकारी खरीद, व्यापार में तकनीकी बाधाएं और व्यापार सुविधा शामिल है। हालांकि एफटीए का जो अब तक का भारत का अनुभव है, उसमें अधिक फायदा साझीदार देश या समूह को ही मिला है। उदारीकरण व मुक्त बाजार व्यवस्था में भी यही हाल हुआ। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ से एफटीए के बाद अब भारतीय उद्यमियों, सेवाओं और उत्पादों को यूरोपीय बाजार तक पहुंच आसान व किफायती होती जाएगी। भारत मुक्त व्यापार समझौते के जरिये अमेरिकी या चीनी बहुपक्षीय ट्रेड खेमे में जाने की बजाय ग्लोबल ट्रेड में अपने रणनीतिक विस्तार को बढ़ावा दे रहा है। भारत और ईएफटीए आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए जनवरी, 2008 से आधिकारिक तौर पर व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) समझौते पर बातचीत कर रहे थे। 16 वर्ष लगे। दोनों पक्षों ने अक्टूबर, 2023 में वार्ता फिर शुरू की और इसे तेजी से पूरा किया। ईएफटीए देश यूरोपीय संघ (ईयू) का हिस्सा नहीं हैं। इस नए एफटीए का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन भारत को अपने मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत व वोकल फॉर लोकल अभियान पर भी ध्यान बनाए रखना होगा। यह सावधानी भी जरूरी है कि एफटीए से भारत एक डंपिंग राष्ट्र में तब्दील न हो जाय। भारत को एफटीए वो राष्ट्र में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाना आना चाहिए। भारत 27 देशों के समूह यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ अलग से एक वृहद मुक्त व्यापार करार के लिए बातचीत कर रहा है। इससे पहले भारत ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए वार्ता को तेजी से पूरा करने की रणनीति अपनाई थी। भारत-ईफएटीए का द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में 18.65 अरब डॉलर रहा था। यह 2021-22 में 27.23 अरब डॉलर था। इन देशों में स्विट्जरलैंड, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। नवंबर 2019 में भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) से बाहर हो गया था। उसके बाद भारत ने नीतिगत स्तर पर एफटीए को बढ़ावा दिया। वर्ष 2021 में भारत व ईयू की वार्ता शुरू हुई। अभी यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ भी बातचीत जारी है। भारत का मॉरीशस के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता (सीईसीपीए) है। दक्षिण एशिया तरजीही व्यापार समझौता (साफ्टा) 1995 में लागू हुआ था। एशिया प्रशांत व्यापार समझौता (एपीटीए) भी है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत रियायतों के आदान-प्रदान के माध्यम से अंतर-क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है। पिछले एक दशक में भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, दक्षिण कोरिया, जापान और मलेशिया के साथ एफटीए किया है।

समाप्ति की ओर वामपंथी उग्रवाद

नक्सल हिंसा
उज्ज्वल दीपक

गरीबों और आदिवासियों को समाज में समाहित करने और सामाजिक-आर्थिक विकास की दिशा में लोगों का आत्म-विश्वास बढ़ रहा है। भारतीय संविधान में विरोध और विचारों में मतभेद को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार किया गया है। 125 करोड़ से अधिक जनसंख्या और 10,000 से ज़्यादा बोलियां और सर्वाधिक सांस्कृतिक समृद्धता वाले भारत में सभी के विचारों का एक दूसरे से सहमत होने की कल्पना भी बेमानी होगी। किंतु जब ये मतभेद 'विचारों' की जगह 'हथियारों' से प्रकट किए जाएं तो वही संविधान शासन को कड़े कदम उठाने की भी शक्ति प्रदान करता है। चुनौती बनकर खड़े होने वाला वामपंथी उग्रवाद अब समाप्ति की ओर है।

हिंसा द्वारा लोकतंत्र को चुनौती देने का वामपंथी उग्रवादियों का लंबा इतिहास रहा है। इस तथाकथित 'विचारधारा की लड़ाई' ने प्रभावित क्षेत्रों में न सिर्फ विकास ठप किया बल्कि पिछले चार दशकों में हिंसा के चलते 16,652 सुरक्षाकर्मियों और नागरिकों ने जान गंवाई हैं। विडंबना यह है कि उग्रवादियों ने जल, जंगल और जमीन की लड़ाई की आड़ में विकास कार्यों को अवरुद्ध किया और स्कूल, अस्पताल एवं सड़कों के निर्माण होने से रोका है। आदिवासियों के हक़ की बातें करने वाले गैर सरकारी संगठन एवं विदेशी वित्तीय सहायता से पनप रहे कुछ अर्बन नक्सलियों की मदद से विदेशी हथियारों की खेप इन उग्रवादियों तक पहुंचाई जाती रही है।

आदिवासियों को ढाल की तरह इस्तेमाल करने की वजह से ही सरकार को बल प्रयोग करने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। दशकों से कांग्रेस सरकार की वामपंथियों के प्रति सहानुभूति, जिसकी वजह से उपजी विफलता और शोषण के फलस्वरूप ही इतने वर्षों तक आदिवासी समुदाय को वामपंथी उग्रवाद दिग्भ्रमित करने में सफल होता रहा है। 2014 के बाद से इस स्थिति में आमूलचूल बदलाव हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कड़े निर्णयों की वजह से वामपंथी उग्रवाद का प्रभाव आज बहुत सीमित हो चुका है और लड़ाई अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। आत्मनिर्भर नए भारत में विकास और शांति के सन्देश के साथ गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए तीन आयामी रणनीति बनाई। बेहतर रणनीति से उग्रवादियों पर लगाम, बेहतर केंद्र-राज्य समन्वय और विकास से जन भागीदारी। इस तीन आयामी रणनीति से पिछले 10 वर्षों में वामपंथी उग्रवाद पर लगाम कसने में ऐतिहासिक सफलता मिली है जो कि आंकड़ों से परिलक्षित होती है। पिछले 35 वर्षों में वामपंथी उग्रवाद से सबसे कम हिंसक घटनाएं और 40 वर्षों में सबसे कम मृत्यु इस वर्ष रिपोर्ट की गई। हिंसक घटनाएं वर्ष 2010 के उच्च स्तर की तुलना में 76 प्रतिशत घट गई। वामपंथी उग्रवाद के भौगोलिक प्रसार में भी लगातार गिरावट आई है। पिछले वर्ष हिंसा की घटनाएं केवल 45 जिलों के 176 थानों से रिपोर्ट की गई थी, जबकि 2010 में 96 जिलों के 465 थानों में हिंसा की घटनाएं हुई थीं। इसका सिकुड़ता दायरा इस बात से भी परिलक्षित होता है कि पिछले वर्ष 72 प्रतिशत हिंसा की सूचना केवल 10 जिलों से रिपोर्ट हुई है। थानों के स्तर पर देखें तो 50 प्रतिशत हिंसा केवल 30 थानों से रिपोर्ट हुई हैं। पिछले कई दशकों के बाद पहली बार आम नागरिकों और सुरक्षाबलों की मृत्यु की संख्या विगत वर्ष 2021 में 100 से कम रही। वामपंथी उग्रवाद ऐतिहासिक रूप से ऐसे क्षेत्रों में पनपा जहां पर गरीबी ने अपनी जड़ें जमा रखी थी। उनके विचार से प्रभावित समूहों ने गरीबी से प्रभावित लोगों की असंतुष्टि को खाद पानी के रूप में इस्तेमाल करके उग्रवाद के बीज बोए थे। इन समूहों को स्थानीय समर्थन मिलने की वजह से सुरक्षा संस्थाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता था, परन्तु 2014 के बाद स्थिति बदली। मोदी सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं का प्रसार इन क्षेत्रों में भी

हुआ और लोगों को यह विश्वास हुआ की सरकार ही उनकी सच्ची हितैषी है, न कि उग्रवादी! विकास से जन भागीदारी के तहत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रभावित क्षेत्रों में गरीब कल्याण और विकास के लिए योजनाओं पर अतिरिक्त जोर देकर सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की है।

उग्रवादियों पर लगाम कसने की रणनीति के तहत सुरक्षा वैक्यूम तथा कोर एरिया को कम किए जाने के भरसक प्रयास किए गए हैं. 2019 के बाद से 195 नए शिविर खोले गए हैं, जिन्होंने कुछ क्षेत्रों को छोड़ कर प्रभावित क्षेत्रों में सिक्यूरिटी वैक्यूम लगभग शून्य कर दिया है। इस रणनीति के सकारात्मक परिणाम देखे जा रहे है और बिहार के बरमसिया, चकरबंदा तथा झारखंड के बूढ़ा पहाड़, पारसनाथ जैसे माओवादियों के गढ़ों में अपने कैम्प स्थापित कर वहाँ पर सेक्युरिटी वैक्यूम को पूरी तरीके से खत्म करने में सफलता प्राप्त की है। इंटेलिजेंस आधारित ऑपरेशनों के माध्यम से 14 पोलित ब्यूरो तथा सेंट्रल कमेटी मेम्बर के नेताओं को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, जिससे वरिष्ठ माओवादी नेतृत्व में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है। सुरक्षा बलों ने उग्रवादियों के खिलाफ ऑफेंसिव रणनीति अपनाते हुए नक्सलियों को घेरा। बेहतर केंद्र राज्य समन्वय के तहत केंद्र ने प्रभावित राज्यों की सरकारों को बिना भेदभाव के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बटालियन, हेलीकॉप्टर, प्रशिक्षण, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए धन, उपकरण और हथियार, खुफिया जानकारी, फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन का निर्माण आदि के लिए मदद मुहैया करवाई। राज्यों के क्षमता निर्माण के लिए पिछले 09 वर्षों में प्रभावित राज्यों को 2606 करोड़ रुपये जारी किए गए। राज्यों के विशेष बलों और विशेष खुफिया शाखाओं को पिछले पांच वर्षों में 1724 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। 536 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन का निर्माण किया गया और 102 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियों को सहायता योजना के तहत कैंप इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु 106 करोड़ और 6 अस्पतालों के उन्नयन के लिए 12.06 करोड़ रुपये दिए गए। सड़क सम्पर्क को बेहतर करने के लिये 12100 किलोमीटर सड़कों की स्वीकृति पिछले 9 वर्षों में दी गई और लगभग 10350 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। डाक विभाग ने प्रभावित जिलों में पिछले 9 वर्षों में बैंकिंग सेवाओं के साथ 4903 नए डाकघर खोले। इसके साथ ही जनजातीय युवा एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत अब तक 26.5 करोड़ रुपये के खर्चे के साथ 22,000 युवाओं को देश के बड़े और विकसित क्षेत्रों के दौरे के लिए ले जाया गया। इसका उद्देश्य इन युवाओं को तकनीकी/औद्योगिक उन्नति से अवगत कराना है ताकि उन्हें वामपंथी उग्रवाद के प्रभाव से दूर किया जा सके।

सरकार की विकास योजनाओं के लाभ को सर्वसाधारण तक पहुंचाने की पहल सफल हुई है और इससे नक्सलियों की संरचना में दबाव महसूस हो रहा है। गरीबों और आदिवासियों को समाज में समाहित करने और सामाजिक-आर्थिक विकास की दिशा में लोगों का आत्म-विश्वास बढ़ रहा है। भारतीय संविधान में विरोध और विचारों में मतभेद को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार किया गया है। 125 करोड़ से अधिक जनसंख्या और 10,000 से ज़्यादा बोलियां और सर्वाधिक सांस्कृतिक समृद्धता वाले भारत में सभी के विचारों का एक दूसरे से सहमत होने की कल्पना भी बेमानी होगी। किंतु जब ये मतभेद 'विचारों' की जगह 'हथियारों' से प्रकट किए जाएं तो वही संविधान शासन को कड़े कदम उठाने की भी शक्ति प्रदान करता है। विदेशी हथियारों और देश विरोधी ताकतों के सहयोग से चुनौती बनकर खड़े होने वाला वामपंथी उग्रवाद अब समाप्ति की ओर है और प्रधानमंत्री मोदी का 'सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास' अब मूर्त रूप ले रहा है।

(लेखक लोक प्रशासन, कोलंबिया विवि में हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

सारा संसार

क़ुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली शहर के महरौली भाग में स्थित, ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊँची मीनार है। यह दिल्ली का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है।

अनदेखी

योगेंद्र माथुर

नंबर प्लेट के नियमों का हो पालन

अपने वाहन की नंबर प्लेट पर नंबर की जगह अपने पद, प्रतिष्ठा और पहचान का खास शब्द, नाम या स्लोगन लिखने अथवा चित्र या प्रतीक बनाने का फैशन छोटे शहरों से लेकर महानगरों तक में प्रायः देखा जाता है। विभिन्न नामों व आकृतियों वाली नंबर प्लेट के वाहन परिवहन नियमों को धता बताते हुए सड़कों पर बेखौफ दौड़ते हैं और अपना रौब गांठते हैं, लेकिन न तो यातायात पुलिस और न ही संबंधित विभाग इस मामले में कोई संज्ञान लेते हैं और न ही कोई कार्रवाई कभी करते दिखते हैं। परिणामस्वरूप ऐसे लोगों का दुस्साहस बढ़ता चला जाता है। यातायात नियमों के अनुसार वाहन की नंबर प्लेट पर नंबर निर्धारित आकार, रंग व तरीके से लिखवाया जाना आवश्यक होता है। विशेष डिजाइन, आकार व रंगों में लिखना और उसके साथ नंबर प्लेट पर अन्य कुछ अंकित करना गैरकानूनी होता है। सड़कों पर दौड़ने वाले अधिकांश दोपहिया व चौपहिया वाहनों की नंबर प्लेट पर वाहन चालकों द्वारा नंबर के बदले या नंबर के साथ साथ कुछ विशेष स्लोगन या नारे लिखे हुए हमें प्रायः देखने को मिलते हैं। कई वाहन चालक अपने बच्चों के नाम अपने वाहन की नंबर प्लेट पर लिखा कर बच्चों के प्रति अपना प्रेम उजागर करते दिखते हैं। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों या धार्मिक व सामाजिक संगठनों से जुड़े वाहन चालक संबंधित दलों, संगठनों के पूरे नाम या संक्षिप्त नाम और उनसे जुड़े अपने पद का नाम लिखा कर अपनी प्रतिष्ठा व पहचान दर्शा कर दूसरों पर विशेषकर यातायात पुलिस आदि पर अपना प्रभाव दर्शाने का जतन करते हैं। 'प्रेस' शब्द का भी खूब जमकर दुरुपयोग किया जाता है। प्रायः वाहन चालकों की यह सोच होती है कि अपने वाहन की नंबर प्लेट पर 'प्रेस' शब्द लिखकर वे चाहे जहां, जब-तब आ-जा सकते हैं और पुलिस की किसी प्रकार की चेकिंग या चालानी कार्रवाई से बचा जा सकता है। बड़ी संख्या में ऐसे वाहन इन शहरों में दौड़ लगा रहे होते हैं, जिन्होंने अपनी नंबर प्लेट पर नंबर तो लिखा रखे होते हैं लेकिन छोटे-बड़े आकार में या इस तरह की डिजाइन अथवा आकृति बना कर अंकित करवाए जाते हैं कि आम राहगीर या पुलिस सामान्य रूप से उन्हें पढ़ या समझ नहीं पाए। ऐसे वाहन किसी प्रकार की दुर्घटना के बाद आम राहगीरों के साथ पुलिस को भी आसानी से चकमा देकर निकल सकने में सक्षम होते हैं और प्रायः सफल भी हो जाते हैं, क्योंकि नंबर 'विशेष' तरीके से लिखे होने के कारण दुर्घटना आदि के समय इनके भागने के प्रयास के दौरान इनके नंबर का पढ़ पाना सामान्य रूप से संभव नहीं हो पाता। नंबर के अभाव में इनके चालक की पहचान करना भी मुश्किल होता है। ऐसा भी नहीं है कि वाहनों की नंबर प्लेट पर नंबर की जगह 'कुछ और या विशेष' लिखने अथवा अंकित कराने का गैर कानूनी कार्य आम वाहन चालक ही कर रहे होते हैं, स्वयं कानून पर अमल करवाने वाले पुलिस विभाग के कर्मचारी और उनके परिजन भी ऐसा करने में कोई कोताही नहीं बरतते हैं। अधिकांश पुलिसकर्मियों व उनके परिजनों द्वारा अपने निजी वाहनों की नंबर प्लेट पर रौब झाड़ने की गरज से 'पुलिस' शब्द लिखवाया जाता है और अपना 'रौब' कायम किया जाता है। यातायात व्यवस्थित करने के नाम पर जब तब चालानी कार्रवाई करने वाली पुलिस प्रायः सभी स्थानों पर इस मामले में आंखें मूंदी नजर आती है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

सिया राम मय सब जग जानी

संकलित
दर्शन

हमारे वेद कहते हैं- सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया...अर्थात सब सुखी हों, सब निरोगी हों। वहां कोई, वर्ण, जाति, समूह और पक्ष-विपक्ष की बात ही नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने युगों पहले यह सूत्र दे दिया था-वसुधैव कुटुंबकम्-यानी पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है। संपूर्ण विश्व के लोगों के सुख और स्वास्थ्य की कामना भारतीय दर्शन का मूल है। न सिर्फ मनुष्य, बल्कि जीव मात्र के हित की इच्छा रखना ही सनातनी परिचय है। मैं राम कथा गाता हूं। राम राज के मूल में भी सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया की ही भावना है। भगवान श्रीराम ने सेतु बनाया। आज पूरे विश्व में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सेतु बनाए जाने की आवश्यकता है। जिसमें भी राम तत्व होगा, वह केवल जोड़ने की बात करेगा, तोड़ने की नहीं। सत्य, प्रेम और करुणा प्रमुख राम तत्व हैं। जिसमें ये तत्व होंगे, वह वंचितों तक पहुंचेगा। राम समाज के वंचित लोगों के पास स्वयं चलकर गए। केवट, शबरी, अहिल्या के प्रसंग इसके प्रमाण हैं। आज समाज की एक बड़ी जरूरत है कि सक्षम लोग वंचित लोगों तक, अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक स्वयं चल कर पहुंचें। मानस में नौ प्रकार की भक्ति का वर्णन हुआ है। शबरी के सामने गाई गई नौ प्रकार की भक्ति में गोस्वामी जी ने सातवीं भक्ति पूरे संसार को ब्रह्ममय मानना-देखना बताई है-'सातवं सम मोहि मय जग देखा।' जब हम पूरे संसार को ब्रह्ममय देखेंगे, महसूस करेंगे तो किसी के भी दोष दिखाई नहीं देंगे।

यात्रा में नई बातें सीख पाएंगे तो व्यक्तित्व में निखार आएगा

संकलित
प्रेरणा

एक गरीब व्यक्ति अर्जुन के पास पहुंचा और बोला कि कोई चोर उसकी गाय चुराकर ले गया है। मेरी मदद करें। अर्जुन उस व्यक्ति की मदद के लिए अपने धनुष-बाण लेने युधिष्ठिर-द्रौपदी के कमरे में चले गए। अर्जुन ने उस गरीब की मदद तो कर दी, लेकिन पांडवों का बनाया हुआ नियम तोड़ दिया। ये नियम तोड़ने के लिए अर्जुन को वनवास जाना पड़ा। अर्जुन 12 वर्षों के लिए अकेले ही वनवास के लिए निकल पड़े थे। वे वन-वन घूम रहे थे। अर्जुन ने तय किया कि मुझे इस वनवास में तपस्या करके अपने व्यक्तित्व को और निखारना चाहिए। उन्होंने सोचा कि मुझे वन में दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि नए लोगों से मिलकर कुछ नया सीखना चाहिए। वनवास के समय में एक श्रीकृष्ण और अर्जुन की मुलाकात हुई। अर्जुन ने पूरी बात श्रीकृष्ण को बता दी। श्रीकृष्ण ने कहा कि तुम मेरे साथ द्वारका चलो। अर्जुन ने कहा कि मुझे तो वनवास में ही रहना है। मैं वन से बाहर नहीं जा सकता। श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वन में घूमो और नए-नए स्थानों का, नई-नई विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करो। जब हम यात्रा में होते हैं, तब हमें लगातार नया सीखते रहने की कोशिश करनी चाहिए। तभी यात्रा का लाभ मिल सकता है। वन तो तुम देख चुके हों, अब मैं तुम्हें द्वारका इसीलिए ले जा रहा हूं, ताकि तुम एक ऐसी नगरी देख सको, जहां तुम्हें और नई बातें सीखने को मिलेगी। द्वारका में योग में भोग और भोग में योग देखने को मिलेगा। तुम्हें द्वारका में बहुत बड़ा संदेश मिलेगा। श्रीकृष्ण की बातें मानकर अर्जुन द्वारका चले गए।

अंतर्मन

आज की पाती

देश में गरीबी घटने का यथार्थ

हाल ही में अमरीकी थिंक टैंक ब्रुकिंग्स की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि हमारे देश में गरीबी कम हो रही है और हमारा देश गरीबी से उबर रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश के शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में असामानता भी कम हुई है। यह हमारे देश के लिए अच्छी बात है कि गरीबी कम हुई है, लेकिन अभी भी भारत को गरीबी से निपटने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमारे देश में गरीबी के वैसे तो बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण के कारण भी गरीबी बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। मौसम चक्र के बिगड़ने के कारण दुनिया भर में इसका कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। - **रमेश पाठक**, रायगढ़

ट्रेंड

जनता का आभार

परिवार के सदस्य की तरह स्नेह देने के लिए पोरबंदर लोकसभा की जनता का आभार। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व, उनकी विकासवादी नीतियों और कार्यकर्ताओं के परिश्रम के साथ हम फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
-मनसुख मंडाविया, केंद्रीय मंत्री

अबाधित पहुंच बनानी होगी

सूडान में 18 मिलियन लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। बीमारी और कुपोषण एक घातक संयोजन है। यदि अब भोजन की अबाधित पहुंच की सुविधा नहीं दी गई, तो भयावह भुखमरी, बीमारी का प्रकोप और मौतें हो सकती हैं।
-टेड्रोस, डब्ल्यूएचओ महानिदेशक

गेंद पर खास नियंत्रण

मैंने एंडरसन को पहली बार 2002 में ऑस्ट्रेलिया में खेलते देखा था और गेंद पर उनका खास नियंत्रण था। नासिर हुसैन ने तब उनकी बहुत तारीफ की थी और आज भी, मुझे यकीन है, वह कहेंगे, "मैंने बोला था" - कि उन्होंने इसे जल्दी बुलाया था।
-सचिन तेंदुलकर, क्रिकेटर

हर नागरिक को हक मिलेगा

पांच न्याय का परचम अपनी गली-गली की दीवार, सब अंधेरे डूब जायेंगे, जब निकलेगा न्याय। यह न्याय-गीत उस भविष्य का सपना है जहां हर मत को न्याय मिलेगा, हर नागरिक को हक मिलेगा।
-प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव

करंट अफेयर

नेतन्याहू इजराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने शनिवार को कहा कि उन्हें लगता है कि इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में हमास के खिलाफ अपने युद्ध के तरीके से 'इजराइल की मदद करने के बजाय उसे नुकसान' पहुंचा रहे हैं। अमेरिकी नेता ने सात अक्टूबर के हमले के बाद हमास के खिलाफ कार्रवाई के इजराइल के अधिकार के प्रति समर्थन जताया लेकिन साथ ही कहा कि नेतन्याहू को 'इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप निर्दोष लोगों की मौत की घटनाओं पर और ध्यान देना चाहिए।' बाइडन कई महीनों से कहते आए हैं कि इजराइल गाजा में बड़ी संख्या में आम नागरिकों की मौत होने के कारण अंतरराष्ट्रीय सहयोग खो सकता है और अमेरिकी समाचार चैनल 'एमएसएनबीसी' के जोनाथन केपहर्ट के साथ हालिया साक्षात्कार में की गई उनकी ताजा टिप्पणी दोनों नेताओं के बीच तनावपूर्ण होते संबंधों की ओर इशारा करती है। बाइडन ने गाजा में लोगों के बड़ी संख्या में मारे जाने पर बात की। उन्होंने कहा, 'इजराइल जिसके लिए प्रतिबद्ध है, यह उसके विपरीत है और मुझे लगता है कि यह एक बड़ी गलती है।' बाइडन ने साथ ही कहा कि वह रॉकेट हमलों से इजराइलियों की रक्षा करने वाले आयरन डोम मिसाइल अवरोधकों जैसे हथियारों की आपूर्ति को नहीं रोकेंगे।

ऑफ बीट

चिंता दूर करने की दवा प्रीगैबलिन से मौत बढ़ी

चिंता-घबराहट की समस्या को दूर करने के लिए आमतौर पर दी जाने वाली दवा प्रीगैबलिन से होने वाली मौतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हाल की प्रेस रिपोर्ट में इन मौतों को 'जीवन को नुकसान पहुंचाने वाली' दवा के कारण होने वाली 'अमेरिकी शैली की ओपिओइड महामारी' के संकेत के रूप में दर्शाया गया है। यह तर्कसंगत तुलना नहीं है, यह देखते हुए कि ओपिओइड (दर्द निवारक दवा) के कारण हजारों अमेरिकियों की मृत्यु हो गई है। ये रिपोर्ट केवल दवा के बारे में अनुचित दहशत पैदा करने का काम कर सकती हैं, खासकर उन लोगों में, जिन्हें डॉक्टरों ने उपयोग करने की सलाह दी है। प्रीगैबलिन (ब्रांड नाम लिरिका और अल्ज़ैन के नाम से भी जाना जाता है) का इस्तेमाल मिर्गी, तंत्रिका संबंधी दर्द और चिंता-घबराहट सहित विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। इस दवा को पहली बार 2004 में यूरोप और अमेरिका में इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई थी। प्रीगैबलिन में लाभकारी गुण हैं और यह उत्साह, शांति और सहज अवस्था की भावनाएं पैदा कर सकता है। ये प्रभाव समझा सकते हैं कि जिन लोगों के पास डॉक्टर का पर्चा नहीं है वे भी प्रीगैबलिन की तलाश क्यों करते हैं।

अपने विचार
हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से **aapkepatra.haribhoomi@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 21

एआई: सक्षम परिवेश पर रहे जोर

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते राष्ट्रीय एआई (आर्टिफिशल इंटेलिजेंस) मिशन के लिए 10,371.92 करोड़ रुपये का पैकेज मंजूर किया था। इस अभियान के तहत देश में कंप्यूटिंग क्षमता तैयार करने पर जोर दिया जाएगा। यह पहले की उन सरकारी घोषणाओं के अनुरूप है जिनमें कहा गया था कि त्रि-स्तरीय कंप्यूटिंग संरचना स्थापित करने पर विचार किया जाएगा। इस मिशन के ब्योरे की बात करें तो अभी तक जो ज्ञात है उसके मुताबिक इसमें निजी क्षेत्र द्वारा उच्च-स्तरीय कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए व्यवहार्यता अंतर का वित्तपोषण शामिल होगा।

प्रासंगिक स्टार्टअप में निवेश के साथ ही शैक्षणिक संस्थानों को अनुसंधान और विकास (आरऐंडडी) में सहयोग के लिए निश्चित राशि भी निर्धारित की गई है। इसमें नए प्लेटफॉर्मों की स्थापना भी शामिल है जो स्वास्थ्य सेवा, कृषि और शासन जैसे क्षेत्रों के लिए प्रमुख भारतीय भाषाओं को कवर करने वाले डेटासेट पर प्रशिक्षित 100 अरब मापदंडों से अधिक क्षमता वाले मूलभूत मॉडल विकसित करेंगे। इसके तहत एआई क्यूरेशन इकाइयों (एसीयू) का भी विकास किया जाएगा। प्रस्ताव में 'एआई मार्केटप्लेस' की स्थापना की बात भी शामिल है, जो एआई को सेवा और पूर्व-प्रशिक्षित मॉडल के रूप में पेश करने के लिए डिजाइन किया गया है। वैसे तो इस क्षेत्र के लिए यह सब उपयोगी और मददगार होगा लेकिन निजी क्षेत्र कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना करने तथा मॉडल एवं बाजार विकसित करने के लिए अपेक्षित निवेश तलाशने में खुद सक्षम है, बशर्ते कि उसे पर्याप्त नीतिगत समर्थन मिले।

एआई जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्र के लिए निवेश जरूर आएगा। वास्तव में, सरकार एआई मिशन की रूपरेखा के मुताबिक महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों के लिए प्रारंभिक वित्तपोषण यानी जरूरी कर्ज या आर्थिक सहयोग से ज्यादा कुछ नहीं दे सकती। इसलिए सरकार को सक्षम वातावरण बनाने पर ज्यादा जोर देना होगा।

एआई के परिवेश को समझदारी वाले, स्पष्ट विनियमन एवं कानून और सक्षम नीति की आवश्यकता है, जिसमें प्रासंगिक हार्डवेयर के आयात के लिए तार्किक सीमा शुल्क और कर नीति, उपकरण के लिए मूल्यह्रास, सॉफ्टवेयर में अनुसंधान एवं विकास के लिए व्यय के दिशानिर्देश, सेमीकंडक्टर जैसे उच्च-स्तरीय उपकरणों के स्थानीय निर्माण को प्रोत्साहित करने पर जोर और एआई परिवेश में निवेशकों के लिए स्पष्ट नीति शामिल हो। इसके अलावा यह देखते हुए कि एआई बड़े पैमाने के डेटा के आधार पर काम करता है, इस क्षेत्र के बढ़ने के साथ-साथ व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत डेटा, दोनों के प्रसंस्करण और भंडारण को बेहतर बनाने की तत्काल आवश्यकता है। ये ऐसी नीतिगत चिंताएं और इनपुट हैं जिनका समाधान केवल सरकार ही कर सकती है। इसलिए जल्द से जल्द इस दिशा में आगे बढ़ना उचित होगा।

इस मिशन में लगभग 10,000 उच्च-स्तरीय ग्राफिक्स प्रोसेसिंग इकाइयों (जीपीयू) की क्षमता स्थापित करने के लिए करीब 4,500 करोड़ रुपये की व्यवहार्यता अंतर के वित्तपोषण की बात की गई है। हालांकि यह आवंटन उच्च-स्तरीय जीपीयू में केवल 1,000 से 1,500 या उसके आसपास की इकाइयों के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त होगा लेकिन जैसे-जैसे व्यापकता बढ़ेगी, लागत कम होती जाएगी।

मौजूदा भारतीय स्टार्टअप तंत्र की जीवंतता और पैमाने को देखते हुए, स्टार्टअप को वित्तपोषित करने के लिए हुए 2,000 करोड़ रुपये के एक और आवंटन को वास्तव में किसी अन्य उद्देश्य के लिए आवंटित किया जा सकता है। हालांकि बड़े मूलभूत मॉडलों में अनुसंधान एवं विकास के लिए इंडियाएआई इनोवेशन रिसर्च सेंटर को 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन और इंडियाएआई डेटासेट प्लेटफॉर्म की स्थापना निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लिए उपयोगी साबित होगी। ये ऐसे खुले बहुपक्षीय मंचों के रूप में काम कर सकते हैं जो कई सार्वजनिक क्षेत्र और निजी संस्थाओं को सहयोग और सेवा प्रदान करते हैं। एआई मिशन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता सराहनीय है और महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करना भी सराहनीय कदम है। इस संदर्भ में देखें तो दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है और भारत को भी पीछे नहीं रहना चाहिए, खासकर इसके अंतर्निहित फायदों को देखते हुए। हालांकि ऊपर उल्लिखित जिन क्षेत्रों की बात हमने की है, उनके बारे में नीति निर्माण महत्त्वपूर्ण है। इसके साथ ही यह भी अहम है कि एआई का विकास और इस्तेमाल एक मजबूत और स्थिर ढांचे के तहत हो। एक बार नीति के मोर्चे पर स्पष्टता आ जाए तो इस क्षेत्र में निवेश जरूर आएगा।

मोदी-भाजपा ने शुरू की 2029 की तैयारी!

शक्तिशाली नेता यह यकीन करते हैं कि वे उम्र और पुरानेपन से पार पा सकते हैं। शी चिनफिंग, जो बाइडन, डॉनल्ड ट्रंप, एर्दोआन और पुतिन ऐसे ही कुछ नाम हैं। मोदी को भी इसमें शामिल कर सकते हैं

राष्ट्र की बात

शेखर गुप्ता

अगर मैं आपसे कहूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गति से यात्राएं कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, आधारशिला रख रहे हैं और देश के अलग-अलग हिस्सों में भाषण दे रहे हैं उससे पता चलता है कि आम चुनावों का प्रचार अभियान शुरू हो चुका है तो आप यकीनन मुझसे कहेंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है? आखिर हम सब जानते हैं कि चुनाव बहुत करीब आ चुके हैं।

यह अच्छा प्रश्न है लेकिन अंतर केवल यह है कि हम 2024 के प्रचार अभियान की बात नहीं कर रहे हैं। उन चुनावों में तो मोदी-शाह की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अपनी जीत सुनिश्चित मान कर चल रही है। हम 2029 के चुनावों के प्रचार अभियान की बात कर रहे हैं। भाजपा के दो दिग्गज नेताओं के बयान इसका प्रमाण हैं।

पहला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दरभंगा में कहा देश से गरीबी मिटाने के लिए मतदाताओं को नरेंद्र मोदी को केवल तीसरे नहीं बल्कि चौथे कार्यकाल के लिए भी चुन लेना चाहिए। उसके बाद गृह मंत्री और भाजपा के प्रमुख रणनीतिकार अमित शाह ने एक मीडिया आयोजन में कहा कि विपक्ष को अब 2034 के बाद के चुनावों की योजना बनानी चाहिए।

इन दोनों बयानों का यही अर्थ निकलता है कि मोदी 2029 में असाधारण रूप से लगातार चौथे कार्यकाल के लिए मैदान में होंगे। अगर आपको यह भ्रम है कि भाजपा में अभी भी 75 वर्ष की उम्र सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्त होने की उम्र है तो ध्यान दीजिए कि 75 वर्षीय हेमा मालिनी को मथुरा से तीसरी बार चुनाव मैदान में उतारा गया है।

अगर आप भाजपा नेताओं से पूछेंगे तो वे कहेंगे, 'आपसे किसने कहा कि उम्र की कोई सीमा है?' चाहे जो भी हो, हेमामालिनी को टिकट मिलना इस बात का साफ संकेत है कि 75 वर्ष की कोई आयु सीमा नहीं है। अगर वह 75 वर्ष की आयु में चुनाव लड़ सकती हैं तो 79 की उम्र में मोदी क्यों नहीं लड़ सकते (2029 में वह 79 वर्ष के होंगे)। उस समय उनकी उम्र जो बाइडन की वर्तमान आयु से दो साल कम और डॉनल्ड ट्रंप की मौजूदा आयु से दो वर्ष अधिक होगी। अगर इस आयु में इनमें से कोई अमेरिकी राष्ट्रपति बन सकता है तो मोदी क्यों नहीं बन सकते?

राजनीति में उम्र की सीमा कब काम करती है? यहां तक कि चीन के कम्युनिस्ट जिन्होंने अपने नेतृत्व को युवा बनाने के लिए सख्त आयु सीमा लागू की है, उन्होंने भी शी चिनफिंग के लिए नियमों को नए सिरे से लिख दिया है।

यहां मैं सन 2007 में आई फिल्म 'जॉनी गद्दार' में धर्मेंद्र के किरदार का उल्लेख करने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं जहां उनका एक साथी आश्चर्यजनक ढंग से कहता है कि वह इतनी अधिक उम्र में 'इतने बुरे' काम कैसे कर लेते हैं। जवाब में धर्मेंद्र कहते हैं कि यह उम्र का नहीं, माइलेज का मामला है।

'माइलेज' वाले नेता मानते हैं कि वे हमेशा पद पर बने रह सकते हैं। शी, बाइडन, ट्रंप, एर्दोआन और पुतिन के उदाहरण सामने हैं और अब तो मोदी को भी इसमें शामिल करने के पूरे प्रमाण मौजूद हैं। 2029 में निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी के चौथे कार्यकाल का प्रचार देखने को मिलेगा।

अमित शाह और राजनाथ सिंह की बातों से भी अधिक प्रमाण इस बात में मिलते हैं कि मोदी फिलहाल कहां और कैसे चुनाव प्रचार कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? तमिलनाडु और केरल में मोदी जितना समय और ऊर्जा लगा रहे हैं वह इसका उदाहरण है।

सभी शंकालु और यहां तक कि द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम के नेता भी दबी जुबान में यह स्वीकार करते हैं कि भले ही भाजपा तमिलनाडु में अपने दम पर कोई सीट नहीं जीत पाए लेकिन उसका मत प्रतिशत बहुत बढ़ेगा। कुछ अनुमानों के मुताबिक तो यह 15 से 17 फीसदी तक हो सकता है। भले ही पार्टी को एक भी सीट नहीं मिले लेकिन इतने वोट 2029 में उसे एक मजबूत दावेदार बनाएंगे।

देश में परिवार संचालित दलों का इतिहास बताता है कि तीसरी पीढ़ी के नेतृत्व संभालने तक सत्ता बहुत हद तक हाथ से निकल जाती है। कांग्रेस के नेहरू-गांधी परिवार से लेकर तमाम परिवारों पर नजर डाली जा सकती है। क्या उदयनिधि के अधीन द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम इसका अपवाद होगी?

अगर भाजपा अन्य परिवार संचालित दलों के प्रदर्शन को ध्यान में रखकर देखती है तो उसे तमिलनाडु में बहुत अधिक गुंजाइश नजर आती है। खासतौर पर द्रमुकवाद की दूसरी दावेदार अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक पहले से ही बंटी हुई है और सहारे से टिकी हुई है।

द्रमुक पर यकीन करने वाले कहते हैं कि वह केवल एक परिवार नहीं बल्कि एक विचारधारा है जिस पर उन्हें यकीन है कि वह किसी भी व्यक्ति से परे है। बहरहाल, वास्तव में भारतीय राजनीति में अब तक यह कारगर नहीं रहा है। विचारधारा को भूल जाइए। हमारे यहां तो धर्म भी परिवार आधारित पराभव को रोकने में नाकाम रहा है।

शिरोमणि अकाली दल का उदाहरण हमारे सामने है। यह देश का इकलौता पूरी तरह धर्म आधारित दल है। इसके संविधान के मुताबिक इस पार्टी का अध्यक्ष किसी अमृतधारी सिख का होना अनिवार्य है। दूसरी पीढ़ी के तहत इसके अतीत और वर्तमान की तुलना करें तो पता चलता है कि परिवार आधारित होने के बाद इसमें कितनी गिरावट आई है। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि मोदी क्यों 2029 में एक बार फिर शीर्ष पद के दावेदार होंगे।

केरल में उनके लिए और अवसर दे रहा है। भाजपा राज्य के ईसाइयों तक लगातार पहुंच बना रही है। वे कांग्रेसनीत संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधन के प्रतिबद्ध मतदाता रहे हैं। इस गठबंधन के अन्य मतदाता वर्ग यानी मुस्लिमों और ईसाइयों के बीच पुराने समय से शकोशुबहा रहे हैं।

अगर कुछ ईसाई भाजपा के खेमे में चले जाते हैं और कांग्रेस का पराभव देखकर मुस्लिम वाम मोर्चे की ओर चले जाते हैं तो भाजपा के पास बहुत अवसर होंगे। मोदी अभी इसी प्रत्याशा में प्रचार कर रहे हैं और उन नेताओं को शामिल कर रहे हैं जो कांग्रेस में हो सकते थे। उदाहरण के लिए कांग्रेस के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ए के एंटनी और के करुणाकरन के बेटे और बेटी। 2029 में केरल के लिए यही उनका प्रचार अभियान है। अगर भाजपा के तेजी से गठबंधन करने के सिलसिले पर नजर डालें तो एक दीर्घकालिक रुझान नजर आता है। आज भाजपा बहुत सावधानी से ऐसे साझेदार चुन रही है जो पहले से ही पराभव की ओर अग्रसर हैं, जो बहुत मोलभाव करने की स्थिति में नहीं हैं और जिनकी जगह भरने का काम भाजपा कर सकती है।

असम में भाजपा ने 2016 का चुनाव असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के साथ साझेदारी में जीता। बाद में हुए बोडोलैंड ट्राइबल काउंसिल के चुनावों में उसने बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट का साथ छोड़ दिया और प्रमोद बोरो की युनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के साथ गठबंधन कर लिया। 2022 में अत्यधिक कमजोर हो चुका बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट दोबारा भाजपा के साथ आ गया। असम गण परिषद भी अपने मूल कद की छाया मात्र बची है।

बिहार में भी ऐसा ही किया गया। भाजपा ने चिराग पासवान का इस्तेमाल नीतीश कुमार को कमजोर करने में किया। याद कीजिए खुद को मोदीजी का हनुमान कहने वाले चिराग ने जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए थे। जब पार्टी जनता दल यूनाइटेड के सांसदों को तोड़ने के लिए प्रयासरत थी तो नीतीश के पास भाजपा के साथ वापस आने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा था। आप कल्पना कर सकते हैं कि 2029 तक जनता दल यूनाइटेड की स्थिति क्या होगी?

आंध्र प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र हर जगह भाजपा स्थानीय साझेदारों के साथ ऐसा ही कर रही है। तेलुगू देशम पार्टी कमजोर होती जा रही है, दुष्यंत चौटाला की पार्टी लगभग समाप्त हो चुकी है शिव सेना बंट चुकी है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नए घटक का भाजपा के बिना कोई अस्तित्व नहीं है।

अगर इन बातों को मिलाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि हम क्यों कह रहे हैं कि मोदी और भाजपा ने 2029 का प्रचार शुरू कर दिया है। विपक्ष क्या कर सकता है? इस बारे में हम आने वाले सप्ताहों में बात करेंगे।

कृषि क्षेत्र में तौर-तरीके बदलने की आवश्यकता

जमीनी हकीकत

सुनीता नारायण

दुनिया की कृषि व्यवस्था में बुनियादी स्तर पर कुछ न कुछ कमी है। जब आप यूरोप के आर्थिक रूप से संपन्न किसानों की तस्वीरें और भारत में अपनी नाराजगी सरकार तक पहुंचाने के लिए ट्रैक्टरों के साथ सड़क जाम करते किसानों को देखते हैं तो खामियों की बात साफ हो जाती है। वास्तविकता यह है कि ये सभी किसान दुनिया में कृषि उत्पादन पर बढ़ी लागत और जलवायु परिवर्तन से होने वाले गंभीर खतरों का सामना कर रहे हैं।

दुर्भाग्य से यूरोप में विवाद की जड़ जलवायु परिवर्तन से जुड़े कानून हैं। इन नए नियमों के अनुसार किसानों को कीटनाशकों का इस्तेमाल घटाकर आधा और उर्वरकों का उपयोग भी 20 प्रतिशत तक करने के लिए कहा गया है। नए नियमों के तहत उन्हें जैविक उत्पादन में इजाफा करना होगा और जैव-विविधता संरक्षण के लिए गैर-कृषि कार्यों हेतु अधिक भूमि छोड़नी होगी। इसके अलावा नीदरलैंड्स ने नाइट्रोजन प्रदूषण कम करने के लिए मवेशियों की संख्या कम करने का प्रस्ताव दिया है और जर्मनी को जीवाश्म ईंधन डीजल पर सब्सिडी कम करनी है। ये सभी उपाय इसलिए जरूरी तौर पर करने होंगे क्योंकि दुनिया जलवायु परिवर्तन के खतरों से जूझ रही है। यूरोपीय संघ (ईयू) ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का बड़ा स्रोत है। उसके सालाना उत्सर्जन का 10 वां हिस्सा ग्रीन गैसें होती हैं। भारतीयों की तुलना में यूरोप के अधिक संपन्न किसान जब कृषि क्षेत्र में बढ़ रहीं चुनौतियों से परेशान हैं तो भारत के किसानों का क्या हाल होगा जो अस्तित्व से जूझ रहे हैं?

वास्तविकता यह है कि दुनिया में आधुनिक कृषि का प्रतीक मानी जाने वाली यूरोपीय कृषि प्रणाली सब्सिडी की बदौलत ही अब तक अपना अस्तित्व बचाती आई है। वर्ष 1962 से ही यूरोपीय संघ की साझी कृषि नीति (सीएपी) ने कृषि को वित्तीय समर्थन मुहैया कराया है। इसकी आलोचना भी खूब होती रही जिसके बाद यह सब्सिडी थोड़ी कम की गई। वर्तमान में सीएपी यूरोपीय संघ के बजट का लगभग 40 प्रतिशत है और इसके तहत किसानों को सीधे सब्सिडी दी जाती है। यूरोपीय आयोग के आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक किसान को सीधे आय समर्थन के रूप में 2021 में सालाना 6,700 यूरो (लगभग 50,000 रुपये प्रति महीने) दिए गए। इसके अलावा यूरोपीय संघ में कृषि को बढ़ावा देने के लिए अधिक निवेश किए जाते हैं।

पिछले कई वर्षों के दौरान कृषि कार्यों के तरीकों में बदलाव आए हैं और खेतों का आकार-बड़ा और अधिक संगठित हो गया है। लागत बढ़ने, ऊंचे मानकों और ढुलमुल सरकारी तंत्र के कारण छोटे किसान या छोटे स्तर पर इन कार्यों में लगे लोग छटपटा रहे हैं। बड़े किसान भी ऋणों के बोझ से परेशान हैं क्योंकि इन दिनों खेती करने की लागत काफी बढ़ गई है। जैविक खेती का चलन उत्पादन खर्च बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। इस समय यूरोपीय संघ में 10 प्रतिशत भूमि पर जैविक खेती हो रही है। किसान बढ़ी लागत का जवाब दूसरे रूप में दे रहे हैं और फसलों एवं दूध आदि का उत्पादन बढ़ाने के लिए वे सभी तरह के उपाय आजमा रहे हैं। अधिक उत्पादन के चक्कर में रसायन और जैव-सामग्री (बायो-इनपुट) का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है। मगर इससे बदलते मौसम एवं जलवायु परिवर्तन के खतरों के बीच कृषि कार्यों की लागत और ज्यादा बढ़ गई है।

लागत में इस बढ़ोतरी को दो वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है। इसमें पहली चुनौती है खाद्य पदार्थों की कीमतें नियंत्रण में रखना और दूसरी चुनौती है जलवायु परिवर्तन के संकट के कारण फसलों को तेजी से होने वाला नुकसान। अंधाधुंध और अधिक से अधिक उत्पादन पाने का चलन बढ़ता ही जा रहा है। यह माना जाता है कि इस चलन को जारी रखते हुए पर्यावरण भी सुरक्षित रखा जा सकता है और किसान उत्पादन बढ़ाकर अपना मुनाफा भी बढ़ा सकते हैं। मगर साफ है कि मामला उतना सीधा भी नहीं है जितना समझा जा रहा है। पश्चिमी देशों में भी अनाज सस्ता नहीं रह गया है।

दिल्ली की दहलीज पर प्रदर्शन करने वाले किसान अपने कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की मांग कर रहे हैं। इन किसानों के सामने भी वही संकट है जिनका सामना पश्चिमी देशों के किसान कर रहे हैं। फर्क केवल इतना है कि भारत में किसानों को फसल उत्पादन के लिए भारी भरकम सब्सिडी नहीं दी जा रही है। इसके बाद दूसरी समस्या है। सरकार को अनाज वितरण के लिए अनाज खरीदना पड़ता है। इसलिए उसे कीमतें नियंत्रण में रखनी पड़ती है। उपभोक्ता (हम सभी लोग) खाद्य महंगाई की मार से बचना चाहते हैं।

किसान ऊंची लागत और बदलते मौसम एवं कीटों के आक्रमण के बीच असहज महसूस कर रहे हैं। उनके लिए इससे भी बड़ी चुनौती यह है कि खाद्य पदार्थों की कीमतें जब भी बढ़ती हैं तो यह किसानों के लिए मुनाफा कमाने का एक अवसर होता है। मगर सरकार आयात के जरिये कीमतें नियंत्रित करने का विकल्प खोज लेती है। इस तरह किसानों को नुकसान उठाना पड़ जाता है। इसके बाद किसान मृदा, जल या जैव-विविधता में सुधार के लिए निवेश करने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं।

अब किसानों को यह समझाया जा रहा है कि मुनाफा बढ़ाने के लिए उन्हें उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। मगर कृषि कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री महंगी होने से अधिक उत्पादन करने पर खर्च भी बढ़ता जा रहा है। उत्पादन का यह गणित अर्थहीन हो जाता है क्योंकि ऊंची लागत के लिए भारत जैसे देश में कोई मदद नहीं दी जा सकती जहां लोगों को सस्ती दरों पर अनाज मुहैया कराना सरकार के लिए जरूरी है।

यह स्पष्ट है कि भारत सरकार यूरोपीय देशों की तरह तो एक-एक किसान को सब्सिडी नहीं दे सकती है। यह बात भी स्पष्ट है कि येन-केन प्रकारेण उत्पादन बढ़ाने के बीच वित्तीय समर्थन भी पर्याप्त नहीं होगा। इस तरह हमें अब इस बात पर चर्चा करनी होगी कि उत्पादन लागत कैसे कम की जाए और किसानों को उनकी मेहनत का फल मिल जाए। इन परिस्थितियों में पुनर्योजी या प्राकृतिक कृषि बड़ी भूमिका निभाएगी। मगर इसे बड़े पैमाने पर करना होगा और इसके लिए ठोस नीतियां भी तैयार करनी होंगी। इनके अलावा वृहद कार्य प्रणाली और वैज्ञानिक विधियों की भी जरूरत होगी। स्थानीय स्तर पर काम करने के लिए हमें खाद्य-क्रय नीतियों की भी जरूरत है ताकि किसानों को गुणवत्तापूर्ण फसलों के लिए अच्छी रकम मिल सके। मध्याह्न भोजन के लिए मोटे अनाज खरीदने की ओडिशा सरकार की योजना इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। सच्चाई यह है कि दुनिया में लोगों का पेट भरने के लिए अनाज की कमी नहीं है मगर समस्या यह है कि इनका काफी हिस्सा मवेशियों को खिलाने में इस्तेमाल होता है या बेकार हो जाता है। हमें इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

(लेखिका सेंटर फॉर साइंस ऐंड एन्वॉयरनमेंट से संबद्ध हैं)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

आपका पक्ष

देश में एमएसपी की अब दरकार नहीं

भारत में कृषि अर्थव्यवस्था के जानकारों और विश्लेषकों का कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 1960 के दशक का विचार है, जब देश अनाज की भारी कमी की समस्या से जूझ रहा था। उस वक्त सरकार ने किसानों को ज्यादा फसल पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के कदम के तौर एमएसपी की व्यवस्था लागू की थी। अब 'फूड सरप्लस' का दौर है और एमएसपी की जरूरत खत्म हो गई है। पहली एमएसपी 1964-65 में धान के लिए दी गई थी। उस वक्त धान की प्रति क्विंटल एमएसपी 33.50 रुपये से लेकर 39 रुपये तय की गई थी। वहीं 1966-67 में गेहूं के लिए प्रति क्विंटल 54 रुपये की एमएसपी दी गई थी। विश्लेषकों का कहना है कि देश अब खाद्य सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। इसलिए इसकी भूमिका खत्म हो चुकी है। यह व्यवस्था हमेशा के लिए नहीं चल सकती है।

किसानों को धान-गेहूं की फसल की बजाय ज्यादा कीमत देने वाली फसलों को पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए

सरकार की ओर से 23 फसलों की एमएसपी पर खरीद की अनिवार्यता के बावजूद सिर्फ गेहूं और धान की खरीद ही इस पर हो रही है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 से पहले तीन साल तक देश में एमएसपी की व्यवस्था के तहत 1,340 लाख टन अनाज खरीदा जा चुका था। इस पर सरकार 2.75 लाख करोड़ रुपये खर्च कर चुकी थी। देश में जरूरत से ज्यादा अनाज का भंडार है और रखने की जगह की कमी के कारण बड़ी मात्रा में अनाज खराब हो जाता है। कुल मिलाकर एमएसपी की कानूनी गारंटी किसानों का अहित करेगी। अगर स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक फसलों के दाम बढ़ेंगे तो खाद्य वस्तुओं के दाम 25 से 30 फीसदी बढ़ जाएंगे और सरकार के लिए महंगाई नियंत्रण बेहद कठिन हो जाएगा। किसानों की आय बढ़ाने के कई उपाय हो सकते हैं। इसमें एक है मूल्य स्थिरता कोष का गठन यानी जब फसलों की बाजार कीमत एमएसपी से नीचे चली जाए तो सरकार इसकी भरपाई करे। चीन में यह व्यवस्था कारगर है। किसानों को धान-गेहूं की फसल की बजाय ज्यादा कीमत देने वाली फसलों को पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। किसानों को फल, सब्जी, मवेशी और मछली पालन के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

पेट्रोल के दाम कम हों

महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृहिणियों को रसोई गैस की कीमत 100 रुपये कम करने की घोषणा के साथ ही उन्हें तोहफा दिया है। अगले कुछ दिनों में लोक सभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले ही सरकार ने रसोई गैस के दाम कम कर लोगों को राहत प्रदान की है। सरकार को पेट्रोल-डीजल तथा सीएनजी की कीमत कम करने पर भी विचार करना चाहए। पिछले कुछ वर्षों से पेट्रोल के दाम लगभग 100 रुपये प्रति लीटर चल रहे हैं जबकि सरकार ने यह दावा किया था कि पेट्रोल की कीमत हर दिन वैश्विक बाजार की कीमतों के अनुरूप होगी। अतः सरकार को पेट्रोल-डीजल के दाम कम कर लोगों को राहत प्रदान करना चाहिए।

मोहित कुमार, नई दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना ने पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त तटरक्षक अभ्यास कार्यक्रम 'सी डिफेंडर्स-2024' में हिस्सा लिया।

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

टेस्ट क्रिकेट को हरा-भरा रखने की सार्थक पहल

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) ने ऐसे खिलाड़ियों की मैच फीस 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 45 लाख रुपए करने का फैसला किया है, जो हर सीजन में कम से कम सात टेस्ट मैच खेलेंगे। इन्हें 4.5 करोड़ रुपए की मोटी रकम मिलेगी जो एक सीजन में 10 टेस्ट मैचों में हिस्सा लेंगे। भारत में टेस्ट क्रिकेट को प्रोत्साहन के लिए यह सार्थक पहल है। ज्यादातर क्रिकेट विशेषज्ञ इस खेल के तीनों प्रारूपों (टेस्ट, 50-50, टी-20) में टेस्ट को असली क्रिकेट मानते हैं। उनके मुताबिक क्रिकेट की तमाम तकनीकी खूबियां टेस्ट मैच में ही देखने को मिलती हैं। पांच दिन का यह प्रारूप खिलाड़ियों का धैर्य, एकाग्रता से लेकर मैदान में लंबे समय तक जूझने के जज्बे तक, सब कुछ 'टेस्ट' करता है।

पहले वनडे (50-50) और उसके बाद टी-20 के रूप में रंग-बिरंगे फटाफट क्रिकेट की शुरुआत ने 147 वर्ष से खेले जा रहे टेस्ट क्रिकेट की लोकप्रियता पर आई आंच से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) के माथे पर भी बल पड़े हुए हैं। क्रिकेट की यह ऐतिहासिक विरासत अब इसके ज्यादातर शेयरधारकों के लिए घाटे का खेल साबित हो रही है। वनडे और टी-20 के मुकाबले मैदान में इसके दर्शक भी घट रहे हैं और प्रायोजक भी। टेस्ट मैचों के शेयरधारक घाटे की भरपाई के लिए वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट्स से जुड़ रहे हैं। भारत में भी टेस्ट मैचों की कमोबेश यही हालत है। तेज रफ्तार जीवन शैली के कारण क्रिकेट प्रेमियों को वनडे और टी-20 ज्यादा रोमांचित कर रहे हैं, जहां कुछ ही घंटों में फैसला हो जाता है। पिछले दिनों चिंताजनक पहलू यह उभरा कि कुछ भारतीय खिलाड़ी सिर्फ इसलिए भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं बने, क्योंकि उन्हें आइपीएल की तैयारी करनी थी। अपने देश के लिए खेलना हर खिलाड़ी का कर्त्तव्य है। कोई भी फ्रेंचाइजी क्रिकेट, भले वह आइपीएल हो, इससे ऊपर नहीं हो सकता। आइपीएल में ज्यादा धन मिलता है, इसलिए नेशनल टीम का हिस्सा बनने के बजाय कुछ खिलाड़ी इसे ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्र ने ही क्रिकेट में उनके सितारे बुलंद किए हैं।

टेस्ट मैच खेलने से इनकार करने वाले दो खिलाड़ियों का नाम सालाना रिटेनर्स की लिस्ट में शामिल नहीं कर बीसीसीआइ पहले ही संदेश दे चुका है कि राष्ट्रीय कर्त्तव्य के मोर्चे पर आनाकानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब रेड बॉल (टेस्ट) और फ्रेंचाइजी क्रिकेट के बीच धन के अंतर को कम कर उसने स्पष्ट कर दिया है कि वह पांच दिन के क्रिकेट को हरा-भरा रखने के प्रति गंभीर है। मुमकिन है इसके लिए कुछ और कदम उठाए जाएं।

मीडिया : पीड़ितों और वंचितों की आवाज बनने की निभानी होगी जिम्मेदारी

संवेदना और सामाजिक सरोकार के बिना पत्रकारिता की सार्थकता नहीं

विजयदत्त श्रीधर
संस्थापक-संयोजक, सप्रे संग्रहालय, भोपाल
@patrika.com

आज का समय सूचना-संचार का है। अधुनातन संचार प्रौद्योगिकी ने सूचना के माध्यमों को बहुआयामी बनाया है। पहले जहां समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के रूप में मुद्रित माध्यम अस्तित्व और व्यवहार में थे ; बीसवीं शताब्दी में पहले रेडियो और फिर टेलीविजन अर्थात दृश्य-श्रव्य माध्यमों का प्रचलन हुआ। रेडियो से सूचनाएं ग्रहण करने में साक्षरता जैसी अनिवार्यता भी नहीं रही। सुनना ही काफी होता है। फिर टेलीविजन आया। इस माध्यम में पढ़ने और सुनने के साथ-साथ देखने की भी सुविधा मिली। माना गया कि देखे हुए का प्रभाव अधिक होता है। कालांतर में सोशल मीडिया के विविध आयामों ने संस्थागत सूचना-संचार से परे व्यक्तिगत स्तर पर अभिव्यक्ति का अवसर सर्वसाधारण के लिए सुलभ करा दिया। अब यदि समाचारपत्र और रेडियो-टेलीविजन यदि किसी घटना-प्रसंग, अन्याय-अनाचार-अत्याचार की सूचनाओं को अपेक्षित महत्त्व नहीं देते हैं अथवा सही-सही पाठकों तक नहीं पहुंचाते हैं, तो सोशल मीडिया- ट्विटर (एक्स), फेसबुक, वाट्सएप, एस.एम.एस, पॉडकास्ट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि कोई न कोई माध्यम उसे जग-जाहिर कर देता है। इसके बावजूद संस्थागत और व्यक्ति गत माध्यमों में एक बुनियादी फर्क होता है। संस्थागत माध्यम नियम-कानून-मर्यादा से बंधे होते हैं, जबकि व्यक्ति गत माध्यमों के नियमन की कोई व्यवस्था नहीं है।

यहां एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि क्या पत्रकारिता अन्य उद्योगों-व्यवसायों की तरह कोई उद्यम होती है? क्या समाचार माध्यमों को उत्पाद के रूप में स्वीकार किया जा सकता है? क्या समाचार माध्यमों को सिर्फ लाभ-हानि की चौखट में कसा जा सकता है? क्या समाचार माध्यमों को किसी एक परिभाषा में बांधा जा सकता है? दूसरा सवाल यह उठता है कि संविधान में प्रेस के लिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जैसा कोई प्रावधान नहीं है। फिर प्रेस को यह मान्यता क्यों दी जाती है? दरअसल, भारत में पत्रकारिता का विकास नवजागरण आंदोलन के साथ-साथ हुआ है। दोनों की चिंताएं और प्राथमिकताएं समान रही हैं। दोनों ने अपने चिंतन और कर्त्तव्य निर्वाह के कारण अवरोध, प्रताड़नाएं और मुसीबतें झेली हैं। यही कारण है कि जन-मानस में प्रेस के प्रति लोकप्रहरी और लोकशिक्षक की अवधारणा बनी। इसकी सबसे जरूरी शर्त लोक विश्वास है। निस्संदेह प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब मीडिया,

> मानव हृदय और मस्तिष्क संवेदनाओं से युक्त होते हैं। इनका स्थान प्रौद्योगिकी कदापि नहीं ले सकती।

सोशल मीडिया के क्षेत्र में असाधारण तकनीकी प्रगति हुई है। नई सज-धज आई है। कलेवर बदला है। लेकिन इससे मीडिया में पूंजी का दखल और दबाव भी बढ़ा है। साधन, साध्य पर हावी हो गया है। नेता-अभिनेता-क्राइम-क्रिकेट-सिनेमा-सनसनी पर जोर है। वही बेचो जो भरमाता है, लुभाता है, ललचाता है। मीडिया का सबसे ज्यादा समय और स्थान तो राजनीति खा जाती है। इस वातावरण में सामाजिक सरोकारों और मानवीय संवेदनाओं के लिए गुंजाइश कहां?

अब माना जाने लगा है कि पत्रकारिता का प्रभाव बढ़ा है, प्रतिष्ठा घटी है। विस्तार हुआ है तो स्खलन भी हुआ है। गुणवत्ता खोई है, संपन्नता पाई है। नाटकीयता और सनसनी ने विश्वसनीयता का संकट उपजाया है। साहित्य और संस्कृति से दूरी ने भाषा को विकृत किया है। संपादक की संस्था का अवमूल्यन हुआ है, जबकि अच्छे पत्र या पत्रिका को संपादक और पाठक का साझा बौद्धिक पराक्रम माना जाता है। टेलीविजन मीडिया में बरती जा रही अति नाटकीयता ने उसे सवालिया निशानों से घेरा है। सोशल मीडिया की पहुंच तो खूब है, परंतु गंभीरता का अभाव झलकता है।

इन मुद्दों का तात्पर्य यह कतई नहीं कि मिशन का जो भाव स्वतंत्रता-पूर्व की भारतीय भाषायी पत्रकारिता में कमोबेश रहा है, वही प्रेस का स्थायी भाव रहे। समय के साथ चीजें बदलती हैं। जरूरतें, आशाएं, अपेक्षाएं बदलती हैं। उसी के अनुरूप पत्रकारिता के तेवर बदलते हैं। समाज के सामने जैसी परिस्थितियां आती हैं, उन्हीं के अनुसार पत्रकारिता की प्राथमिकताएं भी बदलती हैं। यह मानी हुई बात है कि जब हमारे सामने परिस्थितियां कठिन और चुनौतियां विकट होती हैं, तब हमारा सर्वश्रेष्ठ सामने आता है। इसका कारण भी है। पत्रकारिता से दिव्यांग की लाठी, मूक की वाणी और नेत्रहीन की ज्योति बनने की अपेक्षा की जाती है। समाज में अधिकांश लोग अपनी आवाज स्वयं नहीं उठा सकते। पत्रकारिता को उनकी आवाज बनना होता है। सरोकारों और संवेदनाओं का यही तकाजा होता है। मानव हृदय और मस्तिष्क संवेदनाओं से युक्त होते हैं। इनका स्थान मशीनें और प्रौद्योगिकी कदापि नहीं ले सकते। यहां हमें बाजार को भी ठीक-ठीक संदर्भ में समझना होगा। बाजार सदैव से समाज का हिस्सा रहे हैं और रहेंगे, परंतु सेवक और सहायक के रूप में ही बाजार की सहज स्वीकार्यता है। स्वामी की भूमिका में बाजार सामाजिक संकट का कारण बनने लगते हैं।

भारत ऐसा विचित्र देश है जिसमें एक साथ दो देश बसते हैं- भारत और इंडिया। यह प्रकट तथ्य है कि 'इंडिया' का वर्चस्व 'भारत' का शोषण करने वाला है। विकास का प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बिठाया जाता। जल, जंगल, जमीन, कृषि उपेक्षा के शिकार हैं। शिक्षा और चिकित्सा बाजार के हवाले हो रहे हैं। पत्रकारिता की दृष्टि से ये मूलभूत मुद्दे प्राय: ओझल हैं। जाहिर है, प्रौद्योगिकी और पूंजी पत्रकारिता में विचारशीलता का अभाव पैदा कर रही हैं। तब सार्थक पत्रकारिता कैसे संभव है?

मुद्दा : सर्विस सेक्टर में इंजीनियरों की बढ़ती मांग

सर्विस इंजीनियरिंग के रूप में नया विषय है वर्तमान समय की मांग

मिलिंद कुमार शर्मा
प्रोफेसर, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग विभाग, एमबीएम विश्वविद्यालय, जोधपुर

शरद शर्मा
सीनियर एसोसिएट डायरेक्टर, केपीएमजी, गुडगांव

@patrika.com

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भारत के विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के स्वप्न को पूर्ण करने में सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर की प्रमुख भूमिका होगी। दुनिया भर में एवं विशेषत: भारत में यह देखना रोचक है कि सेवा क्षेत्र में मध्यम एवं उच्चस्तरीय कार्यों के लिए इंजीनियरिंग स्नातकों को रोजगार के लिए प्राथमिकता मिल रही है। आकर्षक वेतन भत्तों एवं सेवा शर्तों के माध्यम से इंजीनियर स्नातकों को सेवा के लिए विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संगठनों द्वारा लुभाया जा रहा है।

पेशेवर इंजीनियर भी आकर्षक करियर को देखते हुए अपने मूल विषयों की विशेष योग्यता धारण करने के बावजूद सेवा क्षेत्रों के रोजगार को उत्साहपूर्वक चुन रहे हैं। इस क्षेत्र की विविधतापरक प्रकृति एवं तेजी से होती विकास दर ने प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के विद्यार्थियों को भी अपने मूल विषय से इतर सेवा क्षेत्रों की नौकरियों की ओर आकर्षित किया है। टियर-2 एवं टियर-3 स्तर के निजी एवं सरकारी तकनीकी संस्थानों में भी कैम्पस प्लेसमेंट के लिए सेवा क्षेत्र की कंपनियों की संख्या में उत्तरोत्तर प्रगति देखी जा सकती है। इंजीनियरिंग स्नातकों को उनकी तार्किकता, रचनात्मकता, विश्लेषणात्मक कौशल, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, अंग्रेजी एवं कंप्यूटर ज्ञान में अच्छी पकड़ आदि सॉफ्ट स्किल योग्यताओं के कारण अन्य स्नातकों की अपेक्षा सेवा क्षेत्र के रोजगारों के लिए अधिक योग्य माना जाता है। आपूर्ति शृंखला जैसे व्यवसायों की कई परिस्थितियों में इंजीनियरिंग स्नातकों को अपने समकक्ष प्रबंधकीय स्नातकों से श्रेयस्कर प्रदर्शन करते हुए भी देखा गया है। किंतु एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में मात्र 57 प्रतिशत इंजीनियरिंग स्नातक ही रोजगार योग्य पाए गए हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के तकनीकी संस्थानों में इंजीनियरिंग सीटों की कुल उपलब्ध संख्या का 60 प्रतिशत ही भर पा रहा है। एक अन्य औद्योगिक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 80 प्रतिशत स्नातक इंजीनियर गैर तकनीकी क्षेत्रों को रोजगार के लिए चुन रहें हैं। इसके पीछे सेवा क्षेत्र के रोजगारों का तीव्र गति से विस्तार होना भी एक महत्वपूर्ण कारण है। इन सभी बातों के मध्य आवश्यकता इस बात की है जब स्नातक इंजीनियर अपनी मूल विषय के इतर सेवा के विभिन्न क्षेत्रों यथा वित्त, उपभोक्ता सेवा, विपणन

> इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की तुलना में सेवा क्षेत्र के पाठ्यक्रमों की शुरुआत एवं संचालन अपेक्षाकृत कम निवेश वाला भी होगा। इसके लिए बड़ी प्रयोगशालाओं एवं तकनीकी वर्कशॉप की आवश्यक नहीं होगी।

में कार्य करते हुए एक सफल करियर बना सकते हैं। फिर क्यों नहीं सेवा क्षेत्र की चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए इंजीनियरिंग के एक विशेष विषय का पाठ्यक्रम तकनीकी संस्थानों द्वारा चलाया जाए जो सेवा क्षेत्र के लिए योग्य पेशेवर तैयार कर सके। इंजीनियरिंग स्नातकों को सेवा विशेष में कार्य करने को आवश्यक प्रशिक्षण के लिए व्यापारिक संगठनों को अपेक्षाकृत अधिक समय ऊर्जा एवं संसाधन निवेश करने होते हैं। साथ ही इस प्रकार प्रशिक्षित हुए स्नातक इंजीनियरों को सेवा विशेष में आवश्यक स्तर तक आने में भी कुछ समय लगता है। किंतु जब सेवा क्षेत्र के लिए तैयार किए गए पाठ्यक्रम उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रारंभ किए जाएंगे तो निश्चित रूप से इस प्रकार के पाठ्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षित हुए विद्यार्थी सेवा क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम समय में सेवा विशेष के लिए स्वयं का अनुकूलन कर पाएंगे। वर्तमान परिदृश्य में सेवा क्षेत्र से सम्बंधित पाठ्यक्रम बड़े शहरों के कुछ चुनिन्दा शिक्षण संस्थाओं में चल रहें हैं। किंतु वर्तमान परिस्थिति में सेवा क्षेत्र के लिए सामान्य पाठ्यक्रम शिक्षण संस्थाओं में प्रारंभ करने की आवश्यकता है, जो छात्र-छात्राओं को सेवा क्षेत्र के लिए वांछनीय तकनीकी ज्ञान, सॉफ्ट स्किल एवं उद्योग परक योग्यता प्रदान कर सके। जिस प्रकार तकनीकी पाठ्यक्रम विद्यार्थियों में उद्योग जगत के लिए आवश्यक कौशल आधारित वोकेशनल प्रशिक्षण प्रदान करते है, उसी प्रकार सेवा क्षेत्र के पाठ्यक्रम विद्यार्थियों में वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप व्यापारिक ज्ञान के साथ साथ आवश्यक कंप्यूटर ट्रेनिंग एवं आधुनिकतम तकनीकें यथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्टरनेट ऑफ थिंग्स आदि सम्मिलित कर फिनटेक एवं एडुटेक क्षेत्रों के लिए योग्य पेशेवरों की फौज तैयार की जा सकती है जिससे भारत के साथ-साथ विदेशों में भी रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। नई प्रबंधकीय तकनीकें यथा लीन-सिक्स-सिग्मा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, वैल्यू इंजीनियरिंग, प्रोसेस मैनेजमेंट इत्यादि सेवा क्षेत्र के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित कर विद्यार्थियों को प्रबंधकीय पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित पेशेवरों की श्रेणी में खड़ा कर सकते हैं। प्रबंधकीय पाठ्यक्रमों एवं कोर ब्रांचों के इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की तुलना में सेवा क्षेत्र के पाठ्यक्रम प्रारंभ करना एवं संचालन अपेक्षाकृत कम निवेश वाला भी होगा क्योंकि इसके आधारभूत ढांचे को खड़ा करने के लिए बड़ी प्रयोगशालाओं एवं तकनीकी वर्कशॉप की आवश्यक नहीं होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अखिल भारतीय तकनीकी परिषद जैसी नीति निर्धारक संस्थाओं को इस दिशा में सोचना चाहिए।

कन्याकुमारी से कश्मीर तक ■ **भाजपा कमल खिलाने के जतन में, राहुल का मुकाबला गठबंधन के दल से ही**

केरल में 'इंडिया' गठबंधन के दल आपस में ठोक रहे ताल

देश का चुनावी मिजाज
लोकसभा चुनाव 2024

अनंत मिश्रा

तमिलनाडु के बाद रुख किया केरल की तरफ। नागरकोइल से तिरुनेलवेली-जामनगर एक्सप्रेस पकड़कर अल्लापुझा के लिए रवाना हुआ। ट्रेन में सवार हुआ तो ध्यान द्रविड़ राजनीति से हटकर मलयालम राजनीति पर टिक गया। ट्रेन की बर्थ पर लेटे-लेटे ख्याल आ रहा था कि पिछले पांच सालों में कितनी बदली होगी केरल की जमीनी राजनीति? कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच हिंसक संघर्ष का साक्षी रहा केरल क्या इस बार भी 'हाथ' और 'हांसिया हथोड़ा' के संघर्ष में ही उलझकर रह जाएगा? या फिर इस तटीय प्रदेश में 'कमल' को खिलने का भी मौका मिलेगा?

केरल

ये सवाल इसलिए सामने आया क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु की तरह तमाम दावों के बावजूद भाजपा केरल में भी खाता नहीं खोल पाई थी। नागरकोइल से चली ट्रेन आधा घंटे में कॉफी, रबर, नारियल उत्पादन के लिए पहचाने जाने वाले केरल में प्रवेश कर गई। ट्रेन में यात्री उतरते-चढ़ते रहे। सोचा क्यों ना बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए। सामने सीट पर बैठे कोल्लम निवासी एस. बालाकृष्णन से परिचय बढ़ाना चाहा। काजू और मसालों के व्यवसाय से जुड़े बालाकृष्णन अपने मोबाइल में व्यस्त थे। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो उनसे केरल की राजनीति के समीकरणों को समझना चाहा। राजनीति में अधिक रुचि नहीं रखने वाले बालाकृष्णन ने अपनी जानकारी के हिसाब से बताया कि मुकाबला इस बार भी कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच ही रहने वाला है। क्या भाजपा को जगह मिलेगी, सवाल पूछा तो बोले- एकाध सीट के अलावा कोई खास चांस नहीं।

ट्रेन तिरुवंतपुरम रुकी तो कई यात्री चढ़े। इनमें से पप्पनमकोडे में रहने वाली शिक्षिका धनलक्ष्मी गणेश भी शामिल थी। बातचीत से लगा कि उनकी हिंदी अच्छी है और राजनीति में रुचि भी। सवाल करने से पहले ही बोल उठीं, इस बार हमारे शहर में मुकाबला रोचक होने वाला है। कांग्रेस के दिग्गज शशि थरूर के सामने भाजपा ने केन्द्रीय मंत्री राजीव चंद्रेशखर को उतारा है। पूछा, किसके चांस ज्यादा लग रहे हैं, जवाब- अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन कोई भी निकल सकता है। बातचीत का सिलसिला होते-होते मेरा गंतव्य अल्लापुझा आ गया। ये वही शहर है जहां चार साल पहले भारत में कोरोना का पहला मामला सामने आया था। कांग्रेस ने पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल को यहां से उतारा है। पिछले चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के ए.एम. आरिफ यहां से विजयी हुए थे। वेणुगोपाल का यहां भाकपा प्रत्याशी से मुकाबला होगा। यूं तो पूरे देश में भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस और वामपंथी दल एक उम्मीदवार उतारने की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन केरल में बात कुछ अलग है। यहां दोनों दल एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ शिद्दत से चुनाव लड़ने के लिए कमर कस रहे हैं। 20 सीटों के लिए होने जा रहे संघर्ष में इस बार भाजपा भी अपना खाता खोलने की तैयारी में जुटी है। यहां धर्मान्तरण भी चुनावी मुद्दा है तो भ्रष्टाचार भी बड़ा मुद्दा है। दूसरे तटीय राज्यों की तरह मछुआरों की समस्याएं भी चर्चा के केन्द्र में है। सबसे अधिक शिक्षित इस राज्य में दूसरे राज्यों की तरह बेरोजगारी की चर्चा आम नहीं है।

केरल के अल्लापुझा में हाउसबोट भी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं।

लोकसभा चुनाव 2019

किस दल को कितनी सीटें मिली

किस दल को कितने मत मिले

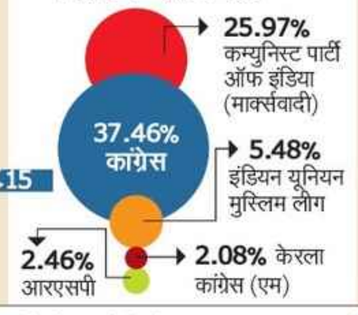

त्रिकोणीय संघर्ष का केन्द्र बनेगा राज्य

दो दिन के प्रवास के दौरान लोगों से हुई बातचीत का सार यही निकलता है कि राज्य इस बार त्रिकोणीय संघर्ष का केन्द्र बनने जा रहा है। पहली पायदान पर कांग्रेस नजर आ रही हैं। वामपंथी मोर्चे की ताकत बढ़ने की पूरी संभावना दिख रही है तो एकाध सीट पर 'भगवा' लहर बन जाए तो आश्चर्य नहीं होगा।

वायनाड: राहुल के मुकाबले राजा

दिल्ली का रास्ता आसान बनाने की जुगत में जुटा 'इंडिया' गठबंधन केरल में कभी एक मंच पर आ नहीं पाया। हालत यह है कि राहुल गांधी की वायनाड सीट पर भाकपा ने एन्नी राजा को उतार मुकाबला रोचक बना दिया है। एन्नी पार्टी महासचिव डी. राजा की पत्नी और पार्टी की पदाधिकारी हैं। यहां 'इंडिया' गठबंधन के दल हर सीट पर एक-दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस और वामपंथी दलों को पता है कि यहां वे एक होकर लड़े तो इसका फायदा भाजपा को मिलना तय है।

थरूर के मुकाबले चंद्रशेखर

पद्मनाभस्वामी मंदिर के शहर तिरुवनंतपुरम में पिछले तीन बार से इस सीट पर जीत रहे कांग्रेस के शशि थरूर के सामने भाजपा ने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को उतार मुकाबला रोचक बना दिया है। 2014 में थरूर भाजपा के खिलाफ कड़े मुकाबले में जीत पाए थे।

फिल्मी सितारों और चर्च का सहारा

राज्य में तीसरी ताकत बनने के प्रयास में जुटी भाजपा चर्च से नजदीकियां बढ़ाकर वोट बैंक मजबूत करना चाह रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पादरियों से मुलाकात कर रहे हैं। पार्टी ने त्रिशूर सीट पर मलयालम अभिनेता सुरेश गोपी को उतारा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे ए.के. एंटनी के पुत्र अनिल एंटनी को पथानामथिट्टा सीट से उतारकर कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के. करूणाकरण की पुत्री पद्मजा वेणुगोपाल को पार्टी में शामिल करना भी भाजपा की सेंधमारी राजनीति का हिस्सा है।

नेतृत्व

संस्थान के विकास में इआइ का महत्व

भावनाएं भी संस्थान की संस्कृति को प्रभावित करती हैं

अमरीकी साइकोलॉजिस्ट और लेखक डैनिएल गोलमैन ने कहा है- 'कौशल के समूह के लिए एक पारंपरिक शब्द है जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रतिनिधित्व करता है- चरित्र।' मैं मानता हूं कि जीवन के रंगमंच में, भावनाएं अदृश्य कलाकार हैं। वे तर्कसंगतता और सहज ज्ञान का प्रतिबिंब हैं। भावनाएं ही हैं जो हमारे मानव विकास की जीवनधारा रही हैं, जो हमारी प्रजाति को बनाए रखती हैं और आगे बढ़ाती हैं। वे हमारे मानस की सूक्ष्म भाषा हैं जिनसे हम अपनी दुनिया को देखते हैं, जो हमारी धारणाएं बनाती हैं और कभी-कभी वस्तुनिष्ठ दुनिया को व्यक्तिपरक रंगों से भर देती हैं।

प्रो. हिमांशु राय
निदेशक, आइआइएम इंदौर
@patrika.com

कार्यस्थलों पर भी भावनाएं संस्थान की संस्कृति, प्रबंधन शैली और यहां तक कि रणनीतिक दिशाओं को ही प्रभावित करती हैं। ऐसे में इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता (इआइ) की अवधारणा सामने आती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता में हमारी अपनी भावनाओं को पहचानने, समझने, प्रबंधित करने और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने और प्रभावित करने की क्षमता होती है। संज्ञात्मकता को मापने वाले इंटेलेक्चुअल कोशियंट (आइक्यू) के विपरीत, भावनात्मक बुद्धिमत्ता भावनाओं के दायरे, हमारे व्यवहार और बातचीत पर उनके प्रभाव को उजागर करती है।

इआइ की शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में हुई, लेकिन 1980 और 1990 के दशक में इस शब्द को प्रमुखता मिलनी शुरू हुई। इस दौरान जीवन के परिणामों को आकार देने में मानव व्यवहार के भावनात्मक पहलुओं की भूमिका को मान्यता मिली। इस आंदोलन के पथप्रदर्शक पीटर सलोवी और जॉन डी. मेयर जैसे मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने पहली बार 1990 में 'इमोशनल इंटेलिजेंस' शब्द गढ़ा था। उन्होंने इआइ को अपनी भावनाओं को समझने, आकलन करने और प्रबंधित करने की क्षमता के रूप में परिभाषित करते हुए मूलभूत ढांचा तैयार किया। हालांकि, यह डैनियल गोलमैन ही थे जिन्होंने इआइ को सुर्खियों में लाकर जन-जन तक पहुंचाया। इमोशनल इंटेलिजेंस पर वर्ष 1995 में प्रकाशित उनकी पुस्तक में कार्यस्थल सहित रोजमर्रा की जिंदगी में इआइ के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है।

आपकी बात

अब भी महंगा है गैस सिलेंडर

रसोई गैस की कीमतों में 100 रुपए की कमी होना पर्याप्त राहत नहीं है। इस घोषणा से आम जनता को कुछ ही मदद मिल सकती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतों में कमी आई है। इसलिए सरकार ने गैस सिलेंडर के भाव घटाए हैं, लेकिन अब भी ये बहुत ज्यादा हैं।

-**ललित महालकरी**, इंदौर, मप्र

महंगाई से त्रस्त है जनता

हर वर्ग पर महंगाई की मार पड़ रही है। सरकार ने पहले तो गरीबों को फ्री गैस कनेक्शन और सस्ते सिलेंडर उपलब्ध करवाए। बाद में इतने महंगे कर दिए कि गांवों में गरीब लोगों ने फिर से कोयले और लकड़ियों से खाना पकाना शुरू दिया। अब सरकार कुछ राहत दे रही है, जो पर्याप्त नहीं है।

-**नूरजहां रंगरेज**, भीलवाड़ा

आज का सवाल

खर्चीली शादियों का समाज पर क्या असर पड़ रहा है?

ईमेल करें
edit@epatrika.com

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की प्रतिक्रियाएं

इसे स्कैन करें

पत्रिकायन का सवाल था, 'क्या रसोई गैस में सौ रुपए की कमी पर्याप्त है ?' इस मुद्दे पर कई प्रतिक्रियाएं आईं। इनमें से कुछ ऑनलाइन भी दी जा रही हैं।

rb.gy/l5y2eh

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक जागरण

नैतिक मूल्यों से विमुख जीवन का कोई औचित्य नहीं

कांग्रेस को एक और आघात

तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने बंगाल की सभी 42 सीटों से जिस तरह अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए और उनकी परेड भी करा दी, वह कांग्रेस और विपक्षी दलों के मोर्चे आइएनडीआइए के लिए एक और झटका है। इसके पहले वाम दलों ने केरल में कांग्रेस को ऐसा ही झटका दिया था। वाम दलों ने तो राहुल गांधी की वायनाड सीट से भी यह कहकर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था कि यदि उन्हें भाजपा का मुकाबला करना है तो वह उत्तर भारत जाकर चुनाव लड़ें। वाम दल बंगाल में तो कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन केरल में इसके लिए तैयार नहीं। बंगाल में वाम दलों की ऐसी हैसियत नहीं कि वे कांग्रेस की कोई बहुत अधिक मदद कर सकें। ममता ने अपने सभी प्रत्याशियों के नाम जारी कर भले ही आइएनडीआइए से अलग होने की घोषणा न की हो, लेकिन बंगाल में अब इस गठजोड़ का कोई महत्व नहीं रह गया है। कांग्रेस का अभी तक उत्तर प्रदेश में सपा और दिल्ली के साथ कुछ और राज्यों की चुनिंदा सीटों पर आम आदमी पार्टी से ही सीटों का तालमेल हो सका है। इन राज्यों में पंजाब नहीं, जहां आम आदमी पार्टी मजबूत है। जम्मू-कश्मीर में भी यह गठबंधन बिखर गया। यह ठीक है कि तमिलनाडु, झारखंड, बिहार आदि में कांग्रेस सहयोगी दलों से मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन ये दल पहले से ही उसके साथ रहे हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना से तालमेल बने रहने के आसार तो दिख रहे हैं, लेकिन वहां सीटों के बंटवारे को लेकर तनातनी बढ़ती जा रही है।

पिछले वर्ष जुलाई में जब आइएनडीआइए का गठन हुआ था तो यह लगा था कि भाजपा को चुनौती देने वाले एक मजबूत गठजोड़ ने आकार ले लिया है, लेकिन कांग्रेस की सुस्ती और सहयोगी दलों के अपनी राजनीतिक जमीन न छोड़ने वाले रवैये के चलते वह आगे नहीं बढ़ सका। वह तब कमजोर और बिखरा हुआ दिखने लगा, जब पहले नीतीश कुमार और फिर जयन्त चौधरी ने उसका साथ छोड़ दिया। इसमें संदेह नहीं कि वाम दलों और तृणमूल कांग्रेस ने इस गठबंधन को और कमजोर करने एवं कांग्रेस की समस्या बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के समक्ष एक संकट यह भी है कि उसके नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला कायम है। इससे अच्छा संदेश नहीं जा रहा है, क्योंकि ऐसे अधिकांश नेता भाजपा में जा रहे हैं। कांग्रेस के साथ आइएनडीआइए के कमजोर दिखने के लिए एक बड़ी हद तक उसके रणनीतिकार ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने अपने गठबंधन को मजबूती देने और सहयोगी दलों से सामंजस्य बैठाने के लिए वैसे जतन नहीं किए, जैसे आवश्यक थे। कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति को धार देने के बजाय राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने पर अधिक ध्यान दिया और उसमें भी सहयोगी दलों को निमंत्रित नहीं किया।

शीघ्र की जाए नियुक्ति

देर से ही सही, झारखंड के चार विश्वविद्यालयों में कुलपतियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए दोबारा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति के लिए अलग-अलग विज्ञापन जारी कर आवेदन मंगाए जा रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि कुलपतियों की तरह प्रतिकुलपतियों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले शुरू होगी। कुलपतियों की नियुक्ति इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि नियुक्ति नहीं होने से इस पद की जिम्मेदारी या तो प्रमंडलीय आयुक्त या फिर प्रतिकुलपति संभाल रहे हैं। विश्वविद्यालयों में कई अन्य गैर शैक्षणिक पद भी पहले से ही रिक्त हैं। इसका कहीं न कहीं असर शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों पर पड़ता है। कुलपतियों एवं प्रतिकुलपतियों के पद पिछले वर्ष मई से ही रिक्त हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया भी पिछले वर्ष मई-जून में शुरू भी की गई थी। सर्च कमेटी ने बाकायदा तीन-तीन नामों के पैनल की भी अनुशंसा कर दी थी, लेकिन राज्यपाल सह कुलाधिपति द्वारा उसपर स्वीकृति नहीं देकर नए सिरे से आवेदन मंगाने के निर्देश दिए गए। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है कि राज्यपाल योग्य एवं कुशल शिक्षाविदों की नियुक्ति इन पदों पर करना चाहते हों, लेकिन यह भी जरूरी है कि रिक्त पद समय पर भरे जाएं। एक अच्छी बात यह भी है कि राज्य में 16 वर्ष बाद झारखंड पात्रता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। आयोग ने मई या जून में इस परीक्षा के आयोजन की संभावना जताई है। निश्चित रूप से इस परीक्षा के आयोजन से विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति का रास्ता साफ होगा।

विश्वविद्यालयों में पदों के रिक्त रहने का असर शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों पर पड़ता है

राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती

हृदयनारायण दीक्षित

द्रमुक नेता ए. राजा ने जैसे बयान दिए, वैसे शूल की तरह चुभते हैं। उच्चतम न्यायालय को ऐसे बयानों का स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करनी चाहिए

राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती असहनीय अपराध है। यह संविधान का भी उल्लंघन है। यह सब जानते हुए भी द्रमुक सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए. राजा ने राष्ट्रीय संप्रभुता पर हमला किया है। उन्होंने भारत माता के प्रति श्रद्धा को भी चुनौती दी है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम को अपशब्द कहे हैं। भारत के अस्तित्व से इन्कार किया कि भारत राष्ट्र ही नहीं है। यह एक उपमहाद्वीप है। इसके भीतर तमिल और मलयालम जैसे देश हैं। इसके पहले द्रमुक नेता उदयनिधि ने सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया आदि कहा था। राजा के बोल पहली बार नहीं बिगड़े। उदयनिधि वाले विवाद के बीच उन्होंने सनातन धर्म की तुलना एचआइवी और कुष्ठ जैसी बीमारियों से की। उन्होंने तमिलनाडु को अलग देश बनाने के लिए आंदोलन की धमकी दी थी। राष्ट्र और संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाने, श्रीराम और भारत माता को अपमानित करने जैसे कृत्य संविधान का अपमान है। संविधान की मूल प्रति में श्रीराम का चित्र है। श्रीराम के प्रति श्रद्धा काल्पनिक नहीं है। यह सांस्कृतिक है और संवैधानिक भी है। उन्होंने सांसद के रूप में ली गई शपथ का उल्लंघन किया है। राष्ट्र क्षुब्ध है।

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 'डिस्कवरी आफ इंडिया' में 'भारत माता' के संदर्भ में लिखा है-मैं सभाओं में जाता हूं। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। भीड़ 'भारत माता की जय' बोलती है। मैं पूछता हूं, यह 'भारत माता' कौन हैं?' एक व्यक्ति कहता है, 'यह भारत की पवित्र धरती।' मैं कहता हूं, 'आप ठीक सोचते हैं। यही भारत माता हैं, किंतु भारत माता इससे भी ज्यादा हैं। ये पर्वत, नदियां, वन, हम, आप, सब भारत माता हैं।' नेहरू से लेकर नरेन्द्र मोदी तक पूरा देश भारत माता के प्रति श्रद्धालु है। इन्हीं भारत माता की आराधना राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' में की गई है। देश की धरती को माता कहना वैदिक काल से भी पुराना है। वंदे मातरम् स्वाधीनता संग्राम में राष्ट्र जागरण का बीज मंत्र रहा है। ए. राजा की तरह मुस्लिम लीग ने भी भारत माता का विरोध किया। संविधान के मूल कर्तव्यों के अनुसार, 'संविधान और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करें। आगे लिखा है कि, 'राष्ट्रीय संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें।' जबकि यहां संप्रभुता और अखंडता को ही दुत्कारा जा रहा है।

भारत के भीतर कई देश नहीं हैं। भारत अमेरिक जैसा नहीं, जो राज्यों के परस्पर अनुबंध से अस्तित्व में आया था। भारत राज्यों के समझौते का परिणाम भी नहीं है। राज्य भारतीय संविधान का परिणाम हैं। राष्ट्र राज्य राज्यों के आकार में परिवर्तन के लिए अधिकृत है। यहां का संघीय ढांचा अमेरिकी संघीय ढांचे से भिन्न है। राज्यों को देश कहना संविधान का उल्लंघन है, मगर ए. राजा राज्यों को राष्ट्र बता रहे हैं। स्वाधीनता संग्राम और उसके बाद भी कुछ वामपंथी तत्वों ने भारत को राष्ट्र नहीं माना। कुछ ने राष्ट्र बनाने का श्रेय अंग्रेजों को दिया था। गांधी जी ने प्रतिवाद में कहा, 'भारत अंग्रेजी सत्ता के पहले भी राष्ट्र था।' ऋग्वेद में सप्तसिंधु का उल्लेख है। मैकडनल और कीथ ने भी इस भूभाग को देश बताया है। पुसालकर ने भी नदी नामों के आधार पर प्राचीन देश की रूपरेखा बनाई है। उन्होंने अफगानिस्तान, पंजाब, अंशतः सिंध, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश सिंध और कश्मीर एवं सरयू तक का पूर्वी भारत इस देश में शामिल बताया है। भारत एक विशेष संस्कृति के कारण एक राष्ट्र था और है। यह दुनिया का प्राचीनतम राष्ट्र है।

अवधेश राजपूत

भाषा और संस्कृति की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने संतोष बनाम मानव संसाधन मंत्रालय (1994) मामले में स्पष्ट किया कि सामासिक संस्कृति का आधार संस्कृत भाषा और साहित्य है। न्यायालय की टिप्पणी है, 'यद्यपि इस देश के लोगों में अनेक भिन्नताएं हैं। वे गर्व करते हैं कि वे एक सामान्य विरासत के सहभागी हैं। वह विरासत संस्कृत की है।' उल्लेखनीय है कि संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राजभाषा बनाया था। गांधी जी गुजराती और अंग्रेजी के जानकार थे। उन्होंने लिखा है कि, 'मेरी हिंदी कमजोर है, लेकिन मैं हिंदी को राजभाषा बनाने का समर्थक हूं।' तमिल, मलयालम, उड़िया आदि भाषाएं भारत का गौरव हैं। सभी भारतीय भाषाओं में संप्रेषण की शक्ति है। भाषा को लेकर विवाद नहीं होने चाहिए, लेकिन ए. राजा ने सारी हदें तोड़ दी हैं। राजा के बयान के एक दिन पहले ही सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि को अनुचित बयानों के लिए फटकार लगाई थी। इस लिहाज से ए. राजा ने कोर्ट का भी अपमान किया।

सनातन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। सत्य सनातन है। ब्रह्मांड सनातन है। प्राकृतिक नियम सनातन हैं। सनातनता शाश्वत गुण है। जिस तत्व पर समय का प्रभाव पड़ता है वह शाश्वत नहीं है और सनातन भी नहीं। उसमें सुधार की संभावनाएं बनी रहती हैं। सत्य पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। भारतीय समाज के उत्कृष्ट तत्व सनातन निरंतरता से आए हैं, लेकिन रोग पुराना है। तमिलनाडु के रामास्वामी नायकर ने द्रमुक की स्थापना की। रामास्वामी से लोहिया की मुलाकात हुई। लोहिया ने उनसे राष्ट्र विरोधी रुझानों को छोड़ने की बात कही। लोहिया ने कहा, 'वह शूद्रों और गरीबों के हित में आंदोलन के समर्थक हैं, लेकिन वे उत्तर भारत का विरोध, द्रविड़ स्थान की मांग, हिंदी विरोध, गांधी जी की तस्वीर जलाना एवं ब्राह्मणों के प्रति हिंसा का त्याग करें।' भाषा के बारे में लोहिया ने कहा कि मैं उनसे तमिल में बोलूं और वह मुझे हिंदी में जवाब दें। इन सब बातों का कोई लाभ नहीं हुआ।

लोकसभा चुनाव आसन्न हैं। कांग्रेस सहित कई दलों ने आइएनडीआइए नाम का मोर्चा बनाया है। कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह राजा के बयानों के साथ है? क्या वह सनातन के विरुद्ध है? क्या वह राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने वाले राजा के साथ है? इस स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है। वैसे राहुल गांधी ने भी कुछ समय पहले राजा की ही तर्ज पर भारत को देश नहीं, बल्कि 'राज्यों का संघ' बताया था। ऐसे बयान शूल की तरह चुभते हैं। उच्चतम न्यायालय इस मामले का स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करे तो स्वागतयोग्य होगा।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

शिक्षा नीति में है पर्चा लीक का समाधान

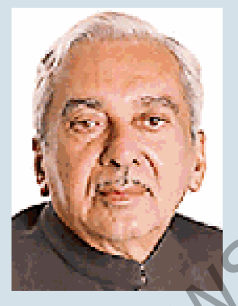

जगमोहन सिंह राजपूत

शिक्षा व्यवस्था में बढ़ रहीं भ्रष्ट प्रवृत्तियां व्यवस्था की साख को दीमक की तरह नष्ट कर रही हैं

https://t.me/NewsPaperPaid

भारत को अपने युवाओं पर गर्व है। सारा विश्व उनकी सृजनात्मकता, बुद्धिमत्ता और प्रतिभा का लोहा मानता है। देश की तकनीकी शिक्षा, प्रबंधन शिक्षा, संचार तकनीकी तथा वैज्ञानिक शोध के संस्थान अनेक देशों के लिए ईर्ष्या के कारण बने हैं। यह सब भारत के भविष्यद्रष्टा नेतृत्व के कारण ही संभव हो सका है। हालांकि कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं, जो देश के लिए अत्यंत चिंताजनक स्थिति निर्मित कर रहे हैं। आज शिक्षा व्यवस्था में असामाजिक तत्व और भ्रष्ट प्रवृत्तियां लगातार बढ़ रही हैं और व्यवस्था की साख को दीमक की तरह नष्ट कर रही हैं। इस पर विमर्श और त्वरित निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक हो गया है। अन्यथा स्थिति हाथ से निकलती जाएगी।

पिछले दिनों हरियाणा के नूंह जिले में परीक्षा में नकल की योजनाबद्ध घटना सामने आई। राजस्थान में भर्ती में पर्चा लीक के एक मामले में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 14 पुलिस कर्मचारियों को मिलाकर 40 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। राजस्थान में 2019 के बाद प्रतिवर्ष तीन पर्चे लीक हुए, जिसमें 40 लाख युवा प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पर्चा लीक के कारण 48 लाख युवाओं का निराश होकर ठगे से रह जाना किसी भी देश के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति ही कही जाएगी। उत्तर प्रदेश की पुलिस नियुक्ति व्यवस्था ने अपनी अक्षमता दिखा दी। इसके बावजूद लाखों युवाओं और परिवारों पर आर्थिक और मानसिक बोझ के लिए जिम्मेदार किसी भी अधिकारी के बर्खास्त होने की खबर न उत्तर प्रदेश से आई, न हरियाणा या राजस्थान से। इस अपराध के लिए कितने लोग जेलों में हैं या उनकी संपत्ति जब्त हुई है? इनमें से अनेक तो लगातार नकल और पर्चा लीक में शामिल बताए जा रहे हैं। 15 राज्यों में पिछले पांच वर्षों के दौरान 1.4 करोड़ युवा पेपर लीक के शिकार हुए हैं। यह चिंताजनक स्थिति है।

परीक्षाओं को कदाचार मुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक माडल अधिनियम बनाया है। राजस्थान सहित कुछ राज्यों ने भी इसके लिए कुछ ऐसा ही रास्ता अपनाया है। समस्या यह है कि किसी को इनके लागू होने के बाद भी स्थिति सुधरने का विश्वास नहीं है। नकल और पर्चा लीक के प्रकरण

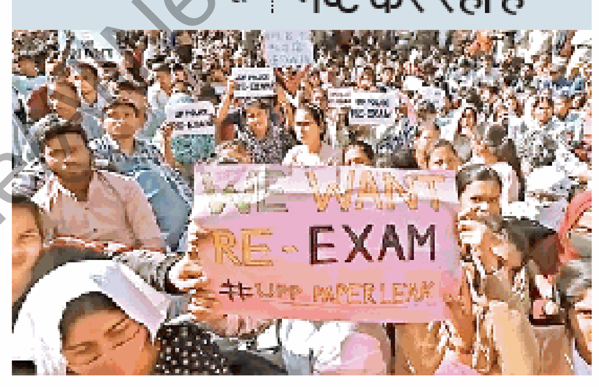

चुनौती बनता प्रश्न पत्रों का लीक होना। फाइल

साल-दर-साल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सवाल है कि आज तक ऐसी किसी व्यवस्था की आवश्यकता क्यों नहीं समझी गई कि नकल और पर्चा लीक में बर्खास्तगी तुरंत होगी। ऐसे हर प्रकरण के लिए सर्वाधिकार संपन्न विशेष न्यायालय की स्थापना की जाएगी और अपराधियों को दंड छह महीने के अंदर दे दिया जाएगा। आज भी पर्चा लीक में संलग्न अपराधी 'अधिकारी' अपनी जगहों पर विद्यमान हैं, जनता के पैसों पर पल रहे हैं। अगर उनके अधिकार हैं तो जिन युवाओं के साथ धोखा हुआ है, उनके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा?

अपराध की गंभीरता को समझना, देश के भविष्य पर उससे घातक परिणामों की चिंता करना सरकार का ही नहीं, समाज का भी उत्तरदायित्व है। परीक्षा में अपनी जगह किसी अन्य को धनराशि देकर बैठाने की तिकड़म लंबे अर्से से चल रही है। विकास, प्रगति या प्रगतिशीलता का यह कैसा उदाहरण है कि मेडिकल की प्रवेश परीक्षा में कोई डाक्टर ही 'साल्वर' बनकर बैठे और किसी को कोई सजा न मिले। दूसरे के लिए परीक्षा में बैठने वाला और उसे बैठाने वाला परिवार समाज के बराबर के अपराधी हैं। ये ऐसी सजा के अधिकारी हैं, जो वह जीवनपर्यंत भोगें। आज तक परीक्षा का पर्चा खरीदने के लिए धन उपलब्ध कराने वाले किसी पालक को शायद ही कभी कोई कठोर दंड मिला हो? इन सभी समस्याओं के संपूर्ण समाधान का रास्ता राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में नजर आता है। इसमें देश के युवाओं के लिए नई आशा का संचार करने की अनेक संभावनाएं निहित हैं। वह देश की शिक्षा व्यवस्था में नैतिकता ला सकती है। सारे सामाजिक परिदृश्य को बदल सकती है। हालांकि इसके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती इसके सफल क्रियान्वयन और अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने की है।

वर्ष 1968 तथा 1986/92 में बनी शिक्षा नीतियों के क्रियान्वयन के अनुभव यह स्पष्ट इंगित करते हैं कि नीति कितनी भी सशक्त क्यों न हो उसकी सफलता उन व्यक्तियों पर निर्भर करती है, जो हर स्तर पर उसके क्रियान्वयन के उत्तरदायित्व निभाते हैं। नई शिक्षा नीति में 2012 में गठित न्यायमूर्ति जेएस वर्मा आयोग के उस निष्कर्ष को दोहराया गया है कि 'देश में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान अध्यापक शिक्षा के प्रति लेशमात्र भी गंभीरता से प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके स्थान पर ऊंचे दामों पर डिग्रियां बेच रहे हैं।' नोबेल पुरस्कार विजेता गुन्नार मिर्डल ने भी अपनी पुस्तक 'एशियन ड्रामा' में लिखा है कि भारत जैसे सभी विकासशील देशों में हर क्षेत्र में गुणवत्ता-वृद्धि का स्रोत एक ही है-उनके अपने शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता।

यदि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में नैतिकता, संस्कृति बोध, कर्तव्यनिष्ठा, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण, सेवा के प्रति सम्मोहन और कार्यसंस्कृति अनुकरणीय होंगे तो देश के स्कूलों के अध्यापक बनने के लिए प्रशिक्षित हो रहे युवा भी इनको ग्रहण और अनुसरण करेंगे। वे बाद में स्कूलों में वैसी ही कार्यसंस्कृति निर्मित करने में सफल होंगे। यहीं से देश को हर कार्यक्षेत्र में वैसे ही लोग मिलेंगे। यह कोई दूर की कौड़ी नहीं है, केवल राष्ट्र द्वारा निर्णय लेने की देरी है। जापान ने अपने पुनर्निर्माण में प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों पर विश्वास कर देश में कार्यनिष्ठा तथा कार्यसंस्कृति के नए आयाम स्थापित कर दिए। भारत भी इसे अपने ढंग से कर सकता है।

(लेखक शिक्षा, सामाजिक सद्भाव और पंथक समरसता के क्षेत्र में कार्यरत हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

प्रतिबोध

आज हर आदमी सुख की खोज में खड़ा है। ऐसे थके-हारे इंसान को प्रतिबोध देते हुए जाने-माने विद्वान खलील जिब्रान लिखते हैं कि 'मैं भी कहता हूं कि जीवन सचमुच! अंधकारमय है, यदि आकांक्षा न हो। सारी आकांक्षाएं अंधी हैं, यदि ज्ञान न हो। सारा ज्ञान व्यर्थ है, यदि कर्म का ज्ञान न हो। जब आप प्रेम से प्रेरित होकर कर्म करते हैं तब स्वयं से बंधते हैं, एक-दूसरे से बंधते हैं, और फिर भगवान से बंधते हैं।' यहां प्रेम का अर्थ संकल्प है। प्रेम में, ज्ञान में और सौंदर्य में कभी अति नहीं होती, जब ये गुण पूर्ण शुद्ध अर्थ में समझे जाएं। तभी हम वह सब कर सकते हैं, जो हम करना चाहते हैं। आप तभी अच्छे बन सकते हैं यदि आपमें आत्मविश्वास है। दृढ़ निश्चय है। निर्णयन क्षमता है। आशावादी दृष्टिकोण है। सकारात्मक सोच और उत्साही मन है। अगर आप दुख में से सुख खोज लेना चाहते हैं तो सचमुच सुख खोज लेंगे। इसके लिए ऐसा सोचते हुए बस आपको संकल्पित होना होगा। यानी आप जिस चीज की इच्छा करेंगे, वह पा लेंगे।

सोचना यह है कि हम गहरे में जमे अपने संस्कारों को कैसे सुधारें? जड़ तक कैसे पहुंचें? बिना जड़ के सिर्फ फूल-पत्तों का क्या मूल्य? पतझड़ में फूल-पत्ते सभी झड़ जाते हैं, मगर वृक्ष कभी इस वियोग पर शोक नहीं करता। उसके पास जड़ की सत्ता सुरक्षित है, जिससे वसंत आने पर पुनः वृक्ष फूल-पत्तों से लहलहा उठता है। अंधेरा तभी तक डरावना है, जब तक हाथ दीये की बाती तक न पहुंचे। अपने आप को अपना भविष्य निर्माता मानिए और फिर कार्य की शुरुआत कर दीजिए। अपने भविष्य की कल्पना कीजिए। सोचिए कि आज से एक वर्ष बाद, दो वर्ष बाद या पांच वर्ष बाद आप कहां पहुंचना चाहते हैं। जहां आपको मनचाही सफलता और जिंदगी हासिल हो। इसीलिए सुकरात का कथन है कि वैसा जीवन जिसमें परीक्षाएं न ली गई हों, जीने योग्य नहीं है।

ललित गर्ग

चुनावों में डीपफेक का खतरा

डा. रमेश ठाकुर

इंटरनेट मीडिया के युग में चुनावों के दौरान भ्रामक खबरों का खतरा काफी बढ़ गया है

डीपफेक की उन्मादी करतूतों ने आगामी लोकसभा चुनाव में व्यापक प्रभाव डालने की आशंकाओं ने चुनाव आयोग को चिंतित किया है। चुनाव के दौरान झूठी सूचनाओं और भ्रामक प्रचार का खतरा बढ़ गया है जिससे निपटना चुनौती है। आम चुनाव एकदम सिर पर हैं। आयोग लोकसभा चुनाव के निष्पक्ष संचालन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआइ का उपयोग करेगा। इसके लिए एक अलग विभाग स्थापित किया है, जो इंटरनेट मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्म पर भ्रामक सूचनाओं को चिह्नित कर उन्हें हटाएगा। कहावत है कि लोहा ही लोहे को काटता है। ठीक उसी तर्ज पर एआइ का उपयोगी वर्जन ही डीपफेक से मुकाबला करेगा। एआइ चुनाव से संबंधित की सामग्रियों की निगरानी करेगी। नकली-बनावटी वीडियो, झूठी खबरें, फेक चेहरों की पहचान करेगी। जल्द नकली सामग्री का मिलान वास्तविक वस्तु से कर लेगी। गलत होने पर उन्हें तुरंत हटा देगी। चुनाव आयोग को अंदेशा है कि प्रधानमंत्री से लेकर प्रमुख मंत्रियों की आवाज चुनाव में गलत इस्तेमाल हो सकती है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव आयोग को बहुत महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त है। इस संस्था के कंधों पर लोकतंत्र की रक्षा की महती जिम्मेदारी है। आज इंटरनेट मीडिया का युग है, जहां बात निकलती है तो दूर तक जा पहुंचती है। पूर्व में संपन्न हुए तमाम चुनावों में अनगिनत ऐसी अप्रिय घटनाएं घटित हुईं, जिसके बाद वोटरों का शक चुनावी प्रक्रियाओं पर भी गहराया? दरअसल इन आरोपों के पीछे डीपफेक की हरकतें ही ज्यादा थीं, जो बाद में पकड़ में आईं? हालांकि ईवीएम का जहां तक सवाल है तो आयोग ने खुद आरोप लगाने वाले दलों को ईवीएम हैक करने की खुली चुनौती कई बार दी, लेकिन तब कोई नहीं पहुंचा। डीपफेक द्वारा फर्जी समाचार एवं गलत सूचनाओं की समस्या से भारत ही पीड़ित नहीं है, यह एक वैश्विक चुनौती बन गई है। डीपफेक की गिरफ्त में नामी हस्तियां ज्यादा फंस रही हैं। बड़े टीवी एंकरों की गलत आवाजें इस वक्त इंटरनेट मीडिया में फैली हुई हैं। निश्चित रूप से समस्या विकराल हो गई है। इसलिए आगामी चुनाव निष्पक्ष हो इसको लेकर चुनाव आयोग बेहद गंभीर है।

चुनावों में डीपफेक के जरिये नेताओं की आवाज निकालकर गलत बातें बुलवाई जाती हैं और उन्हें इंटरनेट मीडिया पर जारी किया जाता है। केंद्र सरकार भी इस बात को मानती है कि गलत सूचनाओं को रोकना बड़ी चुनौती है। खासकर चुनावों के समय डीपफेक के जरिये अराजक तत्व झूठे चुनावी वादे और पार्टी के एजेंडे के विपरीत बातें फैला सकते हैं। इसलिए चुनाव आयोग ने अलग विभाग बनाकर एआइ के माध्यम से ही इनकी कमर तोड़ने का प्लान बनाया है। इस अपराध के लिए सख्त कानून की भी जरूरत है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

विकसित भारत में बाधक वंशवाद

गिरीश्वर मिश्र का 'राजवंश सरीखी राजनीति' विषयक आलेख उन राजनीतिक लोभियों को आईना दिखाता है जिन्होंने राजनीति को धन उगाही का साधन और अपना खानदानी पेशा बना दिया है। भारतीय लोकतंत्र में वंशवादी राजनीति के हस्तक्षेप से इसकी जड़ें कमजोर होंगी। इस संदर्भ में प्राचीन राजशास्त्र के मानक ग्रंथों ने प्रभावी लोकतंत्र के लिए बड़ा आदर्श स्थापित कर रखा है। कौटिल्य के अनुसार राजा का काम स्वार्थ साधना और सत्तासुख भोगना नहीं है। वर्तमान परिदृश्य में राजा का स्थान जनप्रतिनिधियों ने ले लिया है जिन्हें आम जनता शासकीय व्यवस्था चलाने का दायित्व देती है। कौटिल्य की बातें इसलिए उन पर प्रासंगिक मानी जाएंगी, क्योंकि वे जनता के हित साधने के लिए जनप्रतिनिधि बनने की बात करते हैं। दुर्भाग्य से आजकल समाज में उन लक्ष्यों की पूर्ति विरले जनप्रतिनिधि ही करने की सोचते हैं। सम्राट अशोक के शिलालेखों में 'सभी मेरे पुत्र हैं' प्रमुखता से अंकित किया गया है। वैदिक राजतंत्र में राजपद के संदर्भ में 'जानराज्य' और 'स्वाराज्य' जैसे शब्दों का प्रयोग प्रमुखता से मिलता है, जो एक राजा के नेतृत्व में प्रजा की स्वतंत्रता और समग्र जनता की सहभागिता को द्योतित करता है। लेखक का यह मंतव्य कि 'आज के राजनेता जनसेवक होने की जगह खुद अपने लिए जनसेवा कराने लगे हैं', जो चिंता का विषय है। यह भारत के परंपरागत सामाजिक दर्शन के एकदम विपरीत है, जो पद का उपयोग-उपभोग शुचिता से करने को प्रेरित करता है। किसी भी सार्वजनिक पद पर बने रहने के लिए यह आवश्यक है कि पदधारी अपने कार्यों के लिए नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करने के साथ उत्तरदायित्व भी स्वीकार करने के लिए तैयार हो। अपरिपक्व राजनीतिक उत्तरदायित्व का दुष्परिणाम बहुत भयानक हो सकता है, जो राष्ट्रीय हितों को अनदेखा करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित धोखाधड़ी जैसी भयानक समस्याओं का कारण बन सकता है। वर्तमान भारतवर्ष जिस दौर से गुजर रहा है वहां उच्च नैतिक आदर्श युक्त अनुभवी लोग ही पद पर अपेक्षित और उपादेय हैं। यह तभी संभव है जब वंशवाद और खानदानी तौर पर राजवंश सरीखी राजनीति से ऊपर उठकर सामाजिक परिवर्तन के लिए कदम उठाए जाएं। पारिवारिक हितों को सर्वोपरि और राष्ट्रहित को पृथक देखने वालों के हाथ में शासन होने से विकसित भारत का लक्ष्य अप्राप्य हो जाएगा।

डा. धनंजय मणि त्रिपाठी, जामिया-मिलिया-इस्लामिया, नई दिल्ली

मेलबाक्स

कांग्रेस से मोहभंग

पिछले कुछ दिनों या कहें कि कुछ महीनों से कांग्रेस पार्टी में आस्था रखने वाले प्रभावशाली नेताओं के पार्टी छोड़ने के चलन ने जो गति पकड़ी है, वह अब थमने का नाम नहीं ले रही। मध्य प्रदेश, असम, गुजरात, महाराष्ट्र एवं केरल में भी पार्टी से पलायन की बाढ़ कांग्रेस के भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसका कारण कांग्रेस के अंदर ही है, जिस पर पार्टी गंभीर नहीं है। पार्टी के पुराने एजेंडे और समझ से परे बयान भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब भाजपा में आ रहे इन कांग्रेसी नेताओं से सचेत रहने की जरूरत है। पलायन का कारण उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी हो सकती है। भाजपा को बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा। जब कभी पार्टी की स्थिति खराब होगी तो सबसे पहले यही नेता भागेंगे। भाजपा के कार्यकर्ता और उनकी कार्यनिष्ठा को आंच न आए, इसके लिए आने वाले चुनावों में टिकट के बंटवारे में उनकी उपेक्षा न हो इसका विशेष ध्यान भाजपा हाईकमान को रखना होगा। राज्यसभा एवं विधान परिषद के चुनावों में विशेष रूप से। क्योंकि पुराने कार्यकर्ता उपेक्षा से आहत हो सकते हैं। अब भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं की भावना को ठेस न पहुचे और उनका पलायन न हो, इसके लिए विशेष रूप से सावधान रहना होगा। आने वाले दिनों में कांग्रेस में फूट और भी बढ़ सकती है। जिसकी चर्चा जोर पकड़ रही है। वे भी भाजपा में अपनी जगह तलाशने की कोशिश करेंगे। पार्टी की कोशिश करनी चाहिए कि साथ-सुथरी छवि के लोग ही आएं।

कैलाश मेहरा, गुरुग्राम

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • सोमवार • 11 मार्च • 2024
www.rashtriyasahara.com

तेदेपा फिर राजग में

आंध्र प्रदेश में विधानसभा और लोक सभा के चुनाव भाजपा, तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) और जनसेना पार्टी (जेएसपी) मिलकर लड़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लगातार दूसरे दिन बैठक करने के उपरांत तीनों दलों ने संयुक्त बयान जारी करके इस बाबत जानकारी दी। इस प्रकार एनडीए परिवार में दो और दल शामिल हो गए हैं, और तीनों जल्द ही सीट शेयरिंग के तौर-तरीकों को लेकर बातचीत करेंगे। दरअसल, भाजपा दक्षिण भारत में ज्यादा से ज्यादा लोक सभा सीटें जीतने की रणनीति पर गहन मंथन करती रही है। अपनी इसी रणनीति के तहत उसने आंध्र प्रदेश की एक बड़ी पार्टी तेदेपा और बनिस्बत एक छोटे दल को साथ लेकर बढ़ने का फैसला किया है। वैसे, तेदेपा और भाजपा का रिश्ता कोई नया नहीं हैं, दोनों पार्टियों के बीच रिश्ता काफी पुराना है। तेदेपा राजग 1996 में शामिल हुई थी। अटलबिहारी वाजपेयी और नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकारों में सफलतापूर्वक काम कर चुकी है। तेदेपा और भाजपा ने 2014 का लोक सभा और विधानसभा चुनाव साथ लड़ा था जबकि जनसेना पार्टी ने 2014 के आम चुनाव और विधानसभा चुनाव में भाजपा का समर्थन किया था। जेएसपी के अध्यक्ष पवन कल्याण हैं, और इस पार्टी के राज्य के कुछ पॉकेट्स में प्रभाव माना जाता है। तेदेपा का राजग में शामिल होने को लेकर पहले से कोई संशय नहीं था, और माना जा रहा था कि तेदेपा का राजग में शामिल होने की घोषणा कुछ ही दिनों की बात है। आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए उसके लिए जरूरी है कि वह राजग का हिस्सा बने ताकि वाईएसआर का मजबूती से मुकाबला कर सके। पता चला है कि तेदेपा लोक सभा की 17 सीटों और विधानसभा की 145 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा और जेएसपी लोक सभा की 8 सीटों और विधानसभा की 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं। तेदेपा की कोशिश है कि भाजपा खासकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की देशव्यापी लोकप्रियता के सहारे न केवल लोक सभा की अपने हिस्से की सीटें जीत ले, बल्कि विधानसभा में भी अपनी कड़ी प्रतिद्वंद्वी वाईएसआर को शिकस्त देकर राज्य की सत्ता पर काबिज हो जाए। उसे अपनी सरकार के कार्यकाल के प्रदर्शन से कहीं ज्यादा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के करिश्मे और दूरदर्शी व जीवंत नेतृत्व पर विश्वास है, जिसके सहारे वह चुनावी वैतरणी पार हो जाना चाहती है। भाजपा के लिए भी दक्षिण के इस प्रमुख राज्य में उसका साथ माकूल है।

कीमत कटौती से बनेगी बात

महिला दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिलाओं को तोहफा दिया। इसका ऐलान एक्स यानी ट्विटर की पोस्ट के जरिए किया। मोदी ने लिखा-'महिला दिवस के अवसर पर हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में सौ रुपये की छूट का बड़ा फैसला किया है। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। यह कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा।' कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार की कैबिनेट उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर सब्सिडी राहत एक साल के लिए बढ़ा चुकी है। इसके अंतर्गत तीन सौ रुपये प्रति सिलेंडर राहत मिलती है। इसके दायरे में तकरीबन दस लाख लाभार्थी आते हैं जिन्हें साल भर में बारह सिलेंडरों पर सब्सिडी मिलती है। अब इन्हें गैस सिलेंडर 603 रुपये में प्राप्त होगा। इससे सरकार पर बारह हजार करोड़ रुपये का भार आएगा। इस तोहफे के बाद सबको सौ रुपये कम में गैस सिलेंडर मिलना शुरू हो गया। बिना सब्सिडी वाले चौदह किलो के गैस सिलेंडर की कीमत अब तक दिल्ली में 903 रुपये, कोलकाता में 929 रुपये और पटना में 1001 रुपये थी जो अब क्रमशः 803, 829 और 901 रुपये हो गई है। एक मार्च, 2023 को गैस सिलेंडर का दिल्ली में दाम 1103 रुपये था जिसे बाद में दो सौ रुपये सस्ता किया गया था। घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों से मध्यवर्गीय भी परेशान रहता है। खासकर शहरवासियों के लिए गैस पर खाना पकाने की मजबूरी है। अन्य साधन जुटाने में खासी दिक्कत आती है। बढ़ती महंगाई से तंग लोगों के लिए यह तनिक राहत तो हो सकती है मगर घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें बीते दिनों बेतहाशा बढ़ी थीं जिससे उज्ज्वला जैसी योजना का लाभ लेने वालों के लिए भी सब्सिडी के बावजूद सिलेंडर भरवाना मुश्किल हो रहा था। महिलाओं को यह तोहफा देकर प्रधानमंत्री मोदी संदेश दे रहे हैं कि महिलाओं के जिम्मे घरेलू कामकाज खासकर खाना पकाना है जो लैंगिक विभेदकारी सोच है। दरअसल, घरेलू खर्च का बोझ तो सीधा उस पर होता है, जो कमाई करता है। यह किसी हद तक उचित कहा जा सकता है कि गैस पर खाना पकाने से पर्यावरण को फायदा होता है। घर में उठने वाले धुएं से भी पूरा परिवार सुरक्षित रहता है। चुनाव के मद्देनजर ही सही पर आमजन को रत्ती भर मदद होने से राहत तो मिलेगी ही।

परिधि/ राजीव मंडल

उतर गया 'पानी'

देश का सबसे समृद्ध, आधारभूत संरचना से सुसज्जित और विकसित शहर बंगलुरू पानी के संकट से दो-चार है। हालात इस कदर बुरे हैं कि स्कूलों में हफ्ते भर की छुट्टियां घोषित कर दी गई है, पेयजल के गैर जरूरी कार्यों में उपयोग पर रोक लगा दी गई है, वाहनों को धोने, भवन, सड़क निर्माण में पानी का प्रयोग नहीं होगा। अगर कोई नियमों को तोड़ेगा तो उस पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। मतलब यही कि चमक-दमक और अन्य सुविधाओं में बाकी शहरों को मीलों पीछे छोड़ने वाले शहर का 'पानी' उतार पर है।

पानी के स्रोत निःसंदेह सूख चुके हैं, नदी-पोखर, कुएं आदि जल के पारंपरिक स्रोत न जाने कहां गुम हो चुके हैं, मगर सिर्फ यही एक अहम वजह नहीं इन दुश्वारियों की। हमें यह सच्चे मन से मानना होगा कि पानी की बर्बादी हमने कैसे और कितनी नासमझी के साथ की है। आज अगर बंगलुरू शहर की हालत खस्ताहाल है तो देश के बाकी शहरों की स्थिति भी कमोबेश इतनी ही जर्जर है। चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो या चेन्नई या फिर नदियां-पोखर और तालाब से एक वक्त इतराते शहर; सब शहर बे-पानी हो चुके हैं। दरअसल, हमने पानी के समझदारी से इस्तेमाल की न तो कला सीखी न संस्कार। शुरुआत में जब पानी की बहुतायत थी और बड़े-बुजुर्ग पानी के होने की महत्ता को समझते थे, तब तक तो आमजन इस परेशानी से दूर रहे। मगर आज के हालात भयावह हैं। बंगलुरू का वर्तमान परिदृश्य डराता भी है और सचेत भी करता है। शासन को इस मसले पर गंभीरता दिखानी होगी। हां, जनता का दायित्व भी कम नहीं है। पानी की बर्बादी या उसका नासमझी से इस्तेमाल वैसे लोग ही करते हैं, जो अपेक्षाकृत संपन्न हैं। लिहाजा, संपन्नता को पैमाना बनाकर इसकी राशनिंग करने का वक्त आ चुका है। यह सुनने में भले प्रिय लगे कि धरती पर सबसे ज्यादा पानी मौजूद है और पृथ्वी के तीन हिस्से पर पानी मौजूद है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य यही संकेत देने की कोशिश कर रहा है कि अब अगर न चेते तो स्थितियां संभाले नहीं संभलेगी। पानी को लेकर युद्ध होने की भविष्यवाणी सच के करीब दिख रही है। चूंकि अभी गर्मी अपने शबाब पर नहीं है, तब ये हालात हैं तो प्रचंड गर्मी के वक्त दुर्दिन की कल्पना ही की जा सकती है। 500 वर्ष के इतिहास में बंगलुरू ने इतने बुरे दिन नहीं देखे थे। तो क्या यह शहर भी दक्षिण अफ्रीका के केपटाऊन की राह पर है!

कुछ तो है बात

राजनीति

विनीत नारायण

कुछ वर्ष पहले जब मैंने अपने इसी कॉलम में कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए ममता दीदी के सादगी भरे जीवन पर एक लेख लिखा था तो एक खास किस्म की मानसिकता से ग्रस्त लोगों ने मुझे ट्विटर (अब एक्स) पर गरियाने का प्रयास किया। पिछले हफ्ते जब मैं संदेशखालि की घटनाओं के संदर्भ में ममता बनर्जी की कड़ी आलोचना की तो उन लोगों में यह नैतिक साहस नहीं हुआ कि एक्स पर लिखें 'मान गए कि आप निष्पक्ष पत्रकार हैं।'

इसी तरह 2003 में जब मैंने सोनिया गांधी और अटलबिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हुए एक लेख लिखा था जिसमें दोनों के गुण-दोषों का जिक्र था तो कुछ मित्रों ने पूछा, 'तुम किस तरफ हो यह समझ में नहीं आता।' मैंने पलट कर पूछा कि क्या कोई पत्रकार बिना तरफ़दारी के अपनी समझ से सीधा खड़ा नहीं रह सकता? क्या उसका एक तरफ झुकना अनिवार्य है? आज के हालात ऐसे ही हो गए हैं, जिनमें विरला ही होगा जो बिना झुके खड़ा रहे। प्रायः सब अपने-अपने आकाओं के आंचल की छांव में फल-फूल रहे हैं। जनता का दुख-दर्द, लिखे जा रहे तर्कों की प्रामाणिकता, पत्रकारिता में निष्पक्षता, सब गई भाड़ में। अब तो पत्रकारिता का धर्म है कि अपना मुनाफा क्या लिखने या बोलने में है, उसे बिना झिझके ऐलानिया करो।

दरअसल, हर लेख की विषयवस्तु के अनुसार उसके समर्थन में संदर्भ खोजे जाते हैं। किसी एक लेख में हर व्यक्ति की हर बात का इतिहास लिखना मूर्खता है। यह सब भूमिका इसलिए कि आज मैं राजनैतिक लोगों के बिगड़ते बोलों पर चर्चा करूंगा। तो कुछ सिरफिरे कहेंगे कि मैं फलां के भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं लिख रहा। तो क्या ऐसे लोग बता सकते हैं कि आज देश का कौन-सा बड़ा नेता या राजनैतिक दल है, जो आकंठ भ्रष्टाचार में नहीं डूबा है? या देश में कौन-सा नेता है जो अपने दल की आय-व्यय का ब्यौरा देश के सामने खुल कर रखने में हिचकिचाता नहीं है? आज का लेख इन नेताओं और इनके कार्यकर्ताओं की भाषा पर केंद्रित है, जो दिनोंदिन रसातल में जा रही है। अब तो कुछ सांसद संसद के सत्र तक में हर मर्यादा का खुल कर उल्लंघन करने लगे हैं। उनकी भाषा गली-मौहल्ले से भी गई बीती हो गई है। सोचिए, देश के करोड़ों बच्चों, युवाओं और बाकी देशवासियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा होगा? गनीमत है ऐसे कुछ सांसदों के टिकट इस बार कट रहे हैं पर इतना काफी नहीं है। हर दल के नेताओं को इस गिरते स्तर को उठाने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। अपने कार्यकर्ताओं और 'ट्रोल आर्मीज' को राजनैतिक विमर्श में संयत भाषा का प्रयोग करने के कड़े आदेश देने होंगे।

ऐसा नैतिक साहस वही नेता दिखा सकता है, जिसकी खुद की भाषा में संयम हो। इस संदर्भ में मैं अखिलेश यादव के आचरण का उल्लेख करना चाहूंगा। मेरी नजर में अपनी कम आयु के बावजूद जिस तरह का परिपक्व आचरण और विरोधियों के प्रति भी संयत और सम्मानजनक भाषा का प्रयोग अखिलेश यादव करते हैं, ऐसे उदाहरण देश की राजनीति में कम ही मिलेंगे। मेरा अखिलेश यादव से परिचय 2012 में हुआ था जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने। मैं मथुरा के विकास के संदर्भ में उनसे मिलने गया था। ब्रज सजाने के लिए उनका उत्साह और तुरंत सक्रियता ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मथुरा की हमारी सांसद हेमा मालिनी तक अखिलेश यादव के इस व्यवहार की मुरीद हैं। 2012 से आज तक मैंने अखिलेश यादव के मुंह से कभी भी किसी के भी प्रति न तो अपमानजनक भाषा सुनी और न ही उन्हें किसी की निंदा करते हुए सुना है। विरोधियों को भी सम्मान देना और उनके सही कामों को तत्परता से करना अखिलेश यादव की एक ऐसी विशेषता है, जो उनके कद को बहुत बड़ा बना देती है। कई बार कुंठित या चारण किस्म की पत्रकारिता करने वाले टीवी एंकर अखिलेश यादव को उकसाने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो बड़ी शालीनता से उस स्थिति को संभाल लेते हैं। क्या आज हर दल और नेता को इससे कुछ सीखना नहीं चाहिए? सोचिए, अगर ऐसा हो तो उससे देश का राजनैतिक माहौल कितना खुशगवार बन जाएगा। टीवी शो हों या सोशल मीडिया, आज हर जगह गाली-गलौज की भाषा सुन-सुनकर देशवासी पक और थक गए हैं। अखिलेश यादव जैसे सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को जो लोग बात-बात पर 'टोंटी चोर' कहकर अपमानित करते हैं, उन्हें अपने दल के नेताओं के आचरण और कारनामों को भी भूलना नहीं चाहिए। कोई दूध का धुला नहीं है। टोंटी चोर, फेंकू, जुमलेबाज, चारा चोर, पप्पू-ऐसी सब भाषा अब इस चुनाव की राजनीति में बंद होनी चाहिए। इस भाषा से ऐसा बोलने वालों का केवल छिछोरापन ही दिखाई देता है, और देश के सामने मौजूद गंभीर विषयों से ध्यान हट जाता है। कौन-सा नेता या कौन-दल कितने पानी में है, यह जनता सब जानती है। ऐसा नहीं है कि जिन्हें वो वोट देती है, उन्हें वो पाक-साफ मानती है। उन्हें वोट देने के उसके कई दूसरे कारण भी होते हैं।

इसलिए ज्यादा वोट पाकर चुनाव जीतने वालों को अपने महान होने का भ्रम नहीं पालना चाहिए क्योंकि किसी और को पता हो न हो, अपनी असलियत उसे अपने से तो कभी छिपी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सारी सृष्टि प्रकृति के तीन गुणोंः सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से नियंत्रित है जिसका कोई भी अपवाद नहीं है। हां, कौन-सा गुण किसमें अधिक या किस में कम है, यह अंतर जरूर रहता है पर तमोगुण से रहित तो केवल विरक्त संत या भगवान ही हो सकते हैं, हम और आप नहीं। राजनेता तो कभी हो ही नहीं सकते क्योंकि राजनीति तो है ही काजल की कोठरी उसमें से उजला कौन निकल पाया है? इसलिए कहता हूं, 'भाषा सुधारो-देश सुधरेगा।' क्यों ठीक है न?

> अखिलेश यादव जैसे सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को जो लोग बात-बात पर 'टोंटी चोर' कहकर अपमानित करते हैं, उन्हें अपने दल के नेताओं के आचरण और कारनामों को भी भूलना नहीं चाहिए। कोई दूध का धुला नहीं है। टोंटी चोर, फेंकू, जुमलेबाज, चारा चोर, पप्पू-ऐसी सब भाषा अब इस चुनाव की राजनीति में बंद होनी चाहिए। इस भाषा से ऐसा बोलने वालों का केवल छिछोरापन ही दिखाई देता है, और देश के सामने मौजूद गंभीर विषयों से ध्यान हट जाता है

गोल्ड रिफाइनरी लगाने का मौका

- भारत दुनिया में सोने का प्रमुख खरीदार है, और बड़ा खरीदार होने के नाते यहां शोधन (रिफाइनिंग) के बेहतरीन अवसर हैं
- भारत शोधन के लिए करीब 250 टन डोर का आयात करता है। देखना दिलचस्प होगा कि शोधन की अवसंरचात्मक सुविधाएं कितनी और कितना जल्दी विकसित की जा सकती हैं
- इसके लिए कर-नीति या सीमा शुल्क में कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं। मूल्य संवर्धन में आगे बढ़ने की काफी गुंजाइश है

(स्रोत : मीडिया इन्पुट्स)

यूसुफ पठान भी न भारतीय क्रिकेटरों में शामिल हो गए हैं, जो राजनीति में आए। बेशक क्रिकेटर के रूप में उन्होंने कड़े मुकाबलों का सामना किया, लेकिन राजनीति में भी उन्हें एक तगड़े उम्मीदवार (अधीर रंजन चौधरी) का सामना करना होगा।

राजदीप सरदेसाई, पत्रकार
@sardesairajdeep

चिंता की बात | **सुरेश भाई**

मौसम की मार से त्रस्त जनजीवन

इस जनवरी-फरवरी के 45 दिनों में जिस तरह से कंपकंपाती शीत और पहाड़ों पर बर्फ पड़नी चाहिए थी, वह नहीं दिखाई दी। शीतकाल में ही मार्च से शुरू होने वाली गर्मी जैसा महसूस होने लगा था। 14 फरवरी को बसंत पंचमी तक भी पूरी तरह से पतझड़ नहीं हो पाया था क्योंकि उस समय तक शीत लहर के साथ बारिश और बर्फ के अभाव में सूखे पत्ते पूरी तरह से धरती पर नहीं गिर सके और लंबे समय तक पतझड़ वाले पेड़ सूखी पत्तियों को ही ओढ़े रहे क्योंकि नमीयुक्त शीत लहर जब चलती है तो पतझड़ वाले पेड़ों से सूखी पत्तियां झड़कर जमीन पर गिरती हैं। मौसम की इस बेरुखी से चारों तरफ सूखा ही सूखा दिखाई दे रहा है। शीतकाल में हिमालय क्षेत्र में साढ़े 4 हजार से लेकर 10 हजार फीट के बीच में जो बर्फ पड़नी चाहिए थी, वह इस बार गायब रही।

पर्वतीय क्षेत्रों और तराई वाले कृषि क्षेत्र में जहां सरसों के पीले-पीले फूल खेतों में लहलहाते दिखाई देते थे वे भी पहले के जैसे नहीं दिखाई दे रहे। गेहूं और मटर की फसल पानी की कमी के कारण पूरी तरह नहीं उग पाई। ऊंचाई के इलाकों में सेब की फसल भी संकट में पड़ गई है क्योंकि जहां सेब होता है वहां पर शीतकाल में जब बर्फ और बारिश पड़ती है, तभी फसल अच्छी होती है। इस शीतकाल में बारिश की कमी के कारण जंगलों में आग फैलती रही है जो 15 फरवरी के बाद भारी बारिश और बर्फबारी होने पर ही बुझ पाई। बेमौसमी बारिश ने फिर से मौसम परिवर्तन के बड़े संकेत दे दिए हैं क्योंकि इस दौरान मार्च के प्रथम सप्ताह तक बढ़ती ठंड और बारिश के साथ पहाड़ों पर हो रही बर्फवारी के कहर ने जम्मू, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में 12 लोगों की भी जान ले ली है जबकि इस समय किसानों की बोई फसल को तेज बारिश की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां तो इतनी तेज बारिश हुई कि हिमाचल में हिमस्खलन के कारण चिनाब नदी का बहाव रुका रहा। उत्तराखंड में चारधाम की सड़कों पर वारिश और बर्फवारी का दौर जारी है। बरसात के जैसे मौसम में यहां 500 स्थानों पर सड़कें बंद रहीं।

मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी पाकिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से लद्दाख, कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी हुई है। बिहार,

सिक्किम में तूफान के साथ ओलावृष्टि हुई है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में अलग-अलग स्थानों पर बेमौसमी बारिश हुई। भारी बारिश के कारण हिमाचल के किन्नौर और जम्मू कश्मीर के रामबन में 300 से ज्यादा पर्यटक फंसे रहे जबकि ऐसी स्थिति बरसात में देखी जाती थी। बताया जा रहा है कि मार्च में सामान्य से अधिक वर्षा यानी 117 प्रतिशत से अधिक हो सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि इस दौरान दक्षिणी प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है जिसके कारण तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा में लंबी अवधि तक लू चलने का पूर्वानुमान है। यह स्थिति मार्च-मई के बीच में अधिक रह सकती है। यहां पर ग्रीष्मकाल की शुरुआत से ही गर्मी तेजी से बढ़ जाएगी। इसलिए अल नीनो (मध्य प्रशांत महासागर में समुद्री जल के नियमित अंतराल पर गर्म होने की स्थिति) गर्मी के पूरे मौसम में बना रहेगा। इसके बाद भी अच्छी मानसूनी वर्षा के अनुमान हैं। यदि गर्मी और सर्दी की लंबी अवधि चलती रहेगी तो वैज्ञानिकों की वह बात सच हो जाएगी कि 2100 तक पानी ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। शोधकर्ताओं ने कहा है कि तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा तो हिमालय का 90 फीसद क्षेत्र साल भर में सुखे रहेंगे। मौसम में तेज गति के बदलाव के कारण 'परागण' प्रक्रिया पर भी असर पड़ेगा। तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने से भी भारत में खेती की जमीन पर सूखे का खतरा 31 फीसद के बीच घट सकता है और 50 फीसद जैव विविधता के लिए आश्रय के रूप कार्य करने में मदद मिल सकती है। इसके बावजूद सूखा, बाढ़, फसल की पैदावार में गिरावट के साथ प्राकृतिक आपदाओं के खतरे बढ़ सकते हैं। हमारी हर विकास योजना में मौसम की मार का सामना करने के लिए पूरी तैयारी होनी चाहिए।

जलवायु अनुकूल प्लान गांव से लेकर शहर तक बनाना होगा। विकास कार्यों में इस बात का ध्यान रखा जाए कि हर तरह की गतिविधि चलाते समय पानी को अधिक से अधिक संरक्षित करके संतुलित उपयोग के तरीकों का पालन किया जाए। प्राकृतिक संसाधनों से चलने वाली आजीविका को नष्ट होने से बचाया जाए। छोटे और सीमांत किसानों के लिए भूमि वितरण की व्यवस्था हो ताकि खेती का दायरा बढ़ाया जा सके। समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में बदलते मौसम और जलवायु के संकट से बचना मुश्किल होगा।

क्रोध | **श्रीराम शर्मा आचार्य**

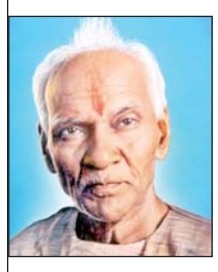

एक युवक ने विवाह के बाद दो साल बाद परदेस जाकर व्यापार की इच्छा पिता से कही। पिता ने स्वीकृति दी तो वह अपनी गर्भवती को मां-बाप के जिम्मे छोड़कर व्यापार को चला गया परदेश में मेहनत से बहुत धन कमाया। 17 वर्ष धन कमाने में बीते गए तो संतुष्टि हुई और वापस घर लौटने की इच्छा हुई। जहाज में बैठ गया। जहाज में एक व्यक्ति मिला जो दुखी मन से बैठा था। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कद्र नहीं है। सेठ ने सोचा इस देश में मैंने तो बहुत धन कमाया। इसका मान रखना चाहिए। उसने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। उस व्यक्ति ने कहा-मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ ने 500 मुद्राएं दे दीं। व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र दिया-कोई भी कार्य करने से पहले दो मिनट रुक कर सोच लेना। कई दिनों की यात्रा के बाद रात्रि के समय अपने घर पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसके पांवों के नीचे की जमीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी के पास एक युवक सोया हुआ था। अत्यंत क्रोध में सोचने लगा कि मैं दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तलवार से वार करने ही जा रहा था कि उतने में ही उसे 500 अशर्फियों से प्राप्त ज्ञान सूत्र याद आया। तलवार पीछे खींची तो एक बर्तन से टकरा गई। बर्तन गिरा तो पत्नी की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नजर अपने पति पर पड़ी वह खुश हो गई और बोली-आपके बिना जीवन सूना सूना था। सेठ तो पलंग पर सोए पुरुष को देखकर कुपित था। पत्नी ने युवक को उठाने के लिए कहा-बेटा जाग। तेरे पिता आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका माथे की पगड़ी गिर गई। उसके लम्बे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा-स्वामी ये आपकी बेटी है। पिता के बिना इसकी मान को कोई आंच न आए इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान ही पालन-पोषण और संस्कार दिए हैं। यह सुनकर सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। पत्नी और बेटी को गले लगाकर सोचने लगा कि यदि आज मैंने उस ज्ञानसूत्र को नहीं अपनाया होता तो जल्दबाजी में कितना अनर्थ हो जाता। मेरे ही हाथों मेरा निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। ज्ञान का यह सूत्र उस दिन तो मुझे महंगा लग रहा था लेकिन ऐसे सूत्र के लिए तो 500 अशर्फियां बहुत कम हैं। ज्ञान अनमोल है।

रीडर्स मेल

खत्म हो राजनीति में अपराधीकरण

बंगाल के संदेशखालि के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को बंगाल सरकार द्वारा बचाने की कोशिश करना राजनीति के अपराधीकरण की पराकाष्ठा है। उच्च न्यायालय की कड़ी टिप्पणी के बाद ही बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले किया। राशन घोटाला, जमीन कब्जाने एवं महिला उत्पीड़न के कई संगीन आरोप शाहजहां के ऊपर लगाए गए हैं। बंगाल में हिंसा की राजनीति के कई दशकों से कायम है। दुर्भाग्यवश बंगाल पुलिस राज्य सरकार के हाथों कठपुतली बन चुकी है। हालांकि राजनीति के अपराधीकरण को बढ़ाने में सभी दलों का योगदान है। पूर्व में जन आंदोलन के द्वारा नेता पैदा होते थे, लेकिन आज परिवारवाद, धनबल और बाहुबल के सहारे लोग राजनीति में आ रहे हैं। सभी दलों को सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार की जरूरत होती है। उम्मीदवारों के आपराधिक पृष्ठभूमि को राजनीतिक दल नजरअंदाज कर देते हैं। राजनीति का बढ़ता अपराधीकरण लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है।

हिमांशु शेखर, गया

घोषणा पत्र के मायने

भारत में चुनावी वर्ष नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आने के लिए लोक-लुभावनी घोषणाएं करने लगती हैं, जैसे मुफ्त में बिजली-पानी, लैपटॉप, साइकिल आदि देने के वायदे करना आदि। यह प्रचलन लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के लिए सभी को समान अवसर मिलने के मूल्य के उल्लंघन को तो दर्शाता ही है, साथ ही सत्ता में आने पर जब सरकार नागरिकों के कर से निर्मित 'लोकनिधि' से ही अपने वायदे पूरे करती है, तो निधि के इस दुरुपयोग से विकास की गति भी धीमी पड़ती है। अरे! तुम क्या जानो/तुम्हारी जान और इज्जत/बदन की खाल, मुफ्त में खिंचवाते हैं/शोर न उठे तुम्हारे संहारो का/दूसरा मुद्दा ले आते हैं/आरक्षण और संविधान को भी/मन भर गरियाते हैं/ समय समय पर/जोर-जोर लतियाते हैं/और तो और! समाज का दुश्मन/तुमको ही बतलाते हैं/इसीलिए तो चुनावी घोषणा पत्र लाते हैं/कागज के लुभावने वायदों/दारू साड़ी में बिक जाते हो/इसीलिए तो/चुनावी घोषणा पत्र लाते हैं।

प्रियंका सौरभ, हिसार, हरियाणा

गाजा पट्टी की मुश्किलें

इस बार गाजापट्टी के लोगों के लिए, रमजान का पावन महीना, भुखमरी, बमबारी, दहशत, बीमारी,पीड़ा और जख्म लेकर आया है। 20 लाख से अधिक लोग, इधर-उधर भटकने को मजबूर हो गए हैं। वो लोग जहां-जहां जाते हैं, वहां-वहां इस्राइली सैनिक गोला-बारूद दागते हैं। इधर रमज़ान कोई मद्देनज़र 6 सप्ताह का युद्ध विराम भी इसराइल के जिद्द के कारण, अमल में नही आ सका। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को अपने स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में कहा कि वह अमेरिकी सेना को भोजन, पानी, दवा और अस्थायी आश्रय ले जाने वाले जहाजों को प्राप्त करने के लिए गाजा के भूमध्यसागरीय तट पर एक घाट स्थापित करने के लिए एक आपातकालीन मिशन का नेतृत्व करने का निर्देश दे चुके हैं। क्या इस मिशन से क्षेत्र का खूनखराबा रुक जाएगा? क्या वहां अकाल और भुखमरी की स्थति बनी हुई है उसे दूर किया जा सकेगा? अगला कुछ ही दिनों के अंदर हमें यह सुनने को मिलेगा की क्षेत्र में लाहों लोग भूख और बदइंतजामी के कारण मर गए। यह आधुनिक विश्व का सबसे बड़ा, मानव निर्मित अकाल और त्रासदी होगा।

जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर, झारखंड

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **जिया कादरी** द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। **समूह संपादक - डॉ. विजय राय।** **स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र*** ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, **फैक्स** - 23352370, **दूरभाष - नोएडा प्रेस** 0120-2444755, 2444756 **फैक्स** - 2550750

वर्ष-33, अंक 209 — आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026 — *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

https://t.me/AllNewsPaperPaid